Machine Translated by Google

त्रिस्तरीय दौड़

बीआरएस के फिसलने से तेलंगाना में कांग्रेस आगे बनी हुई है

एक ओर ट्रा समिति (बीआरएस) गिरावट पर है और दूसरी ओर भरत राश जैसे राक्षस के साथ सत्ता में हैंओवर

दूसरी ओर, पार्टी लाइनों के विपरीत, तेलंगाना आम चुनाव में दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा वाले राज्यों में से एक हो सकता है। जबकि नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रभावशाली 39% वोट जीते, पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बीआरएस, जो अब एक दशक तक सत्ता में रहने के बाद प्रमुख विपक्षी दल है, केवल दो प्रतिशत अंक कम थी। वोट शेयर की शर्तें. कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनावों से अपने वोट शेयर में 14 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी की, जबकि बीआरएस अपने प्रमुख 47% से समान अंतर से कम हो गई।

लेकिन जैसा कि द हिंदू ने तब रिपोर्ट किया था, ऐसा प्रतीत होता है कि बीआरएस के खिलाफ झुकाव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस दोनों के पक्ष में है: आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भाजपा के लिए और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस के लिए।

इसके अलावा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के लगभग चार महीनों के शासन में, सरकार और शासन के बारे में जनता की धारणा में उल्लेखनीय बदलाव आया है।

एक के लिए, मल्लू भट्टी विक्रमार्क, उप मुख्यमंत्री और एक दलित, अब के द्वारा निर्मित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर रहते हैं।

2016 में चन्द्रशेखर राव। दुर्गमता और सामाजिक बहिष्कार की धारणा का मुकाबला करने के लिए इमारत का नाम बदलकर ज्योतिराव फुले प्रजा भवन कर दिया गया है। निश्चित रूप से, केसीआर के पहले उप एवं स्वास्थ्य मंत्री टी. राजैया, जिन्हें शपथ लेने के एक साल के भीतर ही बर्खास्त कर दिया गया था, भी दलित थे। लेकिन उनके स्थान पर पूर्व शिक्षा मंत्री कादियाम श्रीहरि भी थे। जबकि कांग्रेस द्वारा वादा किए गए अधिकांश कल्याणकारी उपाय, जैसे कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली, सात चरण के लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता के कारण अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किए गए हैं, जनता को कोई संदेह नहीं है। अभी कांग्रेस के बारे में लिखने की जल्दी है। और हाल ही में श्री श्रीहरि और राज्यसभा सदस्य के. केशव राव, जिन्हें व्यापक रूप से केसीआर का भरोसेमंद लेफ्टिनेंट माना जाता है, जैसे बीआरएस से कांग्रेस में जाने की उच्च संभावना के साथ, बीआरएस के 2019 में अपने प्रदर्शन से मेल खाने की संभावना है। आम चुनाव - नौ सीटें और 42% वोट शेयर - धूमिल प्रतीत होता है। एक महत्वपूर्ण संकेतक जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए वह है 2018 और 2023 के विधानसभा चुनावों के बीच भाजपा के वोट शेयर का 7% से दोगुना होकर 14% हो जाना। यह तेलान-गाना में उभरती तीन-आयामी दौड़ की ओर इशारा करता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अभी भी एक प्रमुख खिलाड़ी है, हालांकि बिना किसी औपचारिक गठबंधन के। यह देखना बाकी है कि जिन सीटों पर वह चुनाव नहीं लड़ रही है वहां उसके समर्थक कैसे वोट करते हैं।

चुनावी मौसम में द्विपक्षीय संबंधों में खटास का ख़तरा

सुहासिनी हैदर

21वीं सदी के लोकलुभावन युग में नीति निर्माण का "सभी भू-राजनीति स्थानीय है" यह अलिखित है नियम। परिणामस्वरूप, दुनिया भर में अधिकांश नेता ऐसी विदेश नीतियां बनाते हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि घरेलू राजनीति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और यदि संभव हो तो उन्हें कुछ वोट भी मिलें। हालाँकि, शायद ही कभी आम चुनाव विदेश नीति के मुद्दों से जुड़े होते हैं जैसा कि भारत में आगामी चुनाव बन गए हैं।

उदाहरण के लिए, के हालिया बयानों को लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर 1974 के भारत-श्रीलंका समझौते पर सवाल उठा रहे हैं। दोनों ने न केवल कच्चातिवू द्वीप को श्रीलंकाई क्षेत्र के हिस्से के रूप में मान्यता देने के फैसले के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनकी पार्टी की आलोचना की, बल्कि विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा "स्थिति" के लिए एक "समाधान" खोजा जाना चाहिए। समझौते के परिणामस्वरूप तमिलनाडु शेरमेन ने खुद को शामिल कर लिया।

1974 के समझौते और 1976 के पत्रों के आदान-प्रदान के गुण और दोष, कच्चातिवू के "नुकसान" और तेल समृद्ध वाडगे बैंक के "लाभ" से भरे हुए हैं, तब से राजनीतिक स्पेक्ट्रम के दोनों पक्षों द्वारा खारिज कर दिया गया है।

टिप्पणीकारों ने तब से सरकारी बयानों, संसद और सूचना के अधिकार (आरटीआई) के जवाबों और अदालत में बयानों (कच्चतीवू मुद्दे और शेरमेन के अधिकारों पर) की ओर इशारा किया है जो श्री जयशंकर की 1974 के समझौते की आलोचना से भिन्न हैं।

हालांकि बयानों का उद्देश्य भारत के आम चुनाव के पहले चरण के दौरान प्रभाव डालना है, जहां तमिलनाडु में अगले सप्ताह मतदान होगा, इन बयानों का श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा, जो दोनों राष्ट्रपति चुनावों की ओर अग्रसर है। और बाद में संसदीय चुनावों को नज़रअंदाज़ किया गया लगता है। मोदी सरकार द्वारा कोलंबो को देश में आर्थिक संकट से निपटने में मदद करने के लिए अनुमानित 4 बिलियन डॉलर की महत्वपूर्ण सहायता देने के बाद पिछले कुछ वर्षों में श्रीलंका के साथ संबंधों में नई मजबूती देखी जा रही है। किसी अभियान के मुद्दे पर तनाव होने से विक्रमसिंघे सरकार की साख में कुछ कमी आएगी।

विश्वसनीयता को लग सकता है झटका द्विपक्षीय तनाव के अलावा, 50 साल पुराने समझौते को फिर से खोलने के बारे में सरकार के संकेत अन्य अंतरराष्ट्रीय सवाल खड़े करते हैं। क्या 1974 के समझौते के आधार पर हस्ताक्षरित अन्य समझौतों को भी संशोधित किया जा सकता है? क्या ऐसी बातचीत हो सकती है जो भारत अभी कर रहा है, या पहले ही सहमत हो चुका है, जैसे कि बांग्लादेश के साथ समुद्री सीमा समझौता, जिसे 2014 में संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण के फैसले के बाद नई दिल्ली ने स्वीकार कर लिया था, या जैसा कि एक भारतीय विपक्षी नेता ने पूछा था, भूमि सीमा समझौता (भारत-बांग्लादेश) परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान करने के लिए, भविष्य में किसी अन्य सरकार द्वारा संशोधित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा समुद्री समझौतों की मान्यता

चुनाव प्रचार रैलियाँ और मीडिया सम्मेलन शोर मचाने की जगह नहीं हैं

पर बयान संवेदनशील विदेश नीति मुद्दे

जैसे कि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएलओएस) किसी भी संशोधन को कठिन बना देता है। यदि नई दिल्ली आम चुनाव के बाद इस लाइन को आगे बढ़ाने का विकल्प चुनती है तो इससे वार्ताकार के रूप में भारत की विश्वसनीयता भी संदेह में आ जाएगी। नई दिल्ली ने विश्व बैंक द्वारा गारंटीकृत 1960 सिंधु जल संधि के साथ ऐसा करने की चुनौतियों को पहले ही देख लिया है। पांच साल हो गए हैं जब मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ संधि रद्द करने की धमकी दी थी, और नई दिल्ली द्वारा इस्लामाबाद को दोबारा बातचीत के लिए पत्र लिखने के एक साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन मामला अभी तक आगे नहीं बढ़ा है।

सीएए पर, अंतरराष्ट्रीय भागीदारी आम चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, या सीएए के लिए नियमों को अधिसूचित करने का सरकार का निर्णय, जिसे उसने 2019 में कानून पारित होने के बाद से करने से परहेज किया था, इसका एक और उदाहरण है घरेलू कदम जो किसी पड़ोसी के साथ मजबूत संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। हालाँकि सरकार ने लगातार यह माना है कि सीएए पूरी तरह से एक घरेलू कानून है, लेकिन इसके विदेश नीति निहितार्थ अपरिहार्य हैं। इसमें भारत के पड़ोसियों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया गया है। सीएए की बहिष्करणीय प्रकृति, जिसमें तीन देशों के मुसलमानों के अलावा केवल छह धर्मों के लोगों को स्वीकार किया गया है, को पड़ोस के देशों द्वारा भेदभावपूर्ण के रूप में देखा गया है। जबकि तालिबान के तहत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ संबंधों का आज नई दिल्ली के लिए बहुत कम प्रभाव पड़ता दिख रहा है, बांग्लादेश में एक मित्रवत सरकार के खिलाफ आरोप महत्वपूर्ण है।

लंबे समय तक यह डर, कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के बाद के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, बांग्लादेश से आए हजारों लोगों को राज्यविहीन नागरिक माना जा सकता है, ढाका के साथ संबंधों में तनाव पैदा करने की भी संभावना है। . सीएए के खिलाफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध बांग्लादेश में हुआ - 2021 में श्री मोदी की ढाका यात्रा के दौरान, प्रदर्शनकारी भीड़ के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में 12 लोग मारे गए। हालांकि नई दिल्ली द्वारा सीएए पर हालिया फैसले पर बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन जब नीतियां पूरी तरह से लागू हो जाएंगी तो ढाका में भारत के राजनयिकों के लिए उनके काम में कटौती कर दी जाएगी।

उन इलाकों के अलावा जहां सरकार खुद आम चुनाव के समय विदेश नीति को विवाद में ला दिया है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें राजनीतिक क्षेत्र में अन्य लोग उठा रहे हैं। हाल के सप्ताहों में, विपक्ष नियमित अंतराल पर बयान जारी कर मोदी सरकार से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ भारत के गतिरोध और इस तथ्य पर सवाल उठा रहा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अभी तक वह जमीन खाली नहीं की है जिसे उसने अप्रैल में अपने नियंत्रण में ले लिया था। 2020.

द्वारा कथित अंतरराष्ट्रीय हत्याओं का मुद्दा भारतीय एजेंसियां सरकार के लिए एक और कांटा हैं और आम चुनाव शुरू होने के साथ ही इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा रहा है। एक सिख राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की कथित साजिश के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक भारतीय नागरिक पर मुकदमा इस गर्मी में शुरू होने की उम्मीद है। कनाडा में ट्रूडो सरकार से भी कुछ ऐसा ही करने की उम्मीद है क्योंकि कनाडा का आरोप है कि 'भारत के एजेंटों ने ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिख समुदाय के नेता की हत्या कर दी।'

इस बीच, पाकिस्तान ने भी अपने को संरेखित करने की मांग की है दावा है कि भारतीय एजेंटों ने दो पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या कर दी, जिसके मामले अमेरिका और कनाडा में हैं, और एक ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट का समर्थन किया है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में 20 अन्य सिख और इस्लामी अलगाववादी कार्यकर्ताओं की हत्या के पीछे संभवतः भारतीय खुफिया एजेंसी का हाथ है। हालाँकि पाकिस्तान को अपनी धरती पर उन लोगों की मौजूदगी के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए बैकफुट पर रहना चाहिए, लेकिन नई दिल्ली की बेचैनी कनाडा, पाकिस्तान और अमेरिका को दी गई तीन अलग-अलग प्रतिक्रियाओं से उजागर होती है।

रक्षा मंत्री राजनाथ का बयान सिंह का यह कहना कि "पाकिस्तान में जाने वाले आतंकवादियों को मारना" सरकार की नीति है, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के कनाडाई प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को भारत द्वारा खारिज करना, भारत में कनाडाई राजनयिकों के खिलाफ भारत के मजबूत जवाबी कदम, और गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या के असफल प्रयास में भारतीय संलिप्तता के अमेरिकी सरकार के दावों की वैधता को नई दिल्ली की मौन स्वीकृति। कनाडा और पाकिस्तान के साथ अपने रुख के विपरीत, नई दिल्ली पन्नून मामले में अमेरिकी सबूतों की जांच करने और श्रीमान के लिए एक "उच्च-स्तरीय" जांच पैनल गठित करने पर भी सहमत हुई।

जयशंकर ने एक जांच को "भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों" के अनुरूप बताया।

विवेक ही कुंजी इन सभी मुद्दों को केवल विवेकपूर्ण तरीके से, बंद द्विपक्षीय वार्ता में ही हल किया जा सकता है, न कि चुनाव अभियान रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी चकाचौंध में। सरकार को यह समझना चाहिए कि उसके सभी बयान तत्काल पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित करते हैं, खासकर जब क्षेत्रीय और संप्रभुता के मुद्दों की बात आती है।

नई दिल्ली के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि नेपाल सरकार 2019 में प्रकाशित पुनर्गठित जम्मू-कश्मीर के भारतीय राजपत्र मानचित्र या भारत के नए संसद भवन में "अखंड भारत" को दर्शाने वाले भित्तिचित्र पर नाराजगी जताएगी - जैसा कि नहीं इसमें संदेह है कि क्या अभियान सत्र के दौरान उठाए गए कार्टोग्राफिक विवादों पर कोलंबो, ढाका या काठमांडू की ओर से कोई प्रतिक्रिया होगी। हालांकि चुनाव का मौसम अपेक्षाकृत छोटा है, घरेलू राजनीति की वेदी पर द्विपक्षीय संबंधों की बलि चढ़ाने के परिणाम लंबे समय तक बने रह सकते हैं।

suhasini.h@thehindu.co.in

अंतिमता और न्याय

डीएमआरसी विवाद के लिए मध्यस्थों को तथ्य और कानून के प्रति अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है

टी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 के अपने फैसले को रद्द करने और पूर्व रियायतकर्ता के साथ विवाद में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को ₹7,687 करोड़ के अत्यधिक बोझ से राहत देने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग किया है। यह फैसला एक ओर न्यायालय के उपचारात्मक क्षेत्राधिकार के अस्तित्व की पुष्टि करता है, और दूसरी ओर, मुकदमेबाजी में वास्तविकता और वास्तविक न्याय की आवश्यकता के बीच संभावित संघर्ष को बढ़ावा देता है। इस मामले में, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 2017 में दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली हवाई अड्डे तक लाइन के निर्माण, रखरखाव और संचालन का ठेका मिला था। डीएएमईपीएल ने कुछ दोषों को ठीक करने में डीएमआरसी की कथित विफलता का हवाला देते हुए अक्टूबर 2012 में अपने समझौते में समाप्ति खंड को लागू किया था।

जबकि DMRC ने मध्यस्थता खंड लागू किया, DAMEPL ने जून 2013 में परिचालन रोक दिया और लाइन DMRC को सौंप दी। इस बीच, एक संयुक्त आवेदन के आधार पर, मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) ने सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी किया, जिससे मेट्रो के परिचालन को पुनर्जीवित करने में मदद मिली।

अपील पर, दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने डीएमआरसी के खिलाफ मध्यस्थता पुरस्कार को बरकरार रखा, लेकिन एक डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए इसे रद्द कर दिया कि यह पुरस्कार विकृति और पेटेंट अवैधता से प्रेरित है। 2021 में, सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों वाली बेंच ने डीएमआरसी के पक्ष में हाई कोर्ट बेंच के फैसले को पलटते हुए पुरस्कार को बहाल कर दिया। एक समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई.

सुधारात्मक याचिका एक असाधारण उपाय है, क्योंकि यह शीर्ष अदालत द्वारा अपने फैसले की समीक्षा करने से इनकार करने के बाद दायर की जाती है। ऐसी याचिका पर विचार करने के लिए केवल दो मुख्य आधार हैं: प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना और न्याय के घोर गर्भपात को रोकना, हालाँकि उन सभी परिस्थितियों की गणना करना संभव नहीं है जो इसकी गारंटी देती हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि न्याय के प्रति न्यायालय की चिंता नैलिटी के सिद्धांत से कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत के मध्यस्थता कानून के तहत, किसी पुरस्कार को केवल सीमित आधार पर ही रद्द किया जा सकता है। मध्यस्थता के मुद्दों के लिए मुकदमेबाजी के कई स्तर होना सामान्य रूप से अनुचित है - इस मामले में उच्च न्यायालय में एक वैधानिक अपील थी, और एक बेंच, शीर्ष न्यायालय, एक समीक्षा याचिका और एक उपचारात्मक याचिका में अपील की गई थी। अंतिम विश्लेषण में, ऐसा प्रतीत होता है कि डीएमआरसी मामले का फैसला सही हुआ है क्योंकि पहले की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ के इस दृष्टिकोण को खारिज करने में गलती की थी कि सीएमआरएस प्रमाणपत्र साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा था। नतीजा केवल मध्यस्थों और न्यायाधीशों के तथ्य और कानून दोनों को सही करने वाले पुरस्कारों पर अपील पर बैठने के महत्व को कम करता है, ऐसा न हो कि वाणिज्यिक वादियों को न्याय के विचार के निरंतर विस्तार के कारण मध्यस्थता से हतोत्साहित किया जाए। सभी विवादकर्ता सुधारात्मक याचिका के स्तर तक नहीं जा सकते।

लद्दाख और पूरी मानवता को बचाने की लड़ाई

जानकी मुरली

एक पत्रकार और लेखक हैं

जब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता (2018) और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपने 21 दिवसीय जलवायु उपवास की घोषणा करने के लिए 6 मार्च, 2024 को लेह, लद्दाख में 30,000 लोगों की भीड़ को संबोधित किया, वह सिर्फ लद्दाख के लोगों से बात नहीं कर रहे थे बल्कि दुनिया से अपील भी कर रहे थे। .

भारत के पड़ोसियों, पाकिस्तान और चीन के बीच 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित, लद्दाख में 97% स्वदेशी जनजातियाँ हैं, जिनमें से कई साधारण देहाती जीवन जीते हैं और आजीविका के लिए खेती और पशु पालन पर निर्भर हैं।

सीमा विवादों के अलावा, हिमालय क्षेत्र को बाढ़, सूखा, भूस्खलन, ग्रीनहाउस गैसों और अन्य प्रदूषकों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों का भी सामना करना पड़ता है।

हिमालय क्षेत्र में लगभग 15,000 ग्लेशियर हैं, जिन्हें अक्सर तीसरा ध्रुव कहा जाता है। वसंत और गर्मियों में, ये ग्लेशियर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में पिघला हुआ पानी छोड़ कर जल विज्ञान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह हिमालय के ग्लेशियरों के भी पिघलने का खतरा है। इसका असर पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों और निचली धारा में रहने वाले लोगों दोनों पर पड़ेगा।

बुनियादी ढांचे में उछाल 2008 में, केंद्र ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत आठ मिशन शुरू किए। इनमें से एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम (एनएमएसएचई) के अधीन था। जैसा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की वेबसाइट बताती है, "एनएमएसएचई का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता का वैज्ञानिक रूप से आकलन करने और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की स्वास्थ्य स्थिति का लगातार आकलन करने की क्षमता विकसित करना है"।

तो, एनएमएसएचई हिमालय क्षेत्र की रक्षा करने की अपनी भूमिका क्यों भूल गया है?

लगभग जैसे ही लद्दाख संघ बना

सोनम वांगचुक के जलवायु परिवर्तन ने हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की नाजुकता के बड़े मुद्दे को उजागर किया है

क्षेत्र में कई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं तेजी से शुरू की गईं। इनमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुलों का निर्माण, सड़कों, सुरंगों, रेलवे लाइनों का चौड़ीकरण, मेगा सौर परियोजनाएं, एक अत्याधुनिक हवाई अड्डा टर्मिनल और सड़क के किनारे सुविधाएं शामिल हैं। इनमें 14.15 किलोमीटर लंबी ज़ोजिला सुरंग, 230 किलोमीटर लंबी कारगिल-ज़ंस्कर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और चांगथांग क्षेत्र में 20,000 एकड़ को कवर करने वाली 10 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजना शामिल थी। लद्दाख (यूटी)

2023 की औद्योगिक भूमि आवंटन नीति का लक्ष्य "यूटी लद्दाख को निवेश के लिए पसंदीदा स्थलों में से एक बनाना" है।

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के साथ इनमें से कई परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। 2021-22 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, एनएचआईडीसीएल ने अपने दृष्टिकोण के रूप में निम्नलिखित कहा है: “जम्मू और कश्मीर, लद्दाख जैसे सीमा और रणनीतिक क्षेत्रों के पास, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाने के लिए” उत्तराखंड राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में”। संयोग से, ये सभी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं।

एक ऐसा क्षेत्र जिसने आपदाएं देखी हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि परियोजनाओं को मंजूरी देने और उन्हें इतनी तेज गति से क्रियान्वित करने वाली विभिन्न सरकारी संस्थाएं पहाड़ों में पिछली आपदाओं की चेतावनियों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं और उनसे सीख क्यों नहीं ले रही हैं।

2010 के बाद से यहां कई आपदाएं आई हैं हिमालय क्षेत्र में जीवन और आजीविका की हानि हुई। 2013 में, हिमालय के ऊपरी इलाकों में बादल फटने से केदारनाथ में राख फैल गई, जिसमें 6,000 लोगों की जान चली गई और कई बस्तियां बह गईं। जनवरी 2023 में, जोशीमठ में आपदा आई, जब पानी पहाड़ की निचली ढलान से नीचे की ओर बह गया, जिससे शहर के कुछ हिस्से जलमग्न हो गए। नवंबर 2023 में ढहे सिल्क्यारा में फंसे 41 श्रमिकों को बचाया गया हिमालय में सुरंग परियोजना ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया।

उत्तराखंड, जहां ये सभी त्रासदियां हुईं, ने भी 2000 में अपने गठन के बाद से कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं देखी हैं। भूवैज्ञानिकों और पारिस्थितिकीविदों की गंभीर चेतावनियों के बावजूद यह जारी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने यहां तक सुझाव दिया कि अधिकारियों को चार बांध हिमालयी मंदिरों, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या को वहन क्षमता तक सीमित करना चाहिए। वहन क्षमता लोगों की वह अधिकतम संख्या है जिसे एक पारिस्थितिकी तंत्र बिना किसी क्षति के समर्थन कर सकता है। लेकिन, इसके बजाय, हर साल तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि ही हुई है। कुछ विशेषज्ञ समितियों ने तो यहां तक सुझाव दिया है कि पैरा-ग्लेशियल क्षेत्र में कोई जलविद्युत परियोजना स्थापित नहीं की जानी चाहिए।

जब त्रासदी आती है, तो पर्यावरण विनाश की मानवीय लागत दुखद रूप से चल रही परियोजनाओं में गरीब प्रवासी श्रमिकों और निवासियों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों द्वारा वहन की जाती है। परियोजनाओं को मंजूरी देने वाली सरकारी संस्थाएं या उन्हें निष्पादित करने वाले डेवलपर पहाड़ों के प्रकोप से बच जाते हैं।

अल्प समीक्षा जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ताओं के लिए निराशा की बात यह है कि अदालतों का दरवाजा खटखटाने और विशेषज्ञ समितियों के गठन के बावजूद उनकी सिफारिशें धूल फांक रही हैं। शायद ही कोई उचित परिश्रम, जिसमें जोखिम मूल्यांकन, सुरक्षा उपाय और भूवैज्ञानिक और भूकंपीय विश्लेषण शामिल है, पहाड़ों में करोड़ों रुपये की मेगा परियोजनाओं में से किसी में भी जाता है।

विकास के नाम पर हम मनमानी नहीं कर सकते हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी जैव विविधता में नाजुक संतुलन को बिगाड़ना। यह सुनिश्चित करना हम सभी का दायित्व है कि हिमालय और इसकी छाया में रहने वाले लोग सुरक्षित रहें।

वांगचुक की लड़ाई सिर्फ लद्दाख की लड़ाई नहीं है और उसके लोग. यह पूरी मानवता और उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक लड़ाई है।

संपादक के नाम चिठी

सर्वेक्षण पूर्व निष्कर्ष हिंदू -सीएसडीएस-लोकनीति चुनाव पूर्व सर्वेक्षण 2024 के निष्कर्ष, कि "नौकरियां, मुद्रास्फीति" लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दे हैं (पेज 1, ओपिनियन पेज, अंदर के पेज, 11 अप्रैल) शायद ही आश्चर्यजनक हैं। आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी के बोझ तले दब रहा है।

बढ़ती आय असमानता यह भी एक और बड़ी चिंता के रूप में उभरी है। हालाँकि, आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों के बारे में सबसे कम चिंतित है और केवल '400 सीटों' और 'कार्यालय में पहले 100 दिनों के लिए एक कार्य कार्यक्रम' के संदर्भ में बात कर रही है। कि भाजपा जनता का ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों से भटका कर बच निकलने में सक्षम है

आजीविका के मुद्दे और इसके बजाय विभाजनकारी मुद्दों को उठाने पर ध्यान केंद्रित करना मुख्यधारा मीडिया की बंधक स्थिति का एक दुखद प्रतिबिंब है। सही सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं. विपक्षी दल भी महत्वपूर्ण आजीविका पर भाजपा को रोकने में विफल रहे हैं

आम आदमी को प्रभावित करने वाले मुद्दे। बीजेपी के पास है दूर जाने की इजाजत दे दी गई भ्रष्टाचार के खिलाफ योद्धा होने की भ्रामक छवि के साथ, जबकि यह चुनावी बांड योजना के माध्यम से प्राप्त धन का प्रमुख लाभार्थी रहा है।

मनोहर अलेम्बथ, कन्नूर, केरल

ऐसा लगता है कि सर्वेक्षण में कुछ भ्रमित करने वाले नतीजे सामने आए हैं। जबकि ए की प्राथमिक चिंताएँ सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश लोग बेरोजगारी और मुद्रास्फीति से पीड़ित हैं, ऐसा कैसे है कि 48% ने महसूस किया है कि उनके जीवन की गुणवत्ता 'बहुत' या 'कुछ हद तक बेहतर' थी? इससे यह भी पता चलता है कि 55% लोगों ने महसूस किया है कि भ्रष्टाचार 'बढ़ गया है'। यदि सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं द्वारा बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और भ्रष्टाचार पर व्यक्त की गई राय प्रतिबिंबित होती है लोगों के व्यापक वर्ग की राय के अनुसार, हमारे राजनीतिक दलों के लिए बहुत सारे आश्चर्य हो सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म, जाति या लिंग के बावजूद अधिकांश कमजोर वर्गों को देश में देखी गई 'मजबूत' जीडीपी वृद्धि से कोई लाभ नहीं हुआ है।

कोसाराजू चंद्रमौली, हैदराबाद

Machine Translated by Google

अर्थव्यवस्था के बावजूद बीजेपी कैसे है अच्छी स्थिति में?

राम मंदिर के निर्माण और प्रतिष्ठा के माध्यम से हिंदू पहचान को मजबूत करना, नेतृत्व कारक, और दो मुद्दों पर कई मतदाताओं की दुविधा - समान नागरिक संहिता और धारा 370 को कमजोर करना - भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है और उसे अर्थव्यवस्था के बारे में असंतोष को दूर करने में मदद मिल सकती है

सुहास पलशिकर, संजय
कुमार एवं संदीप शास्त्री

आरeports पर आधारित है
चुनाव पूर्व सर्वेक्षण
लोकनीति का-
विकासशील समाजों के अध्ययन केंद्र
(सीएसडीएस),
इन पृष्ठों में प्रकाशित
11 अप्रैल को, पर ध्यान केंद्रित किया
ऐसे कारक जिनमें इसके पक्ष में काम करने की क्षमता थी
लोकसभा चुनाव में विपक्ष. उन्होंने संभावित गड़बड़ियों का संकेत दिया

भाजपा का कवच. लोकप्रिय
आर्थिक स्थिति की अस्वीकृति इसका कारण होनी चाहिए
बीजेपी के लिए चिंता की बात है. हो-वेवर, इसकी बयानबाजी का भाव यह संकेत देता है कि भाजपा
इसे बरकरार रखने की सहमति है
चुनावी बढ़त.
पार्टी को क्या लगता है
इतना संतुष्ट?

धारणाएं और नारे

आज की रिपोर्टों में, हम जो प्रतीत होता है
उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं
के पक्ष में काम कर रहे हैं
सामान्य तौर पर सत्तारूढ़ गठबंधन
और विशेष रूप से भाजपा।
लोकनीति-सीएसडीएस के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण से पता चलता है कि कई संकेतक संतुलन को झुकाने की क्षमता रखते हैं।

सत्ताधारी दल का पक्ष.
भारत की एक सुधरी हुई छवि की धारणा दोनों

देश के भीतर और
विदेश में, प्रमुख रणनीतियों की उल्लेखनीय स्वीकृति,
और एक दृश्यमान दुविधा
कुछ मुद्दों के संबंध में
बीजेपी को मदद मिलने की संभावना है.
लेकिन सब से ऊपर,
हिंदू की मजबूती
पहचान और बीजेपी साफ़
राम से तादात्म्य
मंदिर मुद्दा मदद कर सकता है
पार्टी को इससे उपजे असंतोष का सामना करना पड़ा
अर्थव्यवस्था। अगले भाग में
इस श्रृंखला में, हम भी करेंगे
नेतृत्व कारक पर ध्यान केंद्रित करें, सभी को पकड़ने वाला गोंद
सकारात्मक कारक एक साथ

बीजेपी के लिए.
सवाल भारत का
वैश्विक छवि कुछ तो है
जिसका फायदा बीजेपी उठा सकती है.
लगभग 8%
उत्तरदाताओं ने कहा कि
एक बात जो उन्हें पसंद आयी
नरेंद्र मोदी सरकार इस पर काम कर रही थी

सामने, यानी, एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने का।

एक संबंधित मजबूत बिंदु,
यद्यपि यह कुछ-कुछ संकीर्ण सामाजिक वर्ग के लिए प्रासंगिक है,
जी20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन है।
जबकि कई उत्तरदाता
जी20 के बारे में नहीं सुना था
नई दिल्ली में आयोजित हुआ शिखर सम्मेलन
जो शहरों में हैं और साथ में हैं
मीडिया में उच्च प्रदर्शन
घटना से अवगत थे.
उनमें से जो थे
घटना से अवगत, निकट
प्रत्येक 10 में से सात इसके प्रभाव के बारे में सकारात्मक थे। वे
महसूस किया कि यह प्रतिक्रियात्मक था
भारत की बढ़ती ताकत.
उन्होंने इसे विदेशी के तौर पर भी देखा
नीति उपलब्धि कि
व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी
और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दें।
यद्यपि यह समर्थन
पतला दिखाई दे सकता है, यह था
समाज के उच्च वर्गों द्वारा इसका समर्थन किया जा सकता है
भाजपा को यह धारणा बनाने में मदद करें कि
चीजें सही दिशा में जा रही हैं।

बीजेपी का प्रमुख नारा
2014 का लोकसभा चुनाव 'सबका साथ' था।

'सबका विकास'. 2019 में पार्टी की जीत के बाद
प्रधानमंत्री ने इस नारे में 'सबका विश्वास'
जोड़ा.
चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में यह
आकांक्षा प्रतिध्वनित हुई
तीन-चौथाई से अधिक
उत्तरदाताओं उत्तरदाताओं का भारी बहुमत
इस विचार का समर्थन करता हुआ दिखाई दिया कि भारत

एक देश रहना चाहिए
जहां विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रह सकते हैं और
अपने विश्वास का स्वतंत्र रूप से अभ्यास करें।
जिनकी पहुँच अधिक है

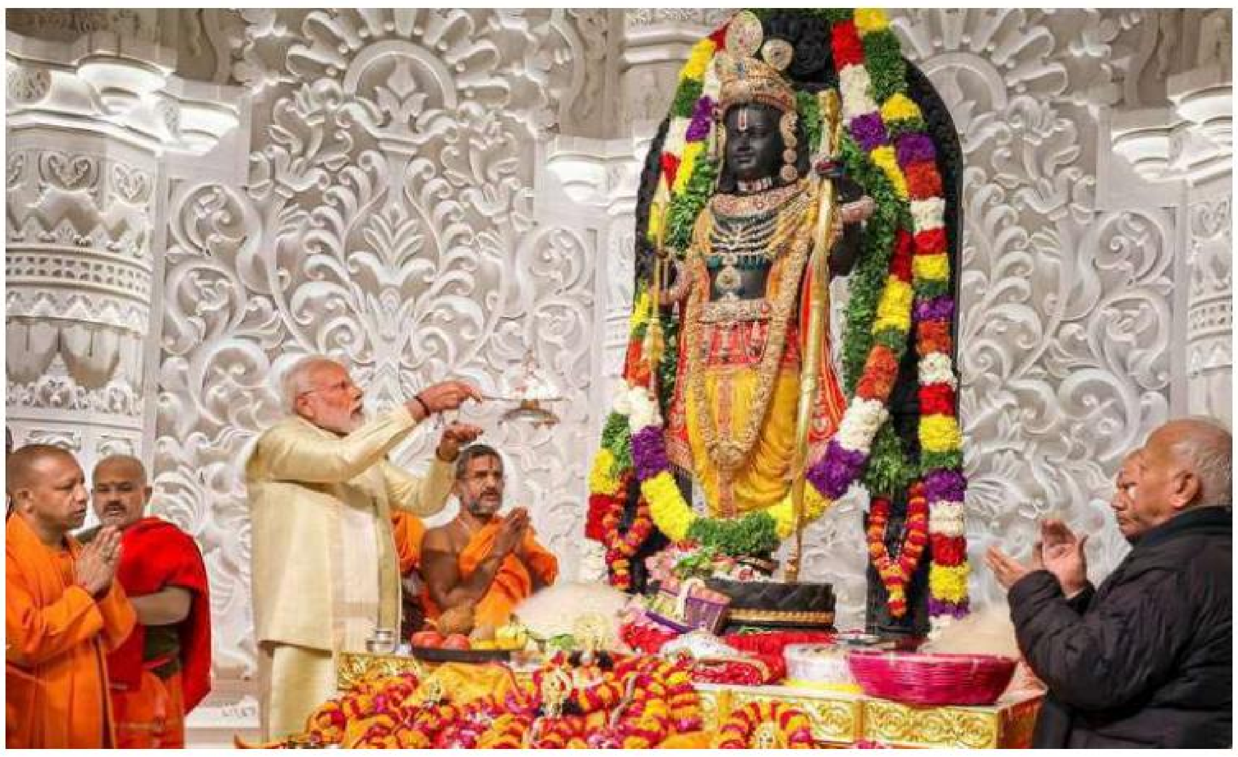

एक विचारोत्तेजक मुद्दा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख
22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक के दौरान मोहन भागवत ने राम लला की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। पीटीआई

शिक्षा को दिखाई दिया
इस कथन का समर्थन करें
और अधिक मजबूती से.

मुद्दों पर दुविधा
समान नागरिक व्यवस्था की दिशा में एक संभावित कदम
संहिता (यूसीसी), और अनुच्छेद 370 का
कमजोर होना, हैं
दो तख्ते जो हो सकते हैं
को संतुष्टि प्रदान करें
बीजेपी के पारंपरिक वोटर ज्यादा हैं. इसके
अलावा, कई मतदाताओं की दुविधा भी जारी है
ये दो मुद्दे काम कर सकते हैं
बीजेपी के फायदे के लिए.
यूसीसी पर, से भी अधिक
आधे उत्तरदाताओं के पास था
इसके बारे में नहीं सुना या पसंद नहीं किया
एक राय व्यक्त करने के लिए नहीं
इस पर। जबकि एक-चौथाई से अधिक ने
कहा कि यह महिलाओं को सशक्त बनाएगा,
उससे कम
प्रत्येक 10 में से दो ने ऐसा कहा
धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप हो सकता है।

आर्टिकल 370 के कमजोर पड़ने पर,
प्रत्येक 10 में से चार

उत्तरदाताओं के पास या तो नहीं था
इसके बारे में सुना या नहीं लिया
खड़ा होना। जबकि इससे भी ज्यादा
एक-तिहाई ने कहा कि यह एक था
अच्छा कदम, छठा भाग महसूस हुआ
कि यह अच्छा कदम था लेकिन
सही तरीके से नहीं किया गया.
दुविधा बनी रहेगी
ये मुद्दे बीजेपी की मदद करते हैं या
कुछ की अनिच्छा होगी
उत्तरदाताओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए
आश्चर्य की बात है?
यह स्पष्ट नहीं है कि
विपक्ष सक्षम होगा
इन दुविधाओं का अपने पक्ष में फायदा उठाने के लिए। पर
जाति जनगणना भी, अधिक
आधे से अधिक उत्तरदाता
इसके बारे में न तो सुना था और न ही सुना था
पर कोई राय व्यक्त न करें
यह। एक-चौथाई ने कहा कि
कांग्रेस और उसके सहयोगी थे
जाति को लेकर गंभीर
जनगणना जबकि एक तिहाई ने कहा
कि यह एक राजनीतिक उपकरण था।
इस प्रकार, संभावित रूप से विवादास्पद और जटिल है-

मुकदमा, स्पष्ट का अभाव
विकल्प जो प्रतिध्वनित होता है
मतदाताओं के साथ काम कर सकते हैं
बीजेपी के पक्ष में.

हिंदू पहचान

सबसे बढ़कर, भाजपा के पास एक है
को स्थानांतरित करने का अवसर
अभियान का फोकस. ए
उत्तरदाताओं की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी का उल्लेख किया गया है
राम मंदिर सबसे बड़ा
मोदी सरकार का काम पसंद आया. तो,
निर्माण और अभिषेक

मंदिर में कई मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में मोड़ने की क्षमता है।

राम मंदिर है
के एक प्रमुख घटक के रूप में बहुत सारी बहस
का केंद्र बिंदु रहा है
बीजेपी की चुनावी रणनीति.
चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में
लगभग आधे उत्तरदाताओं को लगा कि इससे
मदद मिलेगी
हिंदू पहचान को मजबूत करें.
इस दृष्टिकोण का समर्थन
के बीच बहुत अधिक था

हिंदू उत्तरदाता.
वहां के हिंदुओं में
एक स्पष्ट वर्ग और जाति थी
की तीव्रता में विभाजित करें
प्रतिक्रिया। समेकन का दावा जितना अधिक होगा
आर्थिक रूप से संपन्न उत्तरदाताओं और उच्च जातियों के बीच दिखाई दे रहा था।

जबकि एक-चौथाई अल्पसंख्यकों ने भी यही विचार रखा
कि मंदिर मदद करेगा
हिंदू पहचान को मजबूत करें,
मुसलमानों का बहुमत
उत्तरदाताओं ने नहीं व्यक्त किया
इस पर राय.
इस दावे को देखते हुए कि
राम मंदिर ने नेतृत्व किया है
का अधिक एकीकरण
हिंदू पहचान, यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा
बीजेपी की चुनावी रणनीति
इस समय के आसपास। एक चेतावनी
यहाँ क्रम में है: जनता की राय अभी भी भारत के समावेशी विचार के प्रति अधिक अनुकूल है।
कैसे

दूर की राजनीति और अभियान

> **जनता की राय अभी बाकी है अधिक अनुकूलता से**
> एक की ओर झुकाव
> **भारत का समावेशी विचार**

समाज के इस सहज गुण पर विजय पाना अभी भी संभव है
देखा गया।

बीजेपी के लिए मुश्किलें!
जबकि मंदिर मुद्दा हो सकता है
भाजपा को बेअसर करने में सक्षम बनाएं
आर्थिक-आर्थिक मुद्दों पर प्रतिकूल भावनाएं,
कुछ अन्य
कारक नकारात्मक भावनाओं को बढ़ा सकते हैं
पदधारी. विश्वास
चुनाव आयोग
भारत (ईसीआई) की तुलना में नाटकीय रूप से गिरावट आई है
पांच साल पहले. 2019 में
लोकनीति-सीएसडीएस सर्वेक्षण, और अधिक
आधे से अधिक उत्तरदाता
पर बहुत भरोसा जताया
ईसीआई; इससे इनकार कर दिया गया है
प्रत्येक 10 में से तीन से कम।
उन लोगों का हिस्सा जो
बहुत कम भरोसा करना या बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना
ईसीआई में दोगुना हो गया है
पिछले पांच साल. यह
यह देखना दिलचस्प है कि क्या
यह घटता विश्वास भाजपा के समर्थन पर असर डालेगा।
सरकार जैसी एजेंसियों के कार्यों पर

प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय ब्यूरो

जांच के बाद, प्रतिक्रिया के बीच तीन गुना
समान विभाजन दिखाई देता है

जिन्होंने ये कहा
एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा था
राजनीतिक प्रतिशोध के लिए, वे
जिन्होंने कहा कि वे थे
सीमा के अंदर काम कर रहे हैं
कानून का, और जिनके पास था
विषय पर कोई राय नहीं.
क्या काम आ सकता है
बीजेपी का फायदा इतना करीब है
अपने आधे समर्थकों से कहा
कि ये एजेंसियाँ थीं
पार्टी को बनाए रखने की अनुमति देते हुए, कानून के भीतर काम करना

इसका मतदाता आधार.
इसके विपरीत, के मुद्दे
पार्टी बदलना, गैर-वैचारिक गठबंधन और
भाई-भतीजावाद भाजपा को परेशान कर सकते हैं
सीमांत रूप से - शब्दों में कम
छवि के संदर्भ में और भी बहुत कुछ
कोर के समर्थन का
आधार। लगभग आधे उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि वे
स्विच ऑन करके खुद को बचा रहे थे

प्रवर्तन अभिकरण।
आधे से ज्यादा बीजेपी के
समर्थकों का मानना था कि पार्टी को अन्य
दलों के दागी नेताओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए। गठबंधन के संबंध में,

बीजेपी समर्थक ज्यादा थे
यह रुख अपनाने की संभावना है
राजनीति में सब कुछ जायज है
और वैचारिक शुद्धता है
कोई कारक नहीं. वहाँ था
कमोबेश समान समर्थन
इस विचार से कि भाजपा है
की तुलना में कम भाई-भतीजावाद
कांग्रेस और वह
बीजेपी उतनी ही भाई-भतीजावादी है
कांग्रेस। बीजेपी का एक तिहाई
समर्थकों ने कहा कि बीजेपी
की तुलना में कम भाई-भतीजावादी था
कांग्रेस। इससे पता चलता है
कि उत्तरदाता थे
इसे देखने की अधिक संभावना है
उनके लेंस से मुद्दा
पार्टी अलगाव.
यह उन कारकों की टोकरी है जो भाजपा
के पास हो सकते हैं
साथ सौदा करने के लिए। पार्टी है
राम पर भरोसा करने की संभावना
निसंदेह मंदिर मुद्दा
इनमें से सबसे प्रमुख
अन्य को टालने के लिए कारक
कारक. इसके अलावा, नकारात्मक भावनाएँ
भी उत्पन्न होती हैं
उपरोक्त कुछ कारकों में से कुछ को ट्रम्प किया
जा सकता है
नेतृत्व कारक.

सुहास पल्शिकर ने राजनीतिक शिक्षा दी विज्ञान और अध्ययन के मुख्य संपादक हैं भारतीय राजनीति में; संदीप शास्त्री एनआईटीटीई के निदेशक-शिक्षाविद हैं शिक्षा ट्रस्ट, और राष्ट्रीय लोकनीति के संयोजक नेटवर्क; और संजय कुमार हैं प्रोफेसर एवं सह-निदेशक लोकनीति-सीएसडीएस

'राम मंदिर के निर्माण से बीजेपी को हिंदू पहचान मजबूत करने में मदद मिलेगी'

सुहास पलशिकर

अयोध्या में राम मंदिर शायद सबसे प्रसिद्ध है
विचारोत्तेजक मुद्दा जो है
अधिक समय तक राजनीति को आकार दिया
अब तीन दशक। मैं फ़िन
1990 के दशक में, राम जन्मभूमि आंदोलन
ने हिंदू जनमत को संगठित किया

पूरे देश में, मुख्य रूप से
उत्तर और पश्चिम में,
और बीजेपी को आगे बढ़ाया
राजनीति का केंद्र बिंदु,
का निर्माण
मंदिर और उसकी प्रतिष्ठा इसी वर्ष जनवरी में

पार्टी को चुपचाप हिंदू को मजबूत करने में
मदद मिली है
पहचान। क्या अभियान के दौरान इस मुद्दे को
फोकस में लाया जाएगा

महत्वपूर्ण नहीं। यदि यह है,
बीजेपी आगे भी बना सकती है
लाभ, लेकिन भले ही ऐसा न हो,
भाजपा पहले ही खुद को एक ऐसी पार्टी के रूप में स्थापित कर चुकी है हिंदू गौरव के लिए खड़ा है.

संदर्भ बिंदु

हमने यह प्री-पोल आयोजित किया
दो से अधिक का सर्वेक्षण करें
मंदिर के अभिषेक के कुछ महीने बाद। फिर भी,

मंदिर का अभिषेक
के मन में अंकित हो गया था
उत्तरदाताओं को एक प्रमुख के रूप में
आयोजन। जबकि अभिषेक का व्यापक रूप
से स्वागत किया गया,
गैर-हिन्दू अल्पसंख्यकों पर इसके प्रभाव पर भी
संदेह व्यक्त किया गया

लगभग पूर्ण अवस्था
कार्यक्रम का प्रायोजन
अयोध्या. चुनाव के रूप में
अभियान का खुलासा,
मंदिर पहले से ही एक भूमिगत मुद्दा बन चुका है

जिसे मतदाता लेकर जाएंगे
मतदान केंद्र। और निर्विवाद रूप से, समस्या
उत्पन्न होने की संभावना है
बीजेपी के पक्ष में काम करें.
सर्वे में कब
'सबसे' का नाम बताने को कहा
22% से अधिक लोगों को इस सरकार का
कदम पसंद आया-

Table 1: There is a belief that Ram Mandir will consolidate Hindu identity

(%)

The construction of Ram Mandir will	
Help in consolidating Hindu identity	48
Not impact Hindus much	25
No opinion	24

Note: Rest were not aware of Ram Mandir.
Question: Some people say that construction of the Ram Mandir will consolidate Hindu identity while others say Hindus are not really impacted by this. What is your opinion?

Table 3: Rich & upper castes were more likely to believe that the Mandir will consolidate Hindu identity

(%)

	Help in consolidating Hindu identity
Overall	48
Class	
Poor	43
Lower	47
Middle	49
Upper	58
Caste group	
Hindu upper caste	59
Hindu OBC	55
Hindu SCs	46
Hindu STs	47

Table 2: Religious divide on Mandir issue

(%)

	The construction of Ram Mandir will		
	Help in consolidating Hindu identity	Not impact Hindus much	No opinion
Hindu	54	25	18
Muslim	24	21	50
Other minorities	22	36	30

Note: Rest were not aware of the Ram Mandir

Table 4: The Ram Mandir resonates a little less in the south and east

(%)

	The construction of Ram Mandir will		
	Help in consolidating Hindu identity	Not impact Hindus much	Don't know
North and West	51	24	23
South	43	28	23
East and Northeast	45	25	26

Note: Rest were not aware of the Ram Mandir

पंडितों ने उल्लेख किया
राम का निर्माण
मंदिर. लगभग आधे उत्तरदाताओं ने कहा कि
मंदिर का निर्माण होगा

हिन-डु पहचान को मजबूत करने में मदद
(तालिका 1)। यह
मूल्यांकन को सही ठहराया गया
गैर-हिंदुओं की तुलना में हिंदुओं द्वारा अधिक
(तालिका 2)। यह इस प्रकार है-

Table 5: Will the Ram Mandir increase communal differences?

	The construction of Ram Mandir will			
	Increase harmony between Hindus and Muslims	Increase differences among the two communities	Make no difference	No Opinion
Overall	27	24	26	20
Hindu	31	22	27	18
Muslim	13	32	24	26
Other minorities	14	29	24	23

Note: Rest were not aware of the Ram Mandir.
Question asked: People have different views about the construction of the Ram Mandir in Ayodhya. Some people say it will foster harmony between Hindus and Muslims. Others say that it may increase differences between the communities. What is your opinion?

सेशन प्रचलित था
महिला-पुरुषों की तुलना में पुरुषों में अधिक
(विपरीत 49% पुरुष)।
46% महिलाओं ने माना
कि यह हिंदू-दु पहचान को मजबूत करेगा)।
अमीर और
हिंदू उच्च जातियाँ,
मध्य के बाद
वर्ग और हिंदू अन्य
पिछड़ा वर्ग थे
उस पर विश्वास करने की अधिक संभावना है
राम मंदिर हिंदू पहचान को मजबूत करेगा
(तालिका 3)। यह आकलन था

इसकी तुलना में ग्रामीण उत्तरदाताओं (50%)
ने इसे अधिक समर्थन दिया
शहरी उत्तरदाताओं के लिए और
युवा (52%). यह भी
देखें कि मंदिर बनेगा
हिंदू पहचान को मजबूत करें
देश में अधिक उत्तरदाताओं द्वारा आयोजित
किया गया था
उत्तर और पश्चिम की तुलना
पूर्व और दक्षिण की ओर
(तालिका 4)।

धार्मिक विभाजन

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि
मंदिर मुद्दा भी है
धार्मिक-धार्मिक विभाजन की ओर ले जाने की
संभावना। कुल मिलाकर, ख़त्म
प्रत्येक चार उत्तरदाताओं में से एक इस
दृष्टिकोण से सहमत था
कि ऐसा ही होगा.

यह दृष्टिकोण गैर-हिन्दुओं में अधिक प्रमुख था

हिंदुओं की तुलना में. हो-वेवर, दो बिंदुओं की जरूरत है
यहां ध्यान दें: एक, सम
हिंदुओं में, से भी अधिक
हममें से दो ने माना कि मंदिर मुद्दा है

मतभेद बढ़ेंगे
दो समुदायों के बीच; और दो, लगभग एक-

उत्तरदाताओं में से पांचवें ने किया
पर कोई राय नहीं है
यह मामला (तालिका 5).
अगर बीजेपी आगे बढ़ती है
इन भावनाओं के बीच
यह हिंदुओं को इकट्ठा कर सकता है
दोनों में अधिक समर्थन
जिन क्षेत्रों में ऐसी भावना प्रबल है और

वे क्षेत्र जहां पार्टी नए सिरे से पैठ बनाना
चाहती है। आने वाले दिनों में,

यह दिलचस्प होगा
देखिये बीजेपी कैसे इस्तेमाल करती है
यह पहले से मौजूद सामाजिक वातावरण
उसके लाभ के लिए है
और यह भी कि क्या विपक्ष की कोई
राजनीतिक स्थिति है
उस पर व्यवहार्य प्रतिक्रिया।

सुहास पल्शिकर ने राजनीतिक शिक्षा दी विज्ञान और अध्ययन के मुख्य संपादक हैं भारतीय राजनीति में

धार्मिक बहुलवाद के लिए उल्लेखनीय समर्थन

Table 1: Religious tolerance in India

(%)

India belongs to citizens of all religions equally, not just Hindus	79
India belongs only to Hindus	11
No opinion	10

Question asked: I'm reading out two statements. Please tell me which one you agree with the most?

Table 2: Hindu dominance versus religious equality in India

(%)

	India belongs to citizens of all religions equally, not just Hindus (%)
Overall	79
Religion	
Hindu	77
Muslims	87
Other minorities	81
Age	
18 -25 years	81
56 years and above	73

	India belongs to citizens of all religions equally, not just Hindus (%)
Educational Level	
No Schooling	72
College and above	83
Residence	
Village	76
Town	85
City	84

संजीर आलम
और निर्माण्यु चौहान

भारत सदियों से एक बहु-धार्मिक समाज रहा है।

विभिन्न धर्मों में है
सह-अस्तित्व में रहे और बनाए गए
स्वयं सांस्कृतिक क्षेत्र
सामाजिक क्षेत्र में. धार्मिक बहुलवाद ऐतिहासिक
दुर्घटनाओं से बच गया है

और राजनीतिक बवंडर.
लेकिन कुछ सामाजिक-राजनीतिक
घटनाओं और देश को 'हिंदू राष्ट्र' में बदलने की
बढ़ती मांग

संदेह पैदा किया. धार्मिक का लंबे समय से
पोषित आदर्श है
सहिष्णुता अभी भी लोगों के दिलों के करीब है?
क्या भारत का धर्मनिरपेक्ष सामाजिक ताना-बाना खत्म हो गया है?
गंभीर ख़तरा? चुनाव पूर्व सर्वेक्षण स्पष्ट करने
में मदद करता है
ये संदेह.
निष्कर्षों से यह पता चलता है
प्रचंड बहुमत
उत्तरदाताओं (79%) ने इस विचार का समर्थन
किया
कि भारत सभी धर्मों का समान रूप से है, न
कि सिर्फ
हिंदू; कि इसे एक ऐसा देश बने रहना चाहिए
जहां विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले लोग
रह सकें और अभ्यास कर सकें

उनका विश्वास स्वतंत्र रूप से. धार्मिक बहुलवाद के लिए यह पुनः उल्लेखनीय समर्थन यह दर्शाता है
धार्मिक सहिष्णुता एक निषेधात्मक तत्व बनी
हुई है-

> **शहरी लोग सेटिंग्स दिखाई दीं अधिक सहायक बनें धार्मिक बहुलवाद का**
> उन लोगों की तुलना में
> **ग्रामीण क्षेत्र**

सामाजिक ताने-बाने का निर्धारण.
धार्मिक के लिए यह स्वाभाविक है
अल्पसंख्यकों पर जोर देना होगा
धार्मिक बहुलवाद पर. लेकिन
यह दृष्टिकोण कि भारत का है
सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए
के सदस्यों द्वारा भी धारण किया जाता है
बहुसंख्यक धर्म.
प्रत्येक 10 में लगभग आठ
हिंदुओं ने कहा कि उनके पास है धार्मिक बहुलवाद में विश्वास. सिर्फ 11% हिंदुओं ने कहा
कि वे सोचते हैं कि भारत है
हिंदुओं का राष्ट्र.
इससे अधिक आश्वस्त करने वाली बात क्या है
क्या वह अधिक युवा है
लोग (81%) बूढ़े हैं
(73%) डालने के इच्छुक थे
धार्मिक बहुलवाद पर प्रीमियम। यद्यपि धार्मिक
सहिष्णुता का समर्थन

सामाजिक स्तर पर उच्च है
स्पेक्ट्रम, योग्यताएं शिक्षात्मक
अंतर पैदा करती हैं। के साथ तुलना

उनमें से 72% गैर-स्कूली थे, 83% उच्च श्रेणी
के थे
पढ़े-लिखे लोगों ने ऐसा कहा

वे इसके पक्ष में थे
सभी धर्मों को समान दर्जा.
जबकि सांप्रदायिक तनाव/संघर्ष को
आम तौर पर शहरी घटना के रूप में देखा
जाता है, डेटा दिखाता है

अलग-अलग पैटर्न. जैसा कि आम तौर पर प्रचलित धारणा के विपरीत है विश्वास, उर-प्रतिबंध सेटिंग में रहने वाले लोगों को दिखाई दिया
रहने वालों की तुलना में धार्मिक बहुलवाद
और सहिष्णुता का अधिक समर्थन करें

ग्रामीण इलाकों में।
कुल मिलाकर, एक उच्च डिग्री
धार्मिक बहुलवाद और समानता के लिए
समर्थन
सामाजिक स्तर एक की ओर इशारा करता है
चीजों की जोड़ी। पहला,
उभरती धारणाओं के विपरीत, धार्मिक सह-अस्तित्व और सहिष्णुता का विचार अपना
आधार रखता है

rmly. दूसरा, राजनीतिक क्षेत्र में एक तीव्र
धार्मिक विभाजन आवश्यक रूप से स्थिति
पर प्रभाव नहीं डाल सकता है।

व्यापक समाज. एक,
इसलिए, देखने की जरूरत है
धर्म कैसे शामिल है
चुनावी संदर्भ और
रोजमर्रा की जिंदगी में अलग से।

संजीर आलम एसोसिएट प्रोफेसर हैं सीएसडीएस में और निर्मन्यु चौहान हैं लोकनीति-सीएसडीएस के शोधकर्ता

सेमी
वाई.के
एम एनडी-एनडीई

Machine Translated by Google

मूलपाठ& प्रसंग

0

समाचार संख्या में

प्रदूषण नियंत्रण निकायों में रिक्त पदों की संख्या

6,075 50% से अधिक स्वीकृत 12,016 में से 28 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और आठ प्रदूषण नियंत्रण समितियों में पद हैं खाली। पीटीआई

मार्च में सूनोवर तेल आयात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया

4.45 लाख टन. भारत कम कीमतों का फायदा उठाते हुए मार्च में रिकॉर्ड कच्चे सूरजमुखी तेल का आयात किया, जबकि महीने में देश का कुल खाद्य तेल आयात 11.49 लाख टन तक पहुंच गया। पीटीआई

रिक्त ट्रेन ड्राइवर पदों का हिस्सा: रेलवे आरटीआई के जवाब में बोर्ड

14.7इंच प्रतिशत. से बाहर देश भर के सभी रेलवे ज़ोन में ड्राइवरों और सहायक ड्राइवरों दोनों के कुल 1.27 लाख स्वीकृत पद, 1 मार्च तक 18,766 खाली पड़े थे। पीटीआई

में भारत का स्थान विश्व साइबर अपराध अनुक्रमणिका

10 प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जर्नल पीएलओएस वन में, रूस साइबर अपराध की सूची में सबसे ऊपर है, जिसमें अग्रिम शुल्क भुगतान करने वाले लोगों से जुड़ी धोखाधड़ी सबसे आम प्रकार है। पीटीआई

मई तक भारत से श्रमिकों को इजराइल लाया जाएगा

6,000 भारतीय कामगार आएंगे में पहुंचें इज़राइल देश के निर्माण क्षेत्र को श्रमिकों की कमी को पूरा करने में मदद करेगा। पीटीआई

हिंदू डेटा टीम द्वारा संकलित

हमारे पर का पालन करें facebook.com/thehindu twitter.com/the_hindu instagram.com/the_hindu

इसरो का 'शून्य कक्षीय मलबा' मील का पत्थर

PSLV-C58/XPoSat मिशन के बाद इसरो ने यह कैसे सुनिश्चित किया कि पृथ्वी की कक्षा में व्यावहारिक रूप से कोई मलबा न बचे? PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल-3 (POEM-3) का उद्देश्य और कार्य क्या है ? यह अंतरिक्ष मलबे शमन प्रयासों में कैसे योगदान देता है? अंतरिक्ष मलबे से अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को क्या खतरा है?

व्याख्याता

सुचित्रा कार्तिकेयन

अब तक कहानी:

टी वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने यह कहा है PSLV-C58/XPoSat मिशन है व्यावहारिक रूप से शून्य मलबा छोड़ा गया पृथ्वी की कक्षा. अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि मिशन में उपयोग किए गए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) के अंतिम चरण को एक प्रकार के कक्षीय स्टेशन में बदल दिया गया था - जिसे पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल -3 (पीओईएम-3) कहा जाता है - इसे फिर से छोड़ने से पहले - मिशन पूरा होने के बाद कक्षा में घूमने के बजाय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करें। इसरो ने कहा कि सभी उपग्रहों को उनकी लक्षित कक्षाओं में स्थापित करने का प्राथमिक मिशन पूरा करने के बाद, पीएसएलवी के चौथे चरण को पीओईएम-3 में बदल दिया गया। बाद में इसे 650 किमी से 350 किमी तक डी-ऑर्बिट किया गया, जिससे यह पृथ्वी की ओर खींचे जाने और वायुमंडल में जलने के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया। इसरो ने यह भी कहा कि उसने विस्फोट से बचने के लिए "मंच को निष्क्रिय कर दिया", यानी अपना ईंधन डंप कर दिया, जिससे मलबे के छोटे टुकड़े कक्षा में जा सकते थे।

कविता क्या है?

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) द्वारा एक सस्ते अंतरिक्ष मंच के रूप में विकसित, पीओईएम एक कक्षीय मंच के रूप में पीएसएलवी रॉकेट के खर्च किए गए चौथे चरण का उपयोग करता है। जून 2022 में पीएसएलवी-सी53 मिशन में पहली बार इस्तेमाल किया गया, इसरो ने विभिन्न पेलोड के साथ कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए पृथ्वी की कक्षा में पीओईएम लगाया था।

पीओईएम रॉकेट के चौथे चरण के ईंधन टैंक पर लगे सौर पैनलों और लिथियम-आयन बैटरी द्वारा संचालित है। इसमें हीलियम नियंत्रण थ्रस्टर्स के साथ-साथ इसकी ऊंचाई को स्थिर करने के लिए एक नेविगेशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण (एनजीसी) प्रणाली है। एनजीसी प्रणाली में चार सन सेंसर, एक मैग्नेटोमीटर और जाइरोस्कोप हैं, और यह नेविगेशन के लिए इसरो के NavIC उपग्रह समूह से बात करता है। POEM में ग्राउंड स्टेशन के साथ संचार करने के लिए एक दूरसंचार प्रणाली भी है।

कक्षीय ख़तरा: पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों की संख्या में वृद्धि के साथ, अंतरिक्ष मलबा एक गंभीर मुद्दा बन गया है। एएफपी

इसरो ने पहली बार 2019 में अपने PSLV C-44 मिशन में अपने रॉकेट के खर्च किए गए चौथे चरण के पुन: उपयोग का प्रदर्शन किया। उपग्रहों को लक्ष्य कक्षाओं में इंजेक्ट करने के बाद, चौथे चरण, कलामसैट-वी 2 नामक एक छात्र पेलोड को उच्चतर ले जाया गया। 443 किमी की गोलाकार कक्षा में पहुंचा और पेलोड की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए वहां रुका।

POEM-3 ने क्या हासिल किया है?

इसरो ने 1 जनवरी को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी सी-58 मिशन लॉन्च किया था।

XPoSat उपग्रह को तैनात करने के बाद इसकी वांछित कक्षा 650 किमी, चौथा चरण, जिसे अब पीओईएम-3 कहा जाता है, को 350 किमी ऊंची गोलाकार कक्षा में उतारा गया। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जितनी निचली कक्षा में होता है, उसे उतना ही अधिक खिंचाव का अनुभव होता है और कक्षा में बने रहने के लिए उसे उतनी ही अधिक ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता होती है।

पीओईएम-3 में नौ पेलोड शामिल हैं: वीएसएससी और बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से दो-दो, स्टार्ट-अप टेकमी2स्पेस, इंस्पेसिटी स्पेस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, ध्रुव स्पेस से एक-एक, और एलबीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एक-एक। इसरो की भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद।

इसने चारों ओर 400 परिक्रमाएँ पूरी कीं

पृथ्वी अपने 25वें दिन तक। इस समय पेलोड को अपने प्रयोगों को निष्पादित करने के लिए चालू किया गया था। ARKA200, RUDRA और LEAP-TD ने अपने-अपने प्रयोग पूरे कर लिए, जबकि WeSAT, RSEM और DEX से डेटा जमीन पर आगे के विश्लेषण के लिए प्रत्येक कक्षा के बाद एकत्र किया गया। वीएसएससी के दो ईंधन सेल ने बिजली पैदा करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। 27 जनवरी, 2024 तक, POEM-3 के सभी पेलोड उद्देश्य पूरे हो गए।

दो महीने के लिए, POEM-3 ने अपने पुन: प्रवेश के लिए तैयारी की, जबकि इसरो ने बेंगलुरु, लखनऊ, मॉरीशस, श्रीहरिकोटा, पोर्ट ब्लेयर, तिरुवनंतपुरम, ब्रुनेई और बियाक (इंडोनेशिया) और मल्टी में अपने टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क स्टेशनों के साथ इसे ट्रैक किया। -श्रीहरिकोटा में ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार (एमओटीआर)। 21 मार्च को, POEM-3 ने अपने अंतिम अंत को पूरा करते हुए, पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों की संख्या में वृद्धि के साथ, अंतरिक्ष मलबा एक गंभीर मुद्दा बन गया है। पृथ्वी की निचली कक्षा (एलईओ) में अंतरिक्ष मलबे में मुख्य रूप से अंतरिक्ष यान, रॉकेट और निष्क्रिय उपग्रहों के टुकड़े और खराब हो चुकी वस्तुओं के टुकड़े शामिल हैं।

एंटी-सैटेलाइट मिसाइल परीक्षणों के परिणामस्वरूप विस्फोटक रूप से। यह मलबा अक्सर 27,000 किमी/घंटा की तेज़ गति से इधर-उधर घूमता रहता है। अपनी विशाल मात्रा और गति के कारण, वे कई अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

LEO पृथ्वी की सतह से 100 किमी ऊपर से लेकर 2000 किमी ऊपर तक फैला हुआ है। इसमें खुफिया डेटा, एन्क्रिप्टेड संचार और नेविगेशन पर नज़र रखने वाले उपग्रह शामिल हैं। इसरो की अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार, दुनिया ने 2022 में 179 प्रक्षेपणों में 2,533 वस्तुओं को अंतरिक्ष में रखा।

मलबा भी मौजूद है, लेकिन कम मात्रा में, पृथ्वी की सतह से 36,000 किमी ऊपर जियोसिंक्रोनस कक्षा (जीईओ) में। वर्तमान में, 7,000 परिचालन उपग्रह अंतरिक्ष मलबे के लाखों टुकड़ों के साथ अलग-अलग ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। यूएस स्पेस कमांड LEO में 10 सेंटीमीटर से बड़े और GEO में 0.3-1 मीटर से बड़े अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक और सूचीबद्ध करता है।

एजेंसियां मलबे से कैसे निपट रही हैं?

अंतरिक्ष मलबे द्वारा तबाही मचाने की नवीनतम घटना 8 मार्च को दर्ज की गई थी जब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन द्वारा गिराया गया एक बैटरी पैलेट फ्लोरिडा में एक घर की छत को चीरता हुआ निकल गया था।

जैसे-जैसे अधिक संचार उपग्रह/नक्षत्र लॉन्च किए जाते हैं और अधिक उपग्रह-रोधी परीक्षण किए जाते हैं, कक्षा में अधिक विघटन और टकराव होते हैं, जिससे कक्षा में छोटे टुकड़े पैदा होते हैं। इसरो के अनुमान के अनुसार, LEO में 10 सेमी से अधिक आकार की अंतरिक्ष वस्तुओं (मलबा या कार्यात्मक उपकरण) की संख्या 2030 तक लगभग 60,000 होने की उम्मीद है। अंतरिक्ष मलबा कक्षा के अनुपयोगी क्षेत्रों का भी निर्माण कर सकता है जहां बहुत अधिक मलबा जमा हो गया है, और जो टकराव के एक व्यापक हिमस्खलन को ट्रिगर कर सकता है जो मलबे के और भी अधिक, लेकिन छोटे टुकड़े उत्पन्न करता है।

वर्तमान में, LEO मलबे से संबंधित कोई अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून नहीं हैं। अधिकांश अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देश इंटर-एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी (IADC) द्वारा निर्दिष्ट स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन दिशानिर्देश 2002 का पालन करते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में समर्थन दिया था।

सार

इसरो ने PSLV-C58/XPoSat मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया, XPoSat उपग्रह को कक्षा में तैनात किया और बाद में PSLV के अंतिम चरण को PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल-3 (POEM-3) में बदल दिया।

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) द्वारा विकसित, पीओईएम वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए एक कक्षीय मंच के रूप में पीएसएलवी रॉकेट के खर्च किए गए चौथे चरण का उपयोग करता है।

POEM-3 ने पृथ्वी के चारों ओर 400 परिक्रमाएँ पूरी कीं, पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने से पहले विभिन्न प्रयोगों को संचालित करने के लिए नौ पेलोड का संचालन किया।

कक्षा में उपग्रहों की बढ़ती संख्या के साथ, अंतरिक्ष मलबा अंतरिक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है संपत्तियां।

क्या उम्मीदवार के खुलासे में पारदर्शिता की कमी है?

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने वाले गंभीर आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों के बारे में चिंताओं को कैसे संबोधित किया है? इन मुद्दों के समाधान के लिए विधि आयोग और चुनाव आयोग द्वारा क्या सुधार प्रस्तावित किए गए हैं?

रंगराजन. आर

अब तक की कहानी: सुप्रीम कोर्ट

टी ने हाल ही में कहा कि उम्मीदवारों को इसकी आवश्यकता नहीं है अपने चुनावी विज्ञापन में जानकारी और कब्जे के प्रत्येक टुकड़े का खुलासा करें जब तक कि वह प्रकृति में पर्याप्त न हो। एक अन्य घटनाक्रम में, भारत के चुनाव आयोग (ईसी) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से तिरुवनंतपुरम से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के नेतृत्व में वार्षिक आय के संबंध में घोषणा को सत्यापित करने के लिए कहा है।

कानून क्या निर्दिष्ट करता है?

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपी अधिनियम) की धारा 33, चुनाव नियमों के नियम 4ए के साथ पढ़ी जाती है, प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एक निर्धारित प्रारूप में एक एडविट के साथ चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र ले जाना आवश्यक है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) में

बनाम भारत संघ (2002), सर्वोच्च

कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को उम्मीदवार और उसके आश्रितों के आपराधिक इतिहास, आय और संपत्ति के विवरण और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता के बारे में जानने का अधिकार है।

इसके परिणामस्वरूप आरपी अधिनियम में धारा 33ए जोड़ी गई, जिसके तहत चुनावी विज्ञापन का हिस्सा बनने के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि के विवरण की आवश्यकता होती है।

आरपी अधिनियम की धारा 125ए आगे यह प्रावधान करती है कि आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता; नामांकन पत्र या विज्ञापन में गलत जानकारी देने या कोई जानकारी छिपाने पर छह महीने तक की कैद या दोनों से दंडनीय होगा।

मुद्दे क्या हैं?

हाल के एक मामले में, अरुणाचल प्रदेश के एक स्वतंत्र उम्मीदवार 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ते समय अपने चुनावी बयान में तीन वाहनों को संपत्ति के रूप में घोषित करने में विफल रहे। उनके चुनाव को गौहाटी उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलट दिया

निर्णय और यह माना गया कि जो जानकारी महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण नहीं है उसका गैर-प्रकटीकरण मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करने के प्रयास के रूप में नहीं माना जा सकता है। श्री चन्द्रशेखर के मामले में, शिकायत उनकी चुनावी घोषणा में उनकी आय और पर्याप्त संपत्तियों को कथित तौर पर छिपाने के बारे में है, जिसका मतदाताओं के निर्णय पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा संबंधित है गंभीर आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ उम्मीदवारों ने कुछ कॉलम खाली छोड़ कर और अपूर्ण एडविट लिखकर नियम 4ए की आवश्यकता को दरकिनार कर दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कॉलम उचित रूप से लिखे गए हैं, एक बार फिर रिसर्जेंस इंडिया बनाम ईसी (2013) में अदालत के आदेश की आवश्यकता थी। एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 के लोकसभा चुनाव में 19% उम्मीदवारों पर बलात्कार, हत्या या अपहरण के आरोप लगे।

विधि आयोग ने 'चुनावी अयोग्यता' (2014) पर अपनी 244वीं रिपोर्ट में और चुनाव आयोग ने अपने ज्ञापन में

2016 में प्रस्तुत 'चुनावी सुधार' में कुछ सिफारिशें प्रदान की गई थीं। सबसे पहले, झूठी वकालत करने के दोषी पाए जाने पर कम से कम दो साल की कैद की सजा होनी चाहिए और अयोग्यता का आधार होना चाहिए। दूसरा, ऐसे मामलों में सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जानी चाहिए। अंत में, जिन व्यक्तियों पर सक्षम अदालत द्वारा कम से कम पांच साल की कैद की सजा का आरोप लगाया गया है, उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, बशर्ते कि मामला चुनाव से कम से कम 6 महीने पहले चलाया गया हो।

जनहित में सर्वोच्च न्यायालय फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) ने उम्मीदवारों के साथ-साथ राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे चुनाव से पहले स्थानीय समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में कम से कम तीन बार घोषणा जारी करें।

आगे का रास्ता क्या हो सकता है?

आरोप-पत्र दाखिल उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने का विभिन्न सत्तारूढ़ दलों द्वारा दुरुपयोग किए जाने की संभावना है। हालाँकि, गलत बयानबाजी के लिए सजा बढ़ाने और इसे अयोग्यता का आधार बनाने के संबंध में अन्य सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता है।

आपराधिक रिकॉर्ड का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। यह एक समझदार मतदाता को अच्छी तरह से सूचित विकल्प चुनने में सक्षम बनाएगा।

रंगराजन आर एक पूर्व आईएएस अधिकारी और 'पॉलिटी सिंपलीड' के लेखक हैं। व्यक्त किये गये विचार व्यक्तिगत हैं

सार

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उम्मीदवार अपने चुनाव विवरण में हर विवरण का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं हैं, जब तक कि जानकारी पर्याप्त प्रकृति की न हो।

उम्मीदवारों द्वारा संपत्ति और आय का खुलासा करने में विफल रहने के उदाहरणों ने सहायता पत्रों की पारदर्शिता और पूर्णता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जबकि आरोपपत्रों के आधार पर उम्मीदवारों को प्रतिबंधित करने का दुरुपयोग किया जा सकता है, झूठी सहायता के लिए कड़ी सजा लागू करना और आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करने में पारदर्शिता बढ़ाना महत्वपूर्ण कदम हैं। बेहतर प्रकटीकरण तंत्र के माध्यम से मतदाता जागरूकता और सूचित विकल्प सुनिश्चित करना चुनावी अखंडता के लिए आवश्यक है।

Machine Translated by Google

सुर्खियों में

जाति और सिनेमा: अमर सिंह चमकीला की लंबी छाया

चमकीला की बायोपिक की स्ट्रीमिंग से पहले, इस पर एक नज़र डालें कि कैसे उनकी जातीय पहचान ने उनके संगीत को प्रभावित किया, जो उनके साथी के साथ चुप रहने के तीन दशक बाद भी प्रासंगिक बना हुआ है।

अनुज कुमार

ए उस्ताद एआर रहमान को लेकर चल रही बहस के बीच और मशहूर निर्देशक इम्तियाज अली के पास है अभूतपूर्व पंजाबी गायक की आगामी बायोपिक में अमर सिंह चमकीला के संगीत की मिट्टी की मिठास और भावनात्मक विशिष्टता को सही ठहराते हुए, उनकी कला को आकार देने में चमकीला की जातीय पहचान की भूमिका के बारे में चर्चा फिर से शुरू हो गई है।

सोशल मीडिया पर एक वर्ग ने दलित सिख चमकीला का किरदार निभाने के लिए पगड़ी हटाने पर दिलजीत दोसांझ पर सवाल उठाया है।
वे उस कलाकार को याद दिलाते हैं जिसने हिंदी सिनेमा में एक पगड़ीधारी नायक को सामान्य बना दिया था क्योंकि वह अपने उस बयान से पलट गया था जिसमें उसने एक फिल्म में भूमिका के लिए अपनी पगड़ी न खोने का वादा किया था।

हालाँकि, जो लोग सिनेमाई धर्म में विश्वास करते हैं, उन्हें लगता है कि अभिनेता ने अपने लुक को चरित्र के जितना करीब हो सके रखकर सही काम किया है। कलाकार की यात्रा को पकड़ने के पिछले प्रयास, जिनमें से एक में दिलजीत को पगड़ी (जोड़ी, 2023) में दिखाया गया था, को क्रियान्वित किया गया था क्योंकि निर्माताओं के पास चमकीला की बायोपिक बनाने का अधिकार नहीं था।

हिंदी सिनेमा में अभिनेताओं द्वारा अपने किरदारों से धार्मिक और सामाजिक प्रतीकों को अपनाना और हटाना काफी आम है। अतीत में, हमने आमिर खान को केतन मेहता की फिल्म मंगल पांडे: द राइजिंग में सिन्दूर का टीका और पवित्र धागा पहने देखा है और परेश रावल ने अमित राय की रोड टू संगम में एक कट्टर मुस्लिम मैकेनिक हशमतुल्लाह के रूप में नमाज अदा की थी। 1936 में, उस समय की सबसे बड़ी स्टार देविका रानी ने फ्रांज ओस्टेन की अछूत कन्या में एक अछूत की भूमिका निभाई थी। अली अब्बास जफर की जोगी (2022) में, दिल्ली में सिख विरोधी दंगों के दौरान सिखों की दुर्दशा को दर्शाने के लिए दिलजीत ने ऑन-स्क्रीन अपने बाल काटे। किसी ने विरोध नहीं किया.

तो, क्या इसका दिलजीत के पिछले बयान से कुछ लेना-देना है या यह उनके द्वारा रविदासिया सिख की भूमिका निभाने के बारे में है?

एकाधिक अंत अधिकांश मनोरंजक कहानियों की तरह, चमकीला की कहानी भी कई अंत की अनुमति देती है। 27 साल की उम्र में उनकी गायिका-पत्नी अमरजोत कौर और उनके दो सहयोगियों की हत्या ने कई साजिश सिद्धांतों को जन्म दिया। क्या अलगाववादियों ने उन्हें ख़त्म कर दिया था, जिन्हें लगता था कि वह अपने 'अश्लील गानों' से युवा पीढ़ी के दिमाग़ को प्रदूषित कर रहे हैं? क्या उन्हें उनके प्रतिद्वंद्वियों ने मार डाला, जो पंजाबी संगीत उद्योग में उनकी नंबर एक की स्थिति से खतरा महसूस कर रहे थे?

या क्या उन्होंने एक जट्ट सिख लड़की से शादी करने की कीमत चुकाई, जो अपना गायन करियर बनाने के लिए अपनी पहली शादी से अलग हो गई थी?

तीनों संभावनाओं में उनकी भूमिका जातिगत पहचान, संसाधनों पर दलित के नियंत्रण को नकारा नहीं जा सकता. क्या उनके गीतों को 1980 के दशक में शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के तरीकों पर दूसरे की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया था? मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। लगभग उसी समय, दो वामपंथी कवियों, जयमल सिंह पड्डा और अवतार सिंह संधू को भी श्रमिकों के अधिकारों के लिए बोलने के लिए मार दिया गया था, जब धार्मिक उग्रवाद चरम पर था। एक दशक पहले, अनुराग कश्यप सक्रिय रूप से इरफान के साथ पाश पर एक फिल्म बनाने पर विचार कर रहे थे, लेकिन यह सफल नहीं हो सका।

हाल ही में, एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हालाँकि, क्षेत्र ने इस पत्रकार को यह बताया गुरु गोबिंद सिंह ने अपने अनुयायियों से अपनी जाति की पहचान को सिंह और कौर जैसे तटस्थ उपनामों में विसर्जित करने के लिए कहा, जातिगत उपनामों को हटाना रोजमर्रा की बात है

अमर सिंह चमकीला में परिणीति चोपड़ा, दिलजीत दोसांझ । विशेष व्यवस्था

पंजाब की हकीकत. उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि अभी भी दो प्रवेश द्वार वाले गुरुद्वारे हैं और कई गांवों में, उच्च जाति और दलित परिवारों के बीच स्पष्ट सीमांकन है।"

राज्य ने दलित सिखों को शीर्ष राजनीतिक और लौकिक दोनों पदों पर देखा है, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने, पिछले कुछ वर्षों में, हरित क्रांति के सामाजिक-आर्थिक परिणामों को सामने लाया है, जहां भूमिहीन दलित श्रमिकों को जट सिख भूमि मालिकों के हाथों शोषण का सामना करना पड़ा।

जाट-प्रभुत्व वाला पंजाबी एलएम उद्योग पंजाब के समाज की इस विविधता का पता लगाने में सक्षम नहीं है, जहां लगभग 32% आबादी अनुसूचित जाति समूहों से आती है। हिंदी सिनेमा की तरह दलित भी हाशिये पर हैं. हाल के दिनों में, हमारे पास गुरविंदर सिंह की अन्हे घोरे दा दान (एलम्स फॉर ए ब्लाइंड हॉर्स, 2011) जैसे छिटपुट उदाहरण हैं, जिसमें ग्रामीण श्रमिक वर्ग की दुर्दशा को दर्शाया गया है, जिसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली है। कला घराने का एक और प्रयास कबीर सिंह चौधरी की मॉक्युमेंट्री थी

मेहसामपुर ने भी चमकीला के जीवन से प्रेरणा ली। लघु एलएम चैम (त्वचा) एक बूचड़खाने में एक दलित कार्यकर्ता की कहानी कहता है।

मनोरंजन के अजीब आकार इतिहास हमें बताता है कि दमन के समय में मनोरंजन अजीब आकार ले सकता है। चमकीला ने गरीब खेत मजदूरों पर तो विचार किया लेकिन अपने गीतों में उनकी जाति के मामलों के बारे में शायद ही कभी बात की। उन्होंने शायद मुख्यधारा में बने रहने के लिए जट्ट गौरव और जट्ट की दुश्मनी (जट की दुश्मनी) पर टिप्पणी की। एक बहुआयामी कलाकार, जिन्होंने अपने गीत लिखे, बनाए और गाए, चमकीला ने संगीत के माध्यम से एक सामंती समाज में अवैध संबंधों, शराब, दहेज, घरेलू हिंसा और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर एक टिप्पणी प्रस्तुत की। ये विषय उनके लोकप्रिय गीतों के दायरे में मौजूद थे। उनके लोकप्रिय गीत 'ललकारा' में, लड़की अपने प्रेमी की मादक द्रव्यों की लत को स्वीकार करती है, जिसकी धर्म द्वारा अनुमति नहीं है। विचारोत्तेजक 'मार ले होर ट्राई' में

जीजा', एक वृद्ध व्यक्ति की भाभी उस पर अपने साथ एक बेटा पैदा करने के लिए दबाव डाल रही है, जब वह कहता है कि उसकी बहन अब उपजाऊ नहीं है। दोनों गाने हानिरहित, चंचल तरीके से ही सही, सामंती समाज की स्याह हकीकत को दर्शाते हैं

ढंग।

प्रो. क्रांतिपाल, जो पंजाबी पढ़ाते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय भाषा विभाग का कहना है कि चमकीला ने अपने गीतों के माध्यम से यह भी संकेत दिया कि कैसे मकान मालिक कार्यकर्ता से सामाजिक दूरी बनाए रखता है लेकिन अपनी पत्नी के साथ समय बिताना पसंद करता है।

श्याम बेनेगल की पहली फ़िल्म अंकुर (1974) भी इसी विषय को अलग-अलग सेटिंग में गंभीरता से देखती है। बाद में, शोषण और समर्पण का यह अंतर्संबंध गोविंद निहलानी की आक्रोश (1980) और गौतम घोष की पार (1984) में उजागर हुआ ।

पंजाब में, संस्कृति अक्सर एक उप-उत्पाद होती है कृषि का. अखाड़े का उपयोग कुश्ती मुकाबले के लिए एक समर्पित स्थान के साथ-साथ एक खुली हवा में संगीत कार्यक्रम में संगीत प्रदर्शन का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जहां चमकीला को अपना स्टारडम मिला। प्रोफेसर पाल कहते हैं, "इस क्षेत्र में एथलेटिकवाद और सौंदर्यशास्त्र जुड़े हुए हैं।"

संगीत में कुछ तो होना ही चाहिए उनका कहना है कि चमकीला ने उनके गीतों को उनकी मृत्यु के तीन दशक बाद भी प्रासंगिक बनाए रखा है। वे कहते हैं, '' उनके जमीनी संगीत में सादगी (सादगी) और रवांगी (सुसंगत ओउ) और दर्शकों से उनका जुड़ाव बेजोड़ है।'' हाथ में हारमोनियम और ढोलक के साथ एक तुम्बी और अलघोजा, चिमटा और उटे के साथ, वह अपने लाइव शो में एक बुनियादी ध्वनि प्रणाली के साथ जादू पैदा करते थे, और उनके एल्बम ट्रक ड्राइवर को उनकी लय और गीत की ताजगी के साथ बांधे रखते थे। .

लोक कलाकारों के कई गीत अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखने वाली महिला की सशक्त छवि प्रस्तुत करते हैं। वह अपने प्रेमी को नपुंसक कहकर ताना मारती है यदि वह उसके साथ जुड़ने के लिए शारीरिक बाधाओं को पार करने में असमर्थ है।

पुराने समय के लोगों का कहना है कि बाधाओं को तोड़ते हुए चमकीला के गीतों ने एक अच्छी महिला की छवि बनाई, मुमताज जैसी कोई महिला जो उस समय बहुत मांग में थी जब चमकीला अपने कौशल को निखार रही थी।

उनके गीत एक मजबूत महिला को उजागर करते हैं जो न केवल घरेलू काम करती है बल्कि खेती में भी योगदान देती है। उनके संगीत समारोहों में कसाई जैसा माहौल था। फिर भी उनके द्विअर्थी गीतों ने पितृसत्तात्मक बंधनों को तोड़ दिया। वे टेप रिकॉर्डर के माध्यम से रसोई और लिविंग रूम तक पहुंचे और महिलाओं के बीच एक वफादार प्रशंसक आधार पाया जो उन शरारती लोक गीतों के लिए एक नया मुहावरा ढूंढना चाहते थे जिन्हें वे शादियों और प्रसव समारोहों में गाते हुए बड़े हुए थे।

यह उम्मीद करते हुए कि एलएम की चर्चा पंजाब और लोक वाद्ययंत्रों की कहानियों में रुचि बढ़ाती है, प्रोफेसर पाल कहते हैं कि मध्ययुगीन काल से पंजाबी साहित्य में अवैध संबंध एक आम विषय रहा है और चमकिला ने ही इसे खुले में लाया है। यह सीमावर्ती राज्य की सामाजिक अंतर्धाराओं को प्रतिबिंबित करता है जहां किसान, सैनिक और ड्राइवर सदियों से प्रमुख व्यवसाय रहे हैं। जब पुरुष महीनों के लिए बाहर रहते हैं, तो यह दोनों लिंगों को ऐसे बंधन बनाने के अवसर और परिस्थितियाँ प्रदान करता है जिन्हें निषिद्ध माना जाता है।

"कई बार इसका कारण अवैध संबंध होता है इसे वास्तविक रिश्ता माना जाता है क्योंकि आप अपनी गहरी भावनाओं को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करते हैं जिसके साथ आप वास्तव में जुड़े हुए हैं। महाकाव्य सोहनी महिवाल कहानी में, सोहनी की शादी एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिससे वह घृणा करती है और महिवाल से मिलने के लिए नदी में तैरती है, जिसे अपने प्यार से मिलने के लिए भेष बदलना पड़ता है।

ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता गुरदयाल सिंह की रचनाओं में नाजायज संबंधों और जगह; यह शिव कुमार बटालवी की कविता में भी है।"

चमकीला की कल्पना स्तरित या पॉलिश नहीं है। यह वहां है, जिसने उन्हें ग्रामीण लोगों से जोड़ा। उन्हें उनके गीतों में अपनी प्रतिक्रिया मिली। उनका प्रतीकवाद रहस्यमय रूपक में छिपा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह अप्रासंगिक है। जैसा कि प्रो.

पाल कहते हैं, चमकीला की कविता शास्त्रीय दृष्टि से भले ही प्रगतिशील न हो लेकिन वह "लच्छर" (आधार) भी नहीं है। दुर्भाग्य से, वर्तमान पीढ़ी अपनी चमक को दो बक्सों में से एक में समेटने की कोशिश कर रही है।

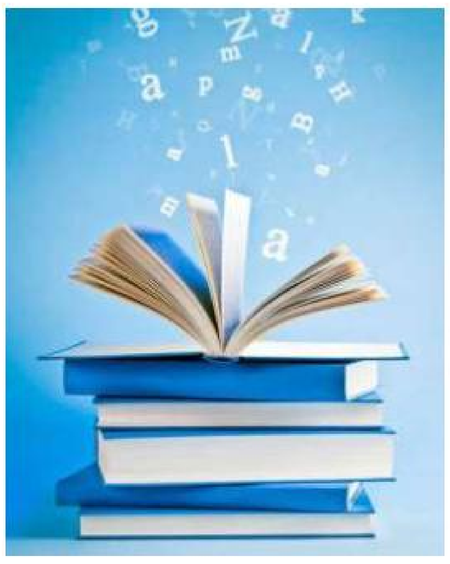

पुरालेखों से

पता है आपकी अंग्रेज़ी

के. सुब्रमण्यन

'काउंटरमैंड' का अर्थ है 'रद्द करना (पहले से दिया गया आदेश या आदेश), विशेष रूप से एक नया और विपरीत आदेश देकर।' यह एक औपचारिक शब्द है. यह 'काउंटर' और 'मंडारे' का संयोजन है, जिसका अर्थ है 'ऑर्डर करना।' 'जनादेश' उसी मूल धातु 'मंदारे' से है। यह भी एक औपचारिक शब्द है.

एक अधिदेश 'एक सामाजिक आदेश या' है एक प्राधिकारी द्वारा निर्देश।' यह राष्ट्रपति का आदेश है. राज्यपाल से अनुरोध एक जनादेश है। तुम्हें इस पत्र का उत्तर देना होगा; उत्तर अनिवार्य है.

'जनादेश' और 'प्रतिआदेश' का प्रयोग संज्ञा और क्रिया के रूप में किया जा सकता है।

जनरल ने सेना को दुश्मन के खिलाफ मार्च करने का आदेश दिया। बाद में उन्होंने अपना आदेश रद्द कर दिया।

'काउंटरमैंड' कोई नया शब्द नहीं है. इसका प्रयोग 15वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था। यह मूलतः एक सैन्य शब्द था। इसका उपयोग अभी भी सशस्त्र बलों द्वारा किया जाता है।

मुझे उसके लिए एक पिन की परवाह है; मुझे एक पिन की परवाह नहीं है उसके लिए। (एसएन रामास्वामी, मद्रास)।

यह है 'मुझे उसके लिए एक पिन की भी परवाह नहीं है।' इसका मतलब है कि मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं है. 'मैं उसके लिए दो पैसों की भी परवाह नहीं करता,' 'मैं उसके लिए रत्ती भर भी परवाह नहीं करता,' 'मैं उसके लिए दो पैसों की भी परवाह नहीं करता' का मतलब भी यही है।

हीरक जयंती, 60वाँ वर्ष घटना या 75वाँ वर्ष (जय सिंह जैन, मद्रास)।

एक समय था जब इसका उपयोग केवल 60वीं वर्षगांठ के संदर्भ में किया जाता था। अब इसका प्रयोग 75वीं वर्षगांठ के सन्दर्भ में भी किया जाता है। केवल कुछ शब्दकोशों में ही दर्ज किया गया है कि यह 71वीं वर्षगांठ का भी उल्लेख कर सकता है। शादी की वर्षगाँठों के नाम हैं: पहला: कॉटन वेडिंग; दूसरा: पेपर वेडिंग; तीसरा: चमड़े की शादी; चौथा: फूल या फल की शादी; पांचवां: लकड़ी की शादी; छठा: लौह या मिश्री विवाह; सातवाँ: ऊनी शादी; आठवां: कांस्य या विद्युत उपकरण विवाह; नौवां: तांबे या मिट्टी के बर्तनों से बनी शादी; दसवां: टिन वेडिंग; ग्यारहवाँ: स्टील वेडिंग; बारहवीं: रेशम और बढ़िया लिनन की शादी; तेरहवीं: फीता शादी; चौदहवाँ: आइवरी वेडिंग; पंद्रहवीं: क्रिस्टल वेडिंग; बीसवीं: चीन शादी; बीसवीं: चांदी की शादी; तीसवाँ: पर्ल वेडिंग; पैंतीसवाँ: मूंगा विवाह; चालीसवां: रूबी वेडिंग; चालीसवाँ: नीलमणि विवाह; पचासवाँ: गोल्डन वेडिंग; पैंतालीसवाँ: पन्ना विवाह; साठवाँ: डायमंड वेडिंग; सत्तरवाँ: डायमंड वेडिंग। नाम इस अवसर के लिए उपयुक्त उपहारों के प्रकार का संकेत देते हैं!

हिस्टेरॉन प्रोटेरॉन (एसके शुक्ला, मेरठ)।

'हिस्टेरॉन प्रोटेरॉन' वाणी का एक गुरु है जिसमें जो शब्द सबसे अंत में आना चाहिए उसे पहले रखा जाता है। यह कुछ ऐसा है जो प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध है। उसने विजय प्राप्त की! उसने देखा! उसने आ! यह ग्रीक 'हिस्टेरॉन प्रोटेरॉन' से है, जिसका अर्थ है 'बाद वाला (पहले के स्थान पर रखा गया)।

मैं मर रहा हूँ! मैं बेहोश हो गया! 1 गिरावट!)

दुःख का पर्यायवाची (एसके बरुआ, डिब्रूगढ़)।

चिंतित, शोकाकुल, क्षमा करें, व्यथित, दुःखी, अप्रसन्न, दुःखी, निःसंतान, शोकग्रस्त, अभागा, दुःखद।

10 दिसंबर, 1991 को द हिंदू में प्रकाशित

Word of the day

Grisly:
shockingly repellent; inspiring horror

Synonyms: awful, ghastly, hideous

Usage: *The town was shaken by a series of grisly crimes.*

Pronunciation: bit.ly/grislypro

International Phonetic Alphabet: /grízlɪj/

पाठ और संदर्भ के लिए प्रतिक्रिया और सुझाव के लिए, कृपया 'पाठ और संदर्भ' विषय के साथ labels@thehindu.co.in पर लिखें।

दैनिक प्रश्नोत्तरी

कृपया अपने उत्तर dailyquiz@thehindu.co.in पर भेजें

रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना है और दुनिया भर के मुसलमान इसे उपवास के महीने के रूप में मनाते हैं। यहां रमज़ान पर एक प्रश्नोत्तरी है

वेंकटराघवन श्रीनिवासन

X

प्रश्न 1 रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान रोज़ा तोड़ने के भोजन को इफ्तार कहा जाता है, रोज़ा शुरू होने से पहले के भोजन को क्या कहा जाता है?

एक्स

प्रश्न 2 इस्लामी परंपरा के अनुसार, रमज़ान के किस दिन पैगंबर मुहम्मद को कुरान का पहला रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ था?

X

प्रश्न 3 पैगंबर मुहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था?

X

प्रश्न 4 इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है? रमज़ान?

X

प्रश्न 5 दिन की पहली प्रार्थना क्या कहलाती है?

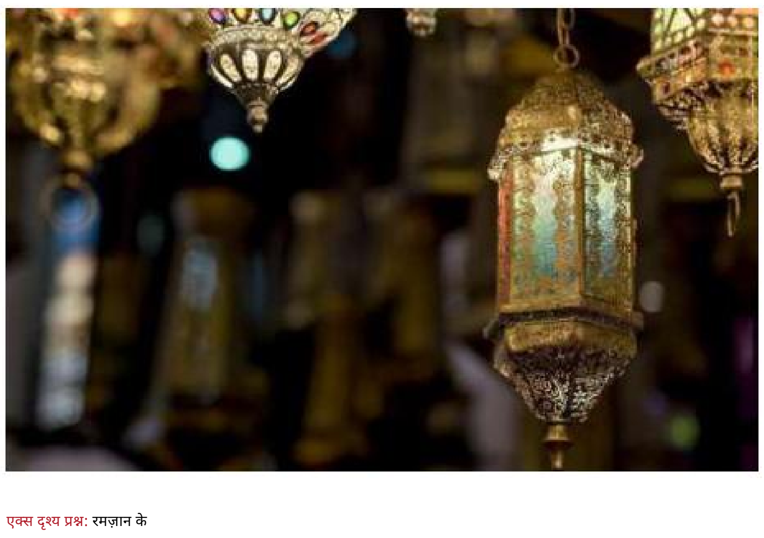

एक्स दृश्य प्रश्न: रमज़ान के दौरान उपयोग की जाने वाली पारंपरिक लालटेन को किस नाम से बुलाया जाता है? ये चमकीले, रंग-बिरंगे लटकते लैंप हैं जिनका उपयोग रमज़ान के दौरान घरों और सड़कों को सजाने के लिए किया जाता है। गेटी इमेजेज

पिछले दिन के दैनिक प्रश्नोत्तरी के प्रश्न और उत्तर: 1. यह तमिल राजनीतिक व्यंग्य एक ग्राम पंचायत चुनाव की पृष्ठभूमि पर आधारित है जिसमें स्थानीय नाई का वोट चुनाव के विजेता का निर्धारण करेगा, योगी बाबू अभिनीत और मैडोना अश्विन द्वारा निर्देशित फिल्म एक ताजगी भरी फिल्म बनकर आई। फिल्म का नाम बताएं. उत्तर: मंडेला 2. वर्ष 2017 में रिलीज़ हुआ यह सम्मोहक भारतीय ब्लैक कॉमेडी ड्रामा, मध्य भारत के संघर्षग्रस्त जंगल में चुनाव ड्यूटी पर तैनात एक सरकारी क्लर्क के बारे में है। अमृत मसूर द्वारा निर्देशित और राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी अभिनीत इस फिल्म का नाम बताइए। उत्तर: न्यूटन 3.

1975 की फिल्म आंधी के निर्देशक कौन थे । यह भी था

चुनावी राजनीति में महिलाओं के बारे में पहली फिल्मों में से एक। उत्तर: गुलज़ार

4. इस लेखक का उपन्यास 2001 की कन्नड़ फिल्म मथादाना है, जो एक अनोखी राजनीतिक ड्रामा फिल्म है। उत्तर: एसएलभैरप्पा 5. वर्ष 1990 में रिलीज़ हुई यह मलयालम फिल्म थॉमस वैद्यन, गौरी अम्मा और थॉमस वैद्यन की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित थी। फिल्म का नाम बताएं. उत्तर: लाल सलाम दृश्य: फिल्म को पहचानें। उत्तर: इरुवर अर्ली बर्ड्स: राजमोहन वी | ज्योत प्रकाश गुलाटी | रोशिश तिरुमाला | लक्ष्मी हरिकुमार | साहेनी जॉर्ज

thehindubusinessline.
शुक्रवार - 12 अप्रैल, 2024

घोर समर्पण

आईआरडीए सरेंडर शुल्क मानदंड पॉलिसी खरीदारों के लिए अनुचित है

मैं अक्सर भारत का बीमा नियामक नहीं होता [illegible] उपभोक्ताओं की ओर से हस्तक्षेप करता है। इसलिए, एक दौर दिसंबर 2023 में खुशी तब बढ़ गई जब बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने पॉलिसीधारकों द्वारा समय से पहले ऑप्ट आउट करने पर बीमाकर्ताओं द्वारा लगाए जाने वाले भारी सरेंडर शुल्क पर लगाम लगाने के लिए एक चर्चा पत्र जारी किया।

प्रीमियम का 30 से 90 प्रतिशत सरेंडर दंड के रूप में लेने की उद्योग प्रथा के विपरीत, आईआरडीए ने सरेंडर शुल्क के एक सीमा स्तर का सुझाव दिया, जिसके परे बीमाकर्ताओं को ग्राहक को सभी प्रीमियम वापस करना होगा।

लेकिन बीमा लॉबी द्वारा एक धक्का ऐसा प्रतीत होता है कि इसने आईआरडीए को संशोधित नियम जारी करने के लिए प्रेरित किया है। नए मानदंड बीमाकर्ताओं को एक वर्ष में ग्राहक के बाहर जाने पर 100 प्रतिशत, दो वर्षों में 70 प्रतिशत और तीन वर्षों में 65 प्रतिशत प्रीमियम वसूलने की अनुमति देंगे।

चौथे और सातवें वर्ष के बीच छोड़ने पर खरीदार को भुगतान किए गए प्रीमियम का 50 प्रतिशत जब्त करना होगा। यह देखते हुए कि बीमाकर्ता अपने फंड को बाजार के साधनों में निवेश करते हैं जो समय से पहले बाहर निकलने की अनुमति देते हैं, 50-100 प्रतिशत का सरेंडर शुल्क अनावश्यक लगता है। इसके अलावा, अत्यधिक सरेंडर शुल्क के पक्ष में बीमा उद्योग द्वारा दिए गए किसी भी तर्क में ज्यादा दम नहीं है। मुख्य बात यह थी कि समर्पण शुल्क कम करने से लाभप्रदता पर बुरा असर पड़ेगा। यह भारतीय बीमा कंपनियों के व्यवसाय मॉडल पर एक दुखद टिप्पणी है क्योंकि दुनिया भर में, जीवन बीमा कंपनियां प्रतिकूल घटनाओं के खिलाफ ग्राहकों को सुरक्षा बेचने और इन जोखिमों की अंडरराइटिंग और सही मूल्य निर्धारण करके अपना मुनाफा प्राप्त करती हैं। भारत में, जीवन बीमा उद्योग और इसके बड़े एजेंट बल बीमा-सह-निवेश उत्पादों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं जो न तो पर्याप्त जीवन कवर प्रदान करते हैं और न ही उचित रिटर्न देते हैं।

उपभोक्ता।

इंडस्ट्री ने भारी जुर्माने का दावा किया बीमा खरीददारों को उनके दीर्घकालिक अनुबंधों से मुकरने से हतोत्साहित करने के लिए समर्पण पर निर्णय आवश्यक हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत में पारंपरिक बीमा योजनाओं के अधिकांश खरीदार उत्पाद की अवधि या उसके लाभों की सही तस्वीर प्राप्त किए बिना ही साइन अप करते हैं।

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) इस आधार पर (गलत) बेचे जाते हैं कि खरीदार को केवल पांच साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
बीमा उत्पादों के लिए विपणन साहित्य शब्दजाल से भरा हुआ है और यह सक्रिय रूप से गलत बिक्री को बढ़ावा देता है।

अकेले वित्त वर्ष 2013 में आईआरडीए के शिकायत पोर्टल पर गलत बिक्री पर एक लाख से अधिक उपभोक्ता शिकायतें प्राप्त हुईं। इससे ड्रॉपआउट दर बढ़ जाती है, भारत में 50 प्रतिशत से अधिक बीमा खरीदार पांचवें वर्ष तक प्रीमियम भुगतान रोक देते हैं। उच्च समर्पण शुल्क बीमाकर्ताओं और उनके मध्यस्थों के लिए ड्रॉपआउट को प्रोत्साहित करने के लिए विकृत प्रोत्साहन पैदा करते हैं।

बीमाकर्ताओं को भारी ग्राहक दंड भुगतना पड़ता है जो उनकी लाभप्रदता में सहायता करता है, जबकि एजेंटों को फ्रंट-लोडेड कमीशन से लाभ होता है जो निरंतर मंथन को प्रोत्साहित करता है। इस तरह के विकृत प्रोत्साहनों के साथ, समर्पण शुल्क को सुव्यवस्थित करने की गेंद वास्तव में आईआरडीए के पाले में थी। अंततः, उनके उत्पाद ग्राहकों को बेहतर मूल्य प्रस्ताव प्रदान किए बिना भारत की बीमा पैठ में सुधार नहीं कर सकते। आईआरडीए को सरेंडर शुल्क के मुद्दे पर दोबारा विचार करना चाहिए।

अभिषेक झा
अंजनी कुमार

एफटीए और कृषि निर्यात: एक मिश्रित बैग

व्यापार के मामले. टारी में कटौती के साथ-साथ, गैर-टारी उपायों को सुव्यवस्थित करना भी भारत के कृषि-निर्यात वृद्धि में भूमिका निभाएगा।

एन विकसित देशों के साथ व्यापार सौदों पर सहमति बनाना और उन्हें संपन्न करना कई जटिल धाराओं, शर्तों और शर्तों के कारण चुनौतीपूर्ण है, जिन्हें पूरा करने और सहमति देने की आवश्यकता है। इन समझौतों को अंतिम रूप देने में सरकार की कोशिशें सराहनीय हैं।

हमारे निर्यात टोकरी गंतव्यों में विविधता लाने, उच्च मूल्य और मूल्य वर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को वैश्विक के साथ एकीकृत करके दोगुना करने का प्रयास करने के उद्देश्य से कृषि निर्यात नीति को लागू किए हुए पांच साल से अधिक समय हो गया है। मूल्य श्रृंखला। निश्चित रूप से, विशेष रूप से विकसित देशों के साथ व्यापार समझौतों का मार्ग नीति निर्माताओं के इरादों का समर्थन करेगा।

वित्त वर्ष 2023 के लिए ईएफटीए राज्यों को भारत का कुल व्यापारिक निर्यात 1.9 बिलियन डॉलर था, जिसमें से 70 प्रतिशत स्विट्जरलैंड को भेजा जाता है, इसके बाद 25 प्रतिशत नॉर्वे को भेजा जाता है। दशक के दौरान, महामारी के चरम वर्षों सहित विकास दर प्रति वर्ष लगभग 4 प्रतिशत के करीब थी।

भारत द्वारा ईएफटीए को निर्यात किए जाने वाले शीर्ष उत्पादों में कार्बनिक रसायन, मूल्य वर्धित रत्न और आभूषण, बिजली से संबंधित उपकरण, सूखी फलीदार सब्जियों का आटा और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं।

वित्त वर्ष 23 में भारत का कृषि निर्यात रहा $0.13 बिलियन, जो ईएफटीए को भारत के कुल व्यापारिक निर्यात का केवल 7 प्रतिशत से भी कम है। ईएफटीए का दुनिया भर से कृषि उत्पादों का आयात भी काफी बड़ा है।

उजागर करने के लिए, उनका कृषि आयात लगभग $29 बिलियन है, जो पिछले तीन वर्षों में 10 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ रहा है। ईएफटीए के शीर्ष कृषि आयात में उत्साही पेय पदार्थ (मुख्य रूप से वाइन), पशु आहार के लिए बचा हुआ भोजन, कोइ, ताजे फल और सब्जियां, खाद्य तेल और वसा, और वेफर्स, स्नैक्स और बिस्कुट शामिल हैं। भारतीय कृषि उत्पादों में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं है, केवल सूखे फलीदार सब्जियों के आटे की दृश्यता मामूली है।

व्यापार समझौते के अस्तित्व में आने के साथ, क्या ईएफटीए द्वारा टैरिफ कटौती, यदि कोई हो, आने वाले समय में भारतीय कृषि निर्यातकों के लिए आशा प्रदान करेगी?

ईएफटीए के गैर-टैरिफ उपाय

भारत के कृषि निर्यात में बाधा आ सकती है। लेकिन एफटीए के बाद संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया को कृषि निर्यात में बढ़ोतरी हुई है

चौखटा? दिलचस्प बात यह है कि स्विट्जरलैंड सभी देशों से आने वाले रसायनों, उपभोक्ता वस्तुओं, वाहनों, कपड़ों सहित सभी औद्योगिक वस्तुओं के लिए टैरिफ-मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। यह नीति 1 जनवरी, 2024 से लागू हो गई और वैसे भी भारत-ईएफटीए व्यापार समझौते का उपयोग महत्वहीन हो जाएगा।

कृषि वस्तुओं (एजी) के लिए, ईएफटीए देशों की टारी प्रतिबद्धताएं उतनी उदार नहीं हैं। इसे हम तीन श्रेणियां बनाकर बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।

तीन श्रेणियाँ एक, जिसके लिए व्यापार समझौते में कोई प्रतिबद्धता नहीं की गई है और बाहर रखा गया है (कृषि अध्यायों के भीतर लगभग 40 प्रतिशत टारी लाइनें हैं)।

दूसरा, ये उच्च टारी दर प्रतिबद्धताओं (डेयरी, मांस और सब्जी अध्यायों से लेकर कुछ की सूची) के साथ कृषि वस्तुओं का एक समूह हैं।

तीसरा, या तो शून्य या कम आयात के साथ तारिस - ये वे उत्पाद हैं जिनके लिए ईएफटीए में घरेलू उत्पादन क्षमता मजबूत नहीं है और मांग है आयात से पूरा किया जाना है। उदाहरण के लिए माल्ट से बनी बीयर, मीठी वाइन, विविध खाद्य तैयारी।

पहली और दूसरी श्रेणी के लिए, यह एफटीए भारतीय कृषि उत्पादों को उनके बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में, यदि कोई हो, मामूली राहत प्रदान करता है। तीसरी श्रेणी के लिए, जहां कुछ राहत है, प्रतिस्पर्धात्मकता वाले भारतीय कृषि उत्पादों और ईएफटीए द्वारा आयातित कृषि उत्पादों के बीच पूरकता सीमित है। इस सेट में, कोइ, अनाज, मीठे बिस्कुट, अवशिष्ट/अपशिष्ट अनाज जैसे उत्पाद शामिल हैं।

सर्वांगसमता व्यापक नहीं है, इस प्रकार भारतीय कृषि निर्यातकों के लिए अवसर का लाभ उठाने का दायरा सीमित हो गया है। पिछले वर्षों में आयात तारिस की कहानी भी ऐसी ही थी। क्षेत्रीय ब्लॉक द्वारा लागू सरल औसत सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) दर 2022 में 5.6 प्रतिशत थी। जबकि एमएफएन देशों से गैर-कृषि वस्तुओं को केवल 1.3 प्रतिशत की साधारण औसत टैरिफ दर का सामना करना पड़ता था, कृषि वस्तुओं पर औसतन 32.4 प्रतिशत शुल्क लागू होते थे, और ये डेयरी उत्पादों के लिए यह बढ़कर 137.7 प्रतिशत हो गई।

इसके अलावा, उत्पाद की प्रतिस्पर्धात्मकता का निर्धारण केवल आयात टारी दरों पर निर्भर नहीं है।

अनेक गैर-तारी उपाय

व्यापार में स्वच्छता और पादप स्वच्छता और तकनीकी बाधाएं भी निर्यातकों की क्षमताओं और क्षमताओं को प्रभावित करती हैं। इन उपायों की आवश्यकताओं को पूरा करना, जो अक्सर जटिल और चुनौतीपूर्ण होते हैं, बाजार भागीदारी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।

जबकि व्यापार समझौतों में आम तौर पर गैर-टारी उपायों के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से व्यापार सुविधा को संबोधित करने वाले प्रावधान शामिल होते हैं, यह अनिश्चित बना हुआ है कि क्या ये उपाय भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के निर्यातकों के लिए फायदेमंद रहे हैं।

एक तुलना

अब, आइए भारत-ऑस्ट्रेलिया और भारत-यूएई के लिए व्यापार समझौते के बाद के कुछ आंकड़ों की तुलना करें। दोनों एफटीए पर 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। उत्साहजनक रूप से, दोनों व्यापार समझौतों में, समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले की अवधि की तुलना में भारतीय कृषि निर्यात में वृद्धि हुई है। भारत-ऑस्ट्रेलिया के मामले में, जहां एफटीए दिसंबर 2022 में लागू हुआ, हमारे कृषि निर्यात में पिछली अवधि की तुलना में अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

यह वृद्धि समग्र से अधिक है उक्त अवधि के दौरान भारत के व्यापारिक निर्यात में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
दिलचस्प बात यह है कि इसी अवधि के दौरान ऑस्ट्रेलिया से हमारा कृषि आयात लगभग 50 प्रतिशत बढ़ गया। इसमें भेड़ के मांस, समुद्री भोजन, ब्रॉड बीन्स, साइट्रस और बादाम जैसे उत्पादों में भारी वृद्धि शामिल है।

भारत-यूएई के लिए भी, 2022-23 में एफटीए पर हस्ताक्षर करने के बाद पहले वर्ष के दौरान भारत के कृषि और समग्र निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब, सवाल उठता है: क्या कृषि निर्यात में यह वृद्धि केवल टैरिफ में कमी के कारण है, या क्या यह गैर-टैरी उपायों की सुविधा से सकारात्मक प्रभाव को भी दर्शाता है?

यदि कृषि निर्यात में वृद्धि केवल एफटीए के परिणामस्वरूप कम टारी दरों के कारण है, तो यह वृद्धि टिकाऊ नहीं हो सकती है और लाभ समाप्त होने के बाद कम हो सकती है। हालाँकि, यदि निर्यात को टैरिफ में कमी और गैर-टैरी उपायों को सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने के लिए बढ़ी हुई तकनीकी क्षमता द्वारा समर्थित किया जाता है, तो विकास पथ टिकाऊ हो सकता है।

सरकार को यह मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या कृषि निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए गैर-टारी उपायों को सुव्यवस्थित करना जमीन पर प्रभावी ढंग से हो रहा है या क्या यह केवल एफटीए के पाठ में एक प्रावधान बनकर रह गया है।

कुमार इंटरनेशनल फूड में सीनियर रिसर्च फेलो हैं
नीति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; और झा जेएनयू, नई दिल्ली में अर्थशास्त्र क्षेत्र में एक शोध विद्वान हैं।

आरबीआई के कैलिब्रेटेड ठहराव के बचाव में

नीतिगत दरों पर रोक एक व्यावहारिक विकल्प है। मानसून मुद्रास्फीति की गतिशीलता तय करेगा

अमरेंदु नंदी
संकल्प भट्टाचार्य

टी वह भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय ब्याज दरों पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए, लगातार सातवीं बार रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखते हुए, इसके नीतिगत रुख पर बहस छिड़ गई है।

केंद्रीय बैंक की नपी-तुली सावधानी की स्थिति घरेलू और बाहरी दोनों मोर्चों पर भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद असंख्य चुनौतियों के प्रति एक व्यावहारिक प्रतिक्रिया है।

सबसे पहले, आइए मुद्रास्फीति पर विचार करें गतिकी। फरवरी 2024 में हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 5.09 प्रतिशत तक कम होने के बावजूद, प्रक्षेपवक्र अनिश्चित बना हुआ है।

2024-25 के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत अनुमानित है, जो केंद्रीय बैंक के 4 प्रतिशत मध्यम अवधि के लक्ष्य से अधिक है।

खाद्य मुद्रास्फीति, जिसका सीपीआई बास्केट में लगभग 40 प्रतिशत का भारित योगदान है, 8.7 प्रतिशत पर बनी हुई है, जो अनाज, सब्जियों और मांस और मछली जैसे प्रोटीन स्रोतों की बढ़ती कीमतों से प्रेरित है, जिससे व्यापक जोखिम उत्पन्न हो रहा है। मूल्य दबाव और मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं की डी-एंकरिंग।

दूसरे, जो बात नीतिगत कैनवास को जटिल बनाती है वह खाद्य मुद्रास्फीति के लिए अनिश्चित दृष्टिकोण है, जो हाल ही में हेडलाइन मुद्रास्फीति का प्राथमिक चालक रहा है।

महीने (ग्राफ़ देखें)। आरबीआई ने मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र पर सही ढंग से प्रकाश डाला है

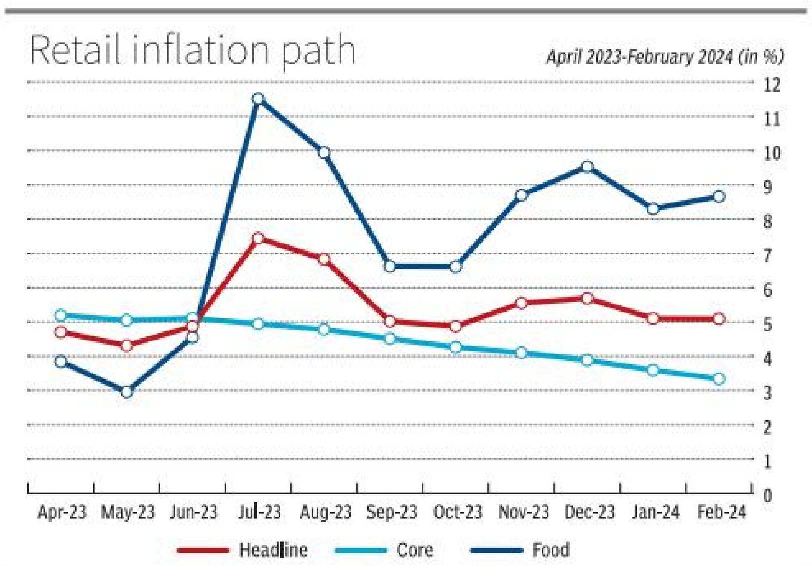

इस वर्ष का मौसम काफी हद तक मानसून के मौसम पर निर्भर करेगा। सामान्य या सामान्य से अधिक मानसून वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में मौद्रिक सहजता की गुंजाइश खोल सकता है।

इसके अलावा, हालांकि मुख्य मुद्रास्फीति, जिसमें अस्थिर खाद्य और ईंधन घटकों को शामिल नहीं किया गया है, फरवरी 2024 में 3.34 प्रतिशत के निचले स्तर पर पहुंच गई, लेकिन पिछले 11 महीनों में यह औसतन 4.43 प्रतिशत रही है।

यह मूल चिपचिपाहट अंतर्निहित मांग-पक्ष दबावों को दर्शाती है जो अनियंत्रित छोड़ दिए जाने पर अवस्फीति को बाधित कर सकती है।
2024-25 के लिए भारत के 7 प्रतिशत के मजबूत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के पूर्वानुमान को देखते हुए,

सकारात्मक वास्तविक ब्याज दरों को बनाए रखना मांग-प्रेरित मुद्रास्फीतिकारी ताकतों को नियंत्रित करने का एक विवेकपूर्ण उपाय है।

तीसरा, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति सामान्यीकरण प्रक्रिया का प्रक्षेप पथ अभी भी विकसित हो रहा है। जैसा कि विभिन्न विश्लेषकों ने उल्लेख किया है, आरबीआई का नीतिगत रुख पिछले दो वर्षों में फेड की कार्रवाइयों से कुछ हद तक जुड़ा हुआ है, जो वैश्विक वित्तीय बाजारों की परस्पर प्रकृति और भारत की बाहरी क्षेत्र की कमजोरियों को दर्शाता है।

भारत की मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र भारी है वैश्विक कमोडिटी कीमतों और अमेरिकी डॉलर की मजबूती से प्रभावित। सावधानी बरतते हुए और फेड की प्रत्याशित दर में कटौती को आगे न बढ़ाकर, आरबीआई संभावित पूंजी बहिर्वाह और मुद्रा अस्थिरता के जोखिमों को कम कर रहा है। कच्चे तेल जैसी वस्तुओं पर भारत की आयात निर्भरता को देखते हुए यह सतर्क दृष्टिकोण प्रासंगिक है, जहां हाल के भू-राजनीतिक तनावों ने कीमतों में वृद्धि को बढ़ावा दिया है, जिससे मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा हो गया है।

चौथा, कुछ विश्लेषकों ने तर्क दिया है कि आरबीआई का रुख "वक्र के पीछे गिरने" का जोखिम है, खासकर अगर फेड जैसे वैश्विक केंद्रीय बैंक अनुमान से पहले दर में कटौती करने पर जोर देते हैं। हालाँकि, RBI का हालिया ट्रैक रिकॉर्ड बदलती आर्थिक परिस्थितियों के जवाब में अपने नीतिगत रुख को तेजी से समायोजित करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

दरअसल, इसका नवीनतम रुख "वापसी" का है आवास की व्यवस्था'' समय खरीदने और लचीलापन बनाए रखने का एक प्रयास प्रतीत होता है। अब तक, मार्च में मजबूत अमेरिकी नौकरियों के आंकड़ों ने फेड द्वारा तत्काल दर में कटौती की उम्मीदों को कम कर दिया है।

अंततः, मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि इस गर्मी में पूरे भारत में तापमान औसत से ऊपर रहेगा। ये कारक कर सकते हैं आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं के माध्यम से मुद्रास्फीति को बढ़ाएँ, व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ाएँ।

आरबीआई का यथास्थिति रुख संभावित आंतरिक और बाहरी झटकों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच साबित होगा।

लेखक आईआईएम, रांची में अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। विचार व्यक्तिगत हैं

व्यूरूम से .

पालतू पशु मालिक - जिम्मेदारी से कार्य करें

पीटी ज्योति दत्ता

ए हाल ही में कर्नाटक उच्च पर कोर्ट का निर्देश "क्रूर और खतरनाक" कुत्तों के प्रजनन और आयात ने सही ढंग से "जिम्मेदार पालतू स्वामित्व" की ओर इशारा किया है - कुछ ऐसा जो कुत्तों पर उच्च-स्तरीय चर्चाओं में खो जाता है।

चाहे पालतू जानवर हों या सामुदायिक कुत्ते, यह हमेशा जिम्मेदार व्यवहार तक सीमित हो जाता है - मालिक से, जानवरों को पंजीकृत करने और उनकी नसबंदी करने के प्रभारी सरकारी विभाग और लोगों के बड़े समुदाय से।

HC ने बैन की दोबारा जांच करने को कहा है

मीडिया-रिपोर्टों के अनुसार, कुत्तों के आयात और प्रजनन को खतरनाक माना गया है, इसके अलावा पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) जैसे हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श की आवश्यकता है। पेटा इंडिया ने पिट-बुल-प्रकार के कुत्तों (अवैध कुत्ते-झगड़ों में इस्तेमाल और दुर्व्यवहार) की रक्षा के लिए और मनुष्यों को हमलों से बचाने के लिए केंद्र के परिपत्र को मजबूत करने का आह्वान किया है।

यहां जरूरत ज्ञान और सहानुभूति के साथ आगे बढ़ने की है।

जानवरों को पाला गया है और उनके व्यवहार को लड़ाई, दौड़ या सिर्फ सहारा बनने के लिए हेरफेर किया गया है। जानवरों के साथ काम करने वाले लोग नस्ल के कुत्तों (बिल्लियों/तोते आदि) के ऐसे कई उदाहरणों का वर्णन करते हैं जिन्हें अत्यधिक आक्रामक होने, पालने में महंगा होने या अधिक बच्चों को जन्म देने में बहुत बीमार होने के कारण छोड़ दिया गया था। जानवर वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे वे करते हैं, क्योंकि वे अक्सर अस्वास्थ्यकर/बेईमान वातावरण में पाले जाते हैं - जो हमें जिम्मेदारी की ओर वापस लाते हैं। अधिकारियों को स्वामित्व, जन्म, मृत्यु, प्रजनकों आदि को मैप करने के लिए एक रजिस्ट्री की आवश्यकता होती है - ठीक इंसानों की तरह। "आक्रामक" पालतू जानवर रखने वाला व्यक्ति उसकी भलाई के लिए जवाबदेह है और यदि उसे छोड़ दिया जाता है तो उसकी पहचान की जानी चाहिए (और काली सूची में डाला जाना चाहिए)। जो व्यक्ति किसी कारण से पालतू जानवर रखने में असमर्थ है, उसे जिम्मेदारीपूर्वक उसे गोद लेने में सक्षम होना चाहिए।

व्यवस्थित पशु जन्म नियंत्रण पहल सुनिश्चित करने और जिम्मेदार जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए नगर पालिकाओं और निवासियों को पशु संगठनों के साथ काम करने की आवश्यकता है - चाहे वह पालतू जानवरों के साथ हो या सामुदायिक जानवरों के साथ।

संपादक को पत्र अपने पत्र ईमेल द्वारा bleditor@thehindu.co.in पर या डाक द्वारा 'संपादक को पत्र', द हिंदू बिजनेस लाइन, कस्तूरी बिल्डिंग, 859-860, अन्ना सलाई, चेन्नई 600002 पर भेजें।

स्मार्ट पोषण केंद्र का तात्पर्य 'मतदान के बाद, राशन की दुकानों को 'स्मार्ट पोषण केंद्र' का रूप देने के लिए' (11 अप्रैल) से है। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बाजरा और बाजरा आधारित वस्तुओं को वितरित करने का केंद्र का प्रस्ताव

के लिए संतुलित आहार सुनिश्चित करेगा उपभोक्ता. 5.38 लाख एफपीएस लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने के लिए इसके संचालन में तकनीकी-उन्मुख उन्नयन की आवश्यकता है।
लक्षित वितरण के लिए लाभार्थियों के आधार को निरंतर आधार पर लिंक करना महत्वपूर्ण है।

जबकि लाभार्थियों की बायोमेट्रिक जांच से संबंधित मुद्दे वस्तुओं का वितरण असामान्य नहीं है और इसलिए कठिनाइयों से बचने के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

बैंकों से रियायती दरों पर कार्यशील पूंजी सुविधाओं की व्यवस्था से एफपीएस को बाजरा और बाजरा-आधारित वस्तुओं का व्यापार करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

किसान उत्पादक संगठनों द्वारा बाजरा और संबंधित वस्तुओं की सीधी आपूर्ति लागत प्रभावी होगी और नियमित आपूर्ति की सुविधा भी प्रदान करेगी।

वीएसके पिल्लई
Changanacherry

माइक्रोप्लास्टिक खतरा

लेख 'द.' के सन्दर्भ में

माइक्रोप्लास्टिक का अदृश्य ख़तरा' (11 अप्रैल), प्लास्टिक, जिसने सबसे सुविधाजनक पैकेजिंग सामग्री की आड़ में मानव जीवन पर आक्रमण किया है, कहर बरपा रहा है और चुपचाप मानव स्वास्थ्य को अपूरणीय रूप से नष्ट कर रहा है।

मानव स्वास्थ्य गंभीर खतरे में है, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक, एक बार मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद, जठरांत्र पथ के माध्यम से पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन वे रक्त में प्रवेश कर सकते हैं और रह सकते हैं।

धारा।

फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के आने के बाद ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना आसान हो गया है

सबसे आम हो गया और भोजन, जिसमें गरम खाना भी शामिल है, प्लास्टिक के पाउच में पैक और वितरित किया जाता है। और प्लास्टिक पाउच में पैक किया गया गर्म भोजन गर्म प्लास्टिक से निकलने वाले रसायनों से दूषित होता है, जो कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है और हृदय और प्रजनन प्रणाली को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। अब समय आ गया है कि सरकारें और अनुसंधान संस्थान प्लास्टिक का समान रूप से सुविधाजनक और बहुमुखी विकल्प खोजने के लिए अनुसंधान के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करें।

कोसाराजू चंद्रमौली हैदराबाद

जल संकट लेख 'जल संकट: खेती दोषी?' (11 अप्रैल) उपयोगी पढ़ने के लिए बना है।

कर्नाटक जल संकट ने हर समय पानी के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता को प्रदर्शित किया है।
जल संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति की प्रमुख जिम्मेदारी है।

सरकारों को देश भर में पानी की स्थिति का जायजा लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए

वितरण।

एस रामकृष्णसायी
चेन्नई

निर्मला लक्ष्मण द्वारा प्रकाशित और एचटी मीडिया लिमिटेड में एस. रामानुजम द्वारा मुद्रित। प्लॉट नंबर 8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा जिला। गौतमबुद्ध नगर, यूपी 201306, टीएचजी पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई-600002 की ओर से। संपादक: रघुवीर श्रीनिवासन (पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेदार संपादक)।
आईएसएसएन 0971-7528

अमेरिकी फार्मा कंपनियों पर आंच

एक नया कानून स्वास्थ्य मंत्रालय को कीमतों पर बातचीत करने की अनुमति देता है

रीटा मैकग्राथ
एम मुनीर

मैं यह आश्चर्यजनक है कि इंसुलिन जैसे 100 साल पुराने उत्पाद की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, यहां तक कि एक अध्ययन में पाया गया कि जीवन रक्षक दवा प्राप्त करना बड़ी संख्या में लोगों के लिए एक अत्यधिक वित्तीय बोझ था - 14 प्रतिशत उदाहरण के लिए अमेरिकी, और 40 मिलियन से अधिक भारतीय मधुमेह रोगी।

मूल्य निर्धारण। एक कांटेदार मुद्दा

क्यों? आंशिक रूप से, दवा कंपनियों को उपचार पर पेटेंट प्रदान किया जाता है, जो अनिवार्य रूप से एक अस्थायी एकाधिकार है जिससे उन्हें अपने अनुसंधान एवं विकास निवेश की भरपाई करने में मदद मिलती है। वे अस्थायी एकाधिकार बहुत प्यारे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रथाओं के माध्यम से विस्तारित करने के लिए बहुत सारी रणनीतियों को प्रेरित किया गया है जिनकी भारी आलोचना हुई है।

अनुसंधान एवं विकास के लिए भुगतान

निर्माताओं का तर्क है कि उन्हें अनुसंधान एवं विकास के लिए भुगतान करने के लिए उच्च कीमतों की आवश्यकता है जो सबसे पहले चमत्कारिक दवाएं बनाती है। एक फार्मा कंपनी नई दवा के लिए कितना शुल्क ले सकती है, इसके बारे में अनिवार्य रूप से कोई नियम नहीं हैं, जिससे कीमतें चौंकाने वाली हो जाती हैं - गिलियड साइंस अपनी हेपेटाइटिस दवा, सोवाल्डी के पूरे कोर्स के लिए $84,000 का शुल्क लेता है।

हालाँकि यह काफी अधिक है, याद रखें कि दवा ने हेपेटाइटिस-सी को ठीक कर दिया, जिससे अंततः यकृत प्रत्यारोपण या अन्य महंगे उपचारों को रोका जा सका। गिलियड ने तर्क दिया कि इलाज खोजने के लिए किए गए निवेश की भरपाई के लिए उच्च कीमत की आवश्यकता थी, और एक उपचारात्मक दवा उस दवा की तुलना में कम आकर्षक होती है जिसे निरंतर आधार पर लेना पड़ता है। कोई यह तर्क दे सकता है कि कंपनी हेप-सी से पीड़ित बड़ी संख्या में रोगियों को राहत प्रदान करने के बजाय मुनाफे से प्रेरित थी।

अमेरिका में हालात थोड़े अजीब हैं। भारत में एमआरपी की तरह, एक "सूची मूल्य" है। लेकिन, फार्मा कंपनी तब फार्मेसी बेनिफिट मैनेजर्स (पीबीएम) के साथ बड़े पैमाने पर बातचीत करती है, जो बीमाकर्ताओं और भुगतानकर्ताओं की ओर से बातचीत करते हैं। पीबीएम से अपेक्षा की जाती है कि वे बीमाकर्ताओं और योजना प्रायोजकों से प्रशासनिक बोझ हटा दें जो वास्तव में पूरी प्रणाली के लिए भुगतान करते हैं।

हकीकत में पीबीएम बन गए हैं अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली, वे अपना अधिकांश पैसा उन छूटों पर कमाते हैं जिनके लिए वे बातचीत करते हैं। उन्हें खुश करने के लिए, कई निर्माता "सूची" मूल्य बढ़ाते हैं और बड़ी छूट देते हैं, जो उन लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जिन्हें वास्तव में सूची मूल्य का भुगतान करना पड़ता है। यह अधिकांश से बिल्कुल भिन्न प्रणाली है

विकसित देश, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियां बातचीत करती हैं।

और, एक अनोखे अमेरिकी मोड़ में, जब 2003 के कानून के तहत मेडिकेयर में प्रिस्क्रिप्शन दवा के लाभ जोड़े गए, तो कांग्रेस ने विशेष रूप से दो बड़े सार्वजनिक भुगतानकर्ताओं को बातचीत करने से मना कर दिया, इसके बजाय एक प्रकार का "सबसे पसंदीदा ग्राहक" खंड लागू किया। इस खंड ने फार्मा कंपनियों को प्रभावी रूप से बाहर कर दिया जब अन्य खिलाड़ियों ने यह कहकर कड़ी बातचीत करने की कोशिश की कि वे अधिक छूट देने का प्रबंध नहीं कर सकते।

दो सबसे बड़े भुगतानकर्ताओं को! अमेरिका में नया मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम अनिवार्य रूप से कुछ दवाओं पर सबसे पसंदीदा ग्राहक खंड को समाप्त करता है, जिससे स्वास्थ्य मंत्रालय को मेडिकेयर रोगियों के लिए डॉक्टर के पर्चे वाली दवा की कीमतों पर बातचीत करने की अनुमति मिल जाती है।

विशिष्टता अवधि

लेकिन अधिनियम में सन्निहित एक और बदलाव, सरकार को नौ साल (तथाकथित छोटे-अणु वाली दवाओं के लिए जिन्हें आप आम तौर पर गोली के रूप में लेते हैं) और बड़े-अणु वाली दवाओं के लिए 13 साल की विशिष्टता अवधि के बाद दवाओं के लिए मूल्य निर्धारण पर बातचीत करने में मदद करता है (जिसे इंजेक्ट/इन्फ़्यूज़ किया जाना है)।

इसका मतलब यह है कि वह जीवनचक्र जिसके दौरान एक फार्मास्युटिकल कंपनी 'एकाधिकार' का आनंद ले सकती है, को छोटा कर दिया जाएगा।

क्या यह निर्माता बनाएंगे क्या आप उन उत्पादों की तलाश कर रहे हैं जिन पर मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम का कम प्रभाव पड़ता है? फार्मा निर्णय निर्माताओं द्वारा छोटी विशिष्ट "समाप्ति तिथि" वाली योजनाओं और कार्यक्रमों पर जोर दिए जाने की संभावना है।

कैटरपिलर जैसे भुगतानकर्ताओं से एक नई चुनौती आएगी, जो काबू पाने में सक्षम है

प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बढ़ती लागत। यह उन भुगतानकर्ताओं के लिए एक अवसर पैदा कर सकता है जिनके पास सबसे कम राशि है

बिल चुकाने के बावजूद सिस्टम पर नियंत्रण।

मैकग्राथ कोलंबिया बिजनेस में प्रोफेसर हैं
विद्यालय; मुनीर फॉर्च्यून-500 सलाहकार, स्टार्टअप निवेशक और गैर-लाभकारी संस्था के सह-संस्थापक हैं
इनोवेशन के लिए मेडिसी इंस्टीट्यूट

thehindubusinessline.

आज से बीस साल पहले .

12 अप्रैल 2004

एसआईपी फंडों से दूर हो रहे निवेशक पिछले छह महीनों में इक्विटी फंडों में प्रवाह तेजी से बढ़ा है। लेकिन कुछ निवेशक फंड हाउसों द्वारा संचालित व्यवस्थित निवेश योजनाओं के माध्यम से अपना निवेश कर रहे हैं। कई फंड हाउस अन्य निवेशकों को एसआईपी निवेश पर 2 प्रतिशत के सामान्य प्रवेश भार से छूट देते हैं।

'ब्रिटेन में एशियाई स्वामित्व वाली कंपनियों की कीमत £8 बिलियन है' ब्रिटेन के एशियाई समाचार पत्र ईस्टर्न आई के एक अध्ययन के अनुसार, ब्रिटेन में एशियाई स्वामित्व वाली कंपनियों की कीमत लगभग £8 बिलियन है। श्री माइक जटानिया, जिनका लोर्नमेड व्यवसाय कई घरेलू ब्रांडों का मालिक है, अनुमानित £500 मिलियन की संपत्ति के साथ सूची में शीर्ष पर हैं। फार्मास्युटिकल कंपनी वेमेड ग्रुप की स्थापना करने वाले भाई श्री विजय और श्री भीखू पटेल 425 मिलियन पाउंड की संपत्ति के साथ सूची में दूसरे स्थान पर हैं।

'अपमानित' अनुबंधों से सूती धागा भेजने वालों पर असर पड़ा कई सूती धागा निर्यातक सुदूर पूर्व, विशेष रूप से कोरिया और हांगकांग के आयातकों के साथ किए गए "अपमानित" अनुबंधों को लेकर परेशान हैं। व्यापार सूत्रों का कहना है कि ये आयातक भारतीय स्पिनरों/सूती धागा शिपर्स के साथ बुक किए गए अनुबंध के लिए ऋण पत्र खोलने में विफल रहे हैं।

आरबीआई उपभोक्ता सेल के समक्ष कार्य

आगे की चुनौतियां। जबकि आरबीआई लोकपाल योजना ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसे जटिल उत्पादों के अनुकूल बनाने की जरूरत है

मानस आर दास

टी 11 मार्च 2024 को जारी लोकपाल योजना 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट, रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस), 2021 के तहत पहली स्टैंडअलोन रिपोर्ट है जो आरबीआई लोकपाल के 22 कार्यालयों की गतिविधियों को दर्शाती है। ORBIOs) 2022-23 के दौरान।

आरबी-आईओएस नवंबर 2021 में तीन पिछली लोकपाल योजनाओं, बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019 के विलय के माध्यम से अस्तित्व में आया। 1 सितंबर से , 2022, आरबी-आईओएस ने क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को भी कवर किया।

चूंकि ओआरबीआईओ में बैंकिंग क्षेत्र से प्राप्त शिकायतें अकेले बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्रों से प्राप्त कुल शिकायतों का बड़ा हिस्सा थीं, इसलिए यह लेख पूर्व क्षेत्र पर केंद्रित है। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, तीन साल की अवधि - 2020-21, 2021-22 और 2022-23 - को चर्चा के लिए माना जाता है।

तालिका 1 सात बैंक समूहों की स्थिति प्रस्तुत करती है: (ए) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), (बी) निजी बैंक (पीवीबी), (सी) भुगतान बैंक (पीवाईबी), (डी) छोटे वित्त बैंक (एसएफबी), (ई)) विदेशी बैंक (एफबी), (एफ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), और (जी) शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)।

बैंकिंग क्षेत्र के भीतर, पीएसबी और पीवीबी ने 90 प्रतिशत शिकायतें दर्ज कीं, जो क्रमिक रूप से 2020-21 में 94 प्रतिशत और 2021-22 में 93 प्रतिशत से कम हो गईं।

कुल मिलाकर, साल-दर-साल गिरावट 2021-22 (16.4 प्रतिशत) की तुलना में 2022-23 (26.6 प्रतिशत) में अधिक थी। एफबी, आरआरबी और यूसीबी को छोड़कर सभी ने समान रुझान प्रकट किए।

तालिका 2 शिकायतों की श्रेणी-वार स्थिति प्रस्तुत करती है। श्रेणी-वार, क्रम संख्या 1 से 5 शीर्ष शिकायतों में शामिल थीं, जो कुल शिकायतों का 93-95 प्रतिशत थीं। विशेष चिंता की बात क्रम संख्या 2, 3 और 8 थी जो 2022-23 में दर्ज की गई भारी उछाल के साथ लगातार बढ़ी।

वार्षिक रिपोर्ट में 1, 4 और 5 को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है: (ए) बैंकों में मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र की अनुपस्थिति और भोले-भाले या वित्तीय रूप से अशिक्षित ग्राहकों द्वारा गोपनीय जानकारी का खुलासा करने के कारण धोखाधड़ी वाले डिजिटल लेनदेन की घटना; और (बी) बैंकों द्वारा विफल लेनदेन को उलटने में अत्यधिक देरी।

ऋण संबंधी शिकायतें निम्नलिखित के कारण थीं: (ए) बैंकों की उधारकर्ताओं को ऋण के नियमों और शर्तों को ठीक से बताने में असमर्थता; (बी) गलत क्रेडिट रिपोर्ट के कारण सीआईसी को अद्यतन करने में अत्यधिक देरी; और (सी) मौजूदा वसूली दिशानिर्देशों पर अपने वसूली एजेंटों को शिक्षित करने में बैंकों की विफलता।

जमा खातों से संबंधित शिकायतें बढ़ीं खातों में न्यूनतम शेष न रखने पर शुल्क लगाने के कारण। पैरा-बैंकिंग शिकायतों में वृद्धि मुख्य रूप से गैर-बैंकिंग उत्पादों में बड़े पैमाने पर गलत बिक्री के कारण है।

2022-23 में क्रमांक 9 में उछाल आ सकता है छोटे मूल्यवर्ग के नोटों/सिक्के की अनुपलब्धता और/या बैंक शाखाओं द्वारा गंदे नोटों को बदलने में असमर्थता के कारण।

उल्लेखनीय विकास

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित दो बिंदु उल्लेखनीय हैं: पिछले कुछ वर्षों में, शायद आंतरिक लोकपाल योजना के कारण, बैंकों के स्तर पर शिकायतों की बढ़ती संख्या का निपटारा किया गया।

2022-23 के दौरान निपटाई गई कुल रखरखाव योग्य शिकायतों (यानी, जो शिकायतें अस्पष्ट नहीं हैं और आरबी-आईओएस की कार्यात्मक परिधि के भीतर आती हैं) में से, 58 प्रतिशत का बहुमत, सुलह/मध्यस्थता/सलाह जारी करने के माध्यम से हल किया गया था।

आरबी-आईओएस ने स्पष्ट रूप से समय के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है। हालाँकि, ORBIOs का काम तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि बैंकिंग खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, अधिक नवीन और जटिल उत्पाद विकसित हो रहे हैं, और अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राहक तेजी से जानकार और सूचित हो गए हैं। इसलिए, ORBIOs की क्षमता को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, जैसे-जैसे इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन और व्यापक होता गया और गहरा, एक तकनीक-सक्षम, मजबूत विवाद समाधान तंत्र जिसका उद्देश्य 'कम से कम लागत' के आधार पर त्वरित समाधान प्रदान करना है, खासकर खुदरा ग्राहकों के लिए, सर्वोपरि रहेगा। बढ़ी हुई वित्तीय साक्षरता सहायक होगी।

अंत में, आरबीआई अगले वर्ष के मार्च के बजाय 'रिपोर्टिंग वर्ष' के दिसंबर तक आरबी-आईओएस वार्षिक रिपोर्ट लाने पर विचार कर सकता है। इसके अलावा, अनुलग्नक 1 में प्रस्तुत 'शिकायत प्रति शाखा' डेटा, यदि 'कुल' शाखा के बजाय प्रति 'शिकायतकर्ता' शाखा दिया जाए, तो यह सांख्यिकीय रूप से अधिक सार्थक होगा।

दास एसबीआई के पूर्व वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं।
विचार व्यक्तिगत हैं.

Complaints received* — TABLE 1

Bank group	2020-21	2021-22	2022-23	y-o-y variation 22/21	y-o-y variation 23/22
PSBs	1,74,974 (55%)	1,54,725 (58%)	1,02,144 (52%)	-11.60%	-34.00%
PvBs	1,26,303 (39%)	94,275 (35%)	73,764 (38%)	-25.40%	-21.80%
PyBs & SFBs	6,918 (2%)	8,076 (3%)	7,888 (4%)	16.70%	-2.30%
FBs	6,157 (2%)	4,464 (2%)	5,639 (3%)	-27.50%	26.30%
RRBs & UCBs	6,382 (2%)	6,508 (2%)	7,200 (4%)	2.00%	10.60%
Total	**3,20,734 (100%)**	**2,68,048 (100%)**	**1,96,635 (100%)**	**-16.40%**	**-26.60%**

Category-wise complaints* — TABLE 2

Complaint category	2020-21	2021-22	2022-23	y-o-y variation 22/21	y-o-y variation 23/22
1 Mobile/ electronic banking	44,385 (24%)	39,388 (24%)	39,855 (23%)	-11.30%	1.20%
2 Loans and advances	20,218 (11%)	24,507 (15%)	39,579 (22%)	21.20%	61.50%
3 Deposit accounts related	8,580 (5%)	16,388 (10%)	33,612 (19%)	91.00%	105.10%
4 ATM/ Debit cards	60,203 (33%)	41,375 (25%)	28,635 (16%)	-31.30%	-30.80%
5 Credit cards	40,721 (22%)	32,162 (19%)	24,549 (14%)	-21.00%	-23.70%
6 Pension payments	4,966 (3%)	6,179 (4%)	4,377 (2%)	24.40%	-29.20%
7 Remittances	3,394 (2%)	3,235 (2%)	2,937 (2%)	-4.70%	-9.20%
8 Para banking	1,236 (1%)	1,480 (1%)	2,476 (1%)	19.70%	67.30%
9 Notes & Coins	332 (0.20%)	296 (0.20%)	505 (0.30%)	-10.80%	70.60%
Total	**1,84,035 (100%)**	**1,65,010 (100%)**	**1,76,525 (100%)**	**-10.30%**	**7.00%**

*at Offices of the RBI Ombudsman
Figures in brackets give percentages to total.

जैसे-जैसे इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन और व्यापक और गहरा होता जाएगा, 'कम से कम लागत' के आधार पर त्वरित समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से एक तकनीक-सक्षम, मजबूत विवाद समाधान तंत्र सर्वोपरि रहेगा।

मत्स्य पालन क्षेत्र में महिलाओं के लिए कच्चा सौदा

-सौरभ बंद्योपाध्याय
लक्ष्मी जोशी

मैं मछली उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। 2022-23 में, भारत ने लगभग 18 मिलियन टन का उत्पादन किया, जो वैश्विक उत्पादन का 8 प्रतिशत है। इसका लगभग 32 प्रतिशत समुद्री स्रोतों से और 68 प्रतिशत अंतर्देशीय स्रोतों से आया। मत्स्य पालन क्षेत्र भारत के जीवीए में 1.09 प्रतिशत और कृषि जीवीए में 6.7 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है।

जल निकाय अंतर्देशीय मत्स्य पालन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल निकायों की जनगणना (2018-19 के दौरान आयोजित और 2023 में रिपोर्ट की गई) के अनुसार, देश में 2.4 मिलियन जल निकाय हैं, जिनमें से 97.1 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 2.9 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में हैं। .

जल निकायों का वितरण इस प्रकार है: 59.5 प्रतिशत तालाब हैं; 15.7 प्रतिशत, टैंक; 12.1 प्रतिशत, जलाशय; 9.3 प्रतिशत, जल संरक्षण योजनाएं/रिसाव टैंक/चेक डैम; 0.9 प्रतिशत, झीलें; 2.5 प्रतिशत, अन्य.

अंतर्देशीय मत्स्य पालन रोजगार प्रदान करता है और भारत में 28 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका सहायता, जिनमें महिलाएं एक अभिन्न अंग हैं, पूर्व-सहायता में सहायता करती हैं।

और कटाई के बाद का काम - छीलना, समुद्री भोजन प्रसंस्करण, सामुदायिक देखभाल, आदि। एनसीएईआर के एक अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं की चिंताओं और हितों की अक्सर उपेक्षा की जाती है।

उदाहरण के लिए, महिला श्रमिक आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले की मछली मंडियों की शिकायत है कि संपूर्ण विपणन गतिविधियों में समान जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद उनके पास अलग शौचालय की सुविधा नहीं है। मत्स्य पालन क्षेत्र में लैंगिक संबंधों की हमारी समझ में अभी भी महत्वपूर्ण अंतर हैं।

काम की अनदेखी की गई

भारत में, मत्स्य पालन कार्यबल में 72 प्रतिशत महिलाएं हैं (एफएओ, 2016), जिनमें से 57 प्रतिशत बीज संग्रह में, 73.6 प्रतिशत विपणन में, और 75.7 प्रतिशत इलाज और प्रसंस्करण में लगी हुई हैं (सीएमएफआरआई, 2010)। उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, महिलाओं के काम को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

प्रसंस्करण उद्योग अक्सर महिलाओं को रोजगार देते हैं, लेकिन कठोर काम के घंटे, घरेलू जिम्मेदारियां और कार्यस्थल से दूरी के कारण उनके लिए समय पर काम पर उपस्थित होना मुश्किल हो जाता है, जिससे तनाव और यहां तक कि चोटें भी लगती हैं।

बड़ा योगदान. घटिया पुरस्कार

महिलाओं के लिए केंद्रीय संस्थान कृषि (CIWA) ने मत्स्य पालन में लिंग कार्य भागीदारी असमानता सूचकांक की गणना की है, जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। नागालैंड, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश में यह <0.15 है, जबकि पंजाब, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में यह 0.34 और 0.59 (CIWA, 2015) के बीच है।

भूमि और अन्य उत्पादक संसाधनों का स्वामित्व मुख्य रूप से पुरुष-प्रधान है; विकसित देशों में, महिलाओं के पास 20 प्रतिशत भूमि है, और अविकसित देशों में, यह केवल 2 प्रतिशत है। कई के कारण

संपार्श्विक कारकों या पुरुष प्रभुत्व के कारण, महिलाओं की वित्तीय पहुंच नहीं है सुविधाएं या विपणन समझौते। तकनीकी सुधारों के कारण कृषि और संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सीमित हो गई है, जिससे मुख्य रूप से पुरुषों को लाभ हुआ है।

97 देशों में, केवल 5 प्रतिशत कृषि विस्तार सेवाएँ महिला किसानों को प्राप्त होती हैं, जो दर्शाता है कि इन सेवाओं तक महिलाओं की पहुँच प्रतिबंधित है। जब पुरुष रोजगार की तलाश में कहीं और चले जाते हैं तो महिलाएं घर पर ही रह जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप काम का बोझ बढ़ जाता है और आय सृजन की संभावना कम हो जाती है। मत्स्य पालन में, महिलाओं को सामाजिक निर्णय लेने वाले प्लेटफार्मों पर कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जो निरंतर सुधारों को चुनौतीपूर्ण बनाता है।

लैंगिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता, महिला-समर्थक विपणन अवसंरचना, लिंग-उत्तरदायी अनुसंधान, पाठ्यक्रम पाठ्यक्रमों की लिंग मुख्य-स्ट्रीमिंग और लिंग-विभाजित डेटा संग्रह मत्स्य पालन क्षेत्र के स्थायी परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

लेखक क्रमशः सीनियर फेलो और फेलो हैं
एनसीएईआर

बीएल टू-वे क्रॉसवर्ड 2416

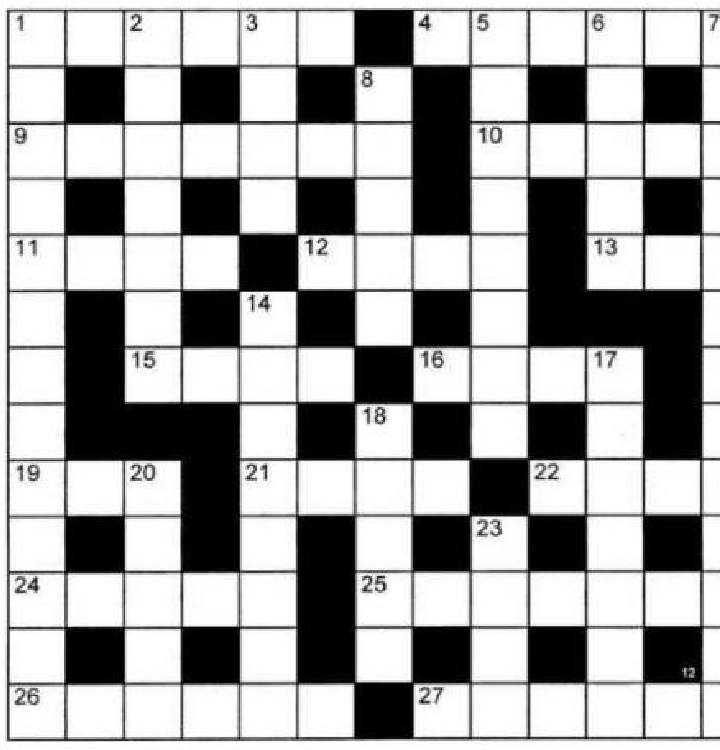

आसान

आर-पार

1. हब (6)
4. चिट-चैट (6)
9. डर से कांपना (7)
10. स्ट्रंग-अप (5)
11. कुल्हाड़ी आदि का हत्था (4)
12.हिन्दू परिधान (4)
13. मुद्रित के रूप में पढ़ा जाना (3)
15. प्याज से जुड़ी सब्जी (4)
16. स्टाइलिश लालित्य (4)
19. एक अग्रिम (3)
21. चिकनी सामग्री (4)
22. महाद्वीप (4)
24. धार्मिक चित्र (5)
25. वायरलेस टेलीग्राफी की प्रणाली (7)
26. बस इतना ही (2,4)
27. किसी की बात अनसुनी कर देना (6)

नीचे

1. अजीब पोजर (5,8)
2. आवश्यक (7)
3. चिढ़ाना (4)
5. सब एक साथ (8)
6. वायु (5)
7. का अमूर्तन मन (13)
8. ऋण निपटान (5)
14. चालू और चालू रहता है (8)
17. बुनाई समाप्त करें (4,3)
18. मनहूस आवास (5)
20. खाना पकाने का तरीका (5)
23. नि:शुल्क (4)

इतना आसान नहीं

आर-पार

1. बीच में होने के कारण विदेशी सिक्के को दोबारा बनवाना होगा (6)
4. बपतिस्मा के समय प्रायोजक बेकार की बातें करेगा (6)
9. एक नंबर लेने वाला लड़का गायक अपना डर दिखाएगा (7)
10. 'X' को आधा लटका हुआ देखा गया (5)
11. लॉन्च के अंत को स्टर्न की ओर संभालें (4)
12. चावल उगाने वाले को पहनाने के लिए आवश्यक परिधान (4)
13. अर्थात् एक अंदर: इसे वैसे ही पढ़ें (3)
15. शिल्प का अनिवार्य भाग सब्जी अपसेटिंग (4)
16. आधे घरेलू मुर्गों द्वारा दिखाई गई शोभा (4)
19. कोच को आगे बढ़ाएं - विपरीत दिशा में! (3)
21. क्यूसी की सामग्री आखिरकार देखने को मिलेगी - स्कॉटलैंड में भी ऐसा ही? (4)
22. ओपेरा में चीन का पिछड़ा होना चिंताजनक है (4)
24. धार्मिक चित्र बनाने वाला है (5)
25. वायरलेस टेलीग्राफी में सबसे पहले 24 में से एक को गलती से खराब कर दें (7)
26. बस एक पाठ के समान, एक अलग तरीका रखें (2,4)
27. किसी को इतना अधिक सुनाओ कि उसे कुछ भी न सुनाई दे (6)

नीचे

1. 'कोई भाग्य?' मछुआरे उसे फँसाने के लिए कुछ सोच सकते हैं (5,8)
2. ईंधन वितरण को समाप्त करने के लिए क्या आवश्यक है (7)
3. पत्नियाँ चीनी टेकअवे पर अतिरिक्त जा रही हैं, शायद (4)
5. अयोग्य, बर्खास्तगी? सही! (8)
6. विख्यात कथन (5)
7. पहले से, व्यापार व्यस्त मन की स्थिति का कारण बनता है (13)
8. मजदूरी की चिंता करके कर्ज चुकाओ (5)
14. व्यक्ति, जाते समय, हृदयहीन हो जाता है - फिर भी चलता रहता है! (8)
17. शिल्प को खोलें और बुनाई समाप्त करें (4,3)
18. स्कॉटलैंड में, केवल आधे में चिमनी, ख़राब आवास की गंदगी (5)
20. एक तरह से पकाएं, दूसरे तरीके से अंदर ही पकाएं (5)
23. किसी को जाने देना व्यर्थ है (4)

समाधान: बीएल टू-वे क्रॉसवर्ड 2415

पार 1. अतिशय 7. पराक्रम 8. मंद 9. आनंद 10. खोया हुआ 12. कान का दर्द 14. प्रतीत 17. थूक 18. बुआलो 21. कोर्सेर 22. बड़ा 23. दिखावा नीचे 1. ओरमोलू 2. मायावी 3. माल्ट 4. आलिंगन 5. अगोग 6. मूर्ति 7. मिल्ड्रेड 11. निजी 13. शिकायत 14. सूक्ष्म 15. पंसारी 16. भूखा रहना 19. किला 20. धैर्य

Machine Translated by Google

Business Standard

वॉल्यूम XXX संख्या 308

नई दिल्ली | शुक्रवार, 12 अप्रैल 2024

एक एप्पल दोहराना की जरूरत है

इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत बेहतर प्रदर्शन कर सकता है

टी विश्व व्यापार संगठन ने 2024 के लिए अपने व्यापारिक व्यापार मात्रा वृद्धि अनुमान को संशोधित कर 2.6 प्रतिशत कर दिया है, जो अक्टूबर के अनुमान से कम है।
3.3 फीसदी का. जबकि धीमी वैश्विक व्यापार वृद्धि संभावनाओं को प्रभावित करेगी, भारत को उभरती संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अमेरिका और चीन कम से कम पिछले पांच वर्षों से - बारी-बारी से गर्म और ठंडे - व्यापार युद्ध में रहे हैं। अमेरिका ने 2018 के जुलाई और अगस्त में देश में कुछ चीनी आयातों, विशेष रूप से मध्यवर्ती वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाकर इस बदलाव की शुरुआत की। अगले वर्ष के दौरान और टैरिफ लगाए गए। कुल मिलाकर, प्रभावित आयात लाइनों का मूल्य लगभग $350 बिलियन था। लेकिन, इस तरह के टैरिफ का उपभोक्ता कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझते हुए, तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने योजना के अनुसार टैरिफ बढ़ोतरी को आगे बढ़ाने से रोक दिया। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, लैपटॉप कंप्यूटर, कंप्यूटर मॉनिटर, मोबाइल फोन, वीडियो गेम कंसोल और खिलौने उच्च आयात शुल्क के दायरे में नहीं आते थे, दिसंबर 2019 के लिए एक विस्तार की योजना बनाई गई थी। हालांकि कई वस्तुओं को कभी भी उच्च टैरिफ के दायरे में नहीं लाया गया था, फिर भी उन वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव आया है। जबकि चीन से मोबाइल फोन के आयात में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि जारी रही, शेष दुनिया से आयात में 70 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।

भारत के लिए प्रासंगिक बात यह है कि वह इस जोखिम से मुक्ति की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत छोटा खिलाड़ी प्रतीत होता है। पिछले वर्षों में उद्योग समूह इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) द्वारा प्रकाशित कई रिपोर्टों ने इस बात को रेखांकित किया है कि हालांकि भारतीय निर्यात में वास्तव में वृद्धि हुई है, लेकिन व्यापार के इस पुनर्गठन से किसी भी लाभ का बड़ा हिस्सा वियतनाम जैसे देशों को चला गया है। जैसा कि इस अखबार ने रिपोर्ट किया है, नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि वियतनाम का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 2018 में 12.1 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 में 51.2 बिलियन डॉलर हो गया, जो उस समय अमेरिका में कुल गैर-चीनी वृद्धिशील इलेक्ट्रॉनिक्स आयात का 28 प्रतिशत से अधिक था। तुलनात्मक रूप से, भारत का $1.3 बिलियन से बढ़कर $8.9 बिलियन हो गया - इलेक्ट्रॉनिक्स आयात में गैर-चीनी वृद्धि का केवल 5.5 प्रतिशत। कंपनियां स्वेच्छा से अपनी आपूर्ति शृंखला के उन हिस्सों में चीनी घटकों को कम करने का विकल्प चुन रही हैं जो अमेरिकी बाजार को सेवा प्रदान करते हैं - और उनमें से कई इस उद्देश्य के लिए भारत के अलावा अन्य देशों को चुनते हैं।

इस आपूर्ति श्रृंखला में चीन का स्थान लेने में अन्य देश भारत से बेहतर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? दो कारण सामने आते हैं. पहला, यदि उनके पास कम, स्थिर टैरिफ और व्यापार व्यवस्था है। स्वाभाविक रूप से, यह मेक्सिको जैसे देशों के पक्ष में है, जो मौजूदा व्यापार समझौते में हैं। इससे वियतनाम जैसे उन लोगों को भी लाभ होता है, जिन्होंने पूर्वानुमानित, कम टैरिफ वाली व्यापार नीति अपनाई है। कंपनियों को शुल्कों में बदलाव या टैरिफ प्रतिबंधों से परेशान होना पसंद नहीं है। हालाँकि, भारत ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से टैरिफ में वृद्धि की है। दूसरा कारण व्यापक कारोबारी माहौल है। भारत ने Apple और उसके उपठेकेदारों को सफलतापूर्वक लुभाया है, और 2018 के बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में सात गुना वृद्धि को इस उपलब्धि के द्वार पर रखा जा सकता है।

लेकिन इसके साथियों ने अपनी व्यापार-समर्थक नीति में बेहतर प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए, वियतनाम, सैमसंग और एलजी दोनों के लिए चुना गया स्थानांतरण गंतव्य था। पूर्व इकाई वियतनाम से 123 देशों को निर्यात करती है, लेकिन भारत से केवल कुछ दर्जन देशों को।
अमेरिका के नेतृत्व में कंपनियों द्वारा चीन से अलगाव की आशंका का लाभ उठाने के लिए भारत के लिए अवसर की एक खिड़की बनी हुई है। लेकिन, जैसे ही भारतीय प्रतिस्पर्धियों में निवेश सफल होगा, अवसर की वह खिड़की बंद हो सकती है।

विनिवेश को पुनर्जीवित करना

अगली सरकार के लिए यह सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए

पिछले महीने बिज़नेस स्टैंडर्ड के एक कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई निजीकरण नीति के लिए. इस संदर्भ में कुछ चिंताएँ उभरीं 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट के बाद, वर्ष के लिए विनिवेश लक्ष्य स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया। ऐसे में मंत्री का बयान आश्वस्त करने वाला है. नई सार्वजनिक क्षेत्र नीति की घोषणा महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी। यह केंद्रीय बजट 2021-22 का भी हिस्सा था। नीति में सभी रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश की परिकल्पना की गई है। सरकार परमाणु ऊर्जा, बिजली, पेट्रोलियम और वित्तीय सेवाओं जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की न्यूनतम उपस्थिति बनाए रखेगी।

हालाँकि, कार्यान्वयन के लिए कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं है, जो शायद समझ में आता है क्योंकि विनिवेश और निजीकरण जटिल अभ्यास हो सकते हैं। कुछ सीपीएसई को कर्मचारी हितों की रक्षा जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण समय लग सकता है। फिर भी, संभावित जटिलता के बावजूद, सरकार को इस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने की सलाह दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार अगले कार्यकाल में बड़े फैसले लेगी और कथित तौर पर विभिन्न मंत्रालय इस संबंध में एक रोडमैप बना रहे हैं। अगली सरकार चाहे जो भी बने, ऐसे मजबूत कारण हैं कि क्यों विनिवेश को पुनर्जीवित करना एजेंडे में सबसे ऊपर होना चाहिए।

सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाकर महामारी से आर्थिक पुनरुद्धार का समर्थन किया है। हालाँकि इसने हाल के वर्षों में विकास को बढ़ावा दिया, उच्च सरकारी व्यय ने राजकोषीय समेकन प्रक्रिया को धीमा कर दिया। केंद्र सरकार 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य बना रही है। यदि विनिवेश निधि की आय पूंजीगत व्यय का हिस्सा हो तो राजकोषीय समेकन प्रक्रिया में तेजी लाने से भारतीय अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। वित्तीय बचत के लिए कम सरकारी मांग से निजी क्षेत्र के लिए धन बचेगा। निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय पुनरुद्धार के अस्थायी संकेत हैं। हालाँकि, यदि सरकार अधिशेष बचत का एक बड़ा हिस्सा अवशोषित करना जारी रखती है, तो निजी पूंजीगत व्यय का पुनरुद्धार जोखिम में होगा। इसे पूंजी आयात करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जो इस स्तर पर वांछनीय नहीं हो सकता है। इस प्रकार, बड़े पैमाने पर विनिवेश न केवल सरकारी पूंजीगत व्यय को बनाए रखने में मदद कर सकता है बल्कि निजी निवेश को पुनर्जीवित करने में भी मदद कर सकता है, जो विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

इसके अलावा, शेयर बाज़ार तेजी से बढ़ रहे हैं और परिदृश्य सकारात्मक है। यह मानते हुए कि भारत एक स्थिर सरकार चुनता है, जिसकी फिलहाल संभावना दिख रही है, चीजें और बेहतर हो सकती हैं। वैश्विक मुद्रास्फीति चरम पर है और वित्तीय स्थिति तुलनात्मक रूप से आसान हो गई है। निवेशकों को उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व इस साल के अंत में नीतिगत ब्याज दरों में कटौती शुरू करेगा। वैश्विक बाजारों में पैसे की कम लागत भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी प्रवाह का समर्थन करेगी, जो शेयर बाजार के मूल्यांकन को और बढ़ा सकती है। शेयरों की बढ़ती मांग और अनुकूल मूल्यांकन का मतलब है कि सरकार को अपनी संपत्तियों के लिए बेहतर कीमत मिलेगी। उसे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। विशेष रूप से, हालांकि सीपीएसई के स्टॉक की कीमतें, जैसा कि एसएंडपी बीएसई पीएसयू इंडेक्स से पता चलता है, पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी हो गई हैं, लेकिन मूल्य-से-आय अनुपात के संदर्भ में मूल्यांकन अभी भी बेंचमार्क एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स से काफी कम है। महत्वपूर्ण विनिवेश से निवेशकों की भागीदारी बढ़ने की संभावना है, जिससे इन कंपनियों के लिए विस्तार के लिए पूंजी जुटाना आसान हो जाएगा। इस प्रकार, आक्रामक विनिवेश और निजीकरण को आगे बढ़ाने से कई तरीकों से विकास में वृद्धि होगी।

आरबीआई 90 के स्तर पर फिट होकर लड़ रहा है

जब केंद्रीय बैंक प्रदर्शन करता है, जब वह सरकार सहित सभी हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखता है, तो राजनीतिक प्राधिकरण उसे अपना काम करने देने से बहुत खुश होता है।

चित्रण: बिनय सिन्हा

न केवल शिष्टता बल्कि एक सतर्कता और चपलता उस उम्र में असामान्य. इसकी जो प्रशंसा है 90 पर , भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) प्रधानमंत्री से प्राप्त किया गया मंत्री और वित्त मंत्री इसके योग्य हैं। आर्थिक उदारीकरण प्रक्रिया के दौरान आरबीआई का रिकॉर्ड शानदार रहा है। फिर भी, पिछले चार या पांच वर्षों का रिकॉर्ड इसलिए स्पष्ट है क्योंकि अपेक्षाकृत कम समय में आरबीआई को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

कोविड-19 संकट ने 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, जब बैंकिंग प्रणाली अभी भी 2019-20 में 8.5 प्रतिशत ऋण पर सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के साथ गहरे संकट में थी। फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन संघर्ष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी अनिश्चितताएँ पैदा कर दीं। वैश्विक विकास दर दो दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई।

इस बेहद तनावपूर्ण अवधि में, आरबीआई ने सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खुद को विश्वसनीयता से बरी कर लिया: मौद्रिक नीति, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता। यह वित्तीय स्थिरता का प्रबंधन है, जो संभवत: सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि है। 2020 में महामारी की शुरुआत में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ऋण के अनुपात के रूप में सकल एनपीए लगभग साढ़े तीन वर्षों में 3.2 प्रतिशत तक गिर सकता है। वित्तीय स्थिरता में योगदान देने वाली कई नीतियां समय के साथ विकसित हुई हैं; अन्य लोग महामारी की प्रतिक्रिया में उभरे। यह नीतियों के दोनों सेटों को देखने लायक है।

पर उंगली नाड़ी

टीटी राम मोहन

समय के साथ जो नीतियां विकसित हुई हैं, उनमें सबसे पहले, विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण है। विनियमन और पर्यवेक्षण एक ही इकाई में रखे गए हैं। हाल के वर्षों में आरबीआई ने बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के एकीकृत विनियमन की ओर कदम बढ़ाया है। ये दोनों नियामक को इन खिलाड़ियों के अंतर-संबंध को बेहतर ढंग से समझने और कमजोर स्थानों की तुरंत पहचान करने में सक्षम बनाते हैं।

दूसरे, आरबीआई ने "लाइट टच" विनियमन से परहेज किया है। यह नहीं मानता कि जोखिम प्रबंधन को पूरी तरह से बैंकों के बोर्ड और प्रबंधन पर छोड़ा जा सकता है। जहां आवश्यक हो, वहां विस्तृत प्री-स्क्रिप्शन बनाने में इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई है, उदाहरण के लिए, बैंकों के लिए बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क।

तीसरा, आरबीआई ने बैंक पूंजी पर नियामक वक्र से आगे रहने का विकल्प चुना है। जबकि बेसल मानदंड न्यूनतम 8 प्रतिशत पूंजी के लिए है, आरबीआई ने 9 प्रतिशत की आवश्यकता निर्दिष्ट की है। इसने वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद के उस ज्ञान का प्रतिपादन किया कि बैंकिंग में कम पूंजी की तुलना में अधिक पूंजी बेहतर है।

चौथा, आरबीआई ने एनबीएफसी के नियमन को सख्त कर दिया है। इसकी स्थिति यह है कि बड़े, व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी को बैंकों में परिवर्तित होना चाहिए और खुद को बैंकों पर लागू होने वाले सख्त विनियमन के दायरे में लाना चाहिए।

पांचवें, कई केंद्रीय बैंकों के विपरीत, आरबीआई ने लंबे समय से कई संकेतक दृष्टिकोण का पालन किया है। यह अपने दायरे को न केवल मूल्य स्थिरता बल्कि आर्थिक विकास, वित्तीय स्थिरता और वित्तीय समावेशन को कवर करने के रूप में देखता है। ये संकेतक परस्पर सुदृढ़ हैं। सभी संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करने से उनमें से प्रत्येक पर बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलती है।

छठा, बैंकों में निजी और विदेशी स्वामित्व के लिए एक रूपरेखा है जिसके तहत भारतीय बैंकों में एक इकाई के स्वामित्व की सीमा निर्धारित की जाती है। विदेशी बैंकों के लिए भी नीति है, जिसके तहत वे घरेलू बैंकों के समान व्यवहार की उम्मीद कर सकते हैं, बशर्ते वे सहायक मार्ग से आएं।

फिर, हमारे पास आरबीआई की कई रचनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं महामारी के लिए. तीन विशेष उल्लेख के पात्र हैं।
पहला है लोन चुकाने पर छह महीने की मोहलत. विश्लेषकों ने सोचा कि लगभग हर कोई इस सुविधा को लेने के लिए आगे आएगा। वे गलत थे: मोरा-टोरियम केवल बकाया ऋणों के 40 प्रतिशत के लिए लिया गया था। जिनको लिक्विडिटी की समस्या नहीं थी समय पर ऋण न चुकाने में उन्हें कोई लाभ नजर नहीं आया।
दूसरे, कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत ऋणों के पुनर्गठन की योजना थी। विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि बकाया ऋणों का 5 प्रतिशत तक पुनर्गठित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका आधा हिस्सा बाद में खराब हो जाएगा, जिसमें पहले से ही संकटग्रस्त क्षेत्र के ऋणों का 2.5 प्रतिशत एनपीए शामिल हो जाएगा।

ऐसा कुछ नहीं हुआ. औसतन, सभी ऋणों में से केवल 1.5 प्रतिशत का पुनर्गठन किया गया। केवल 0.2 प्रतिशत कॉर्पोरेट ऋणों का पुनर्गठन किया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुनर्गठन के लिए अर्हता प्राप्त करने की शर्तें और साथ ही कॉर्पोरेट पुनर्गठन के लिए निगरानी योजनाएं कड़ी थीं। उनका उद्देश्य फर्जी मामलों को छांटना और केवल वास्तविक लोगों की मदद करना था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एनपीए के स्तर में गिरावट आई है, वृद्धि नहीं हुई है।

फिर, मई 2020 में आरबीआई के परामर्श से सरकार द्वारा आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की घोषणा की गई।

आर्थिक संकट का सामना कर रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को पूरी तरह से गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) के रूप में ~ 3 ट्रिलियन तक की अतिरिक्त फंडिंग दी गई। विरोधियों ने ईसीएलजीएस योजना को एक और "ऋण मेला" के रूप में देखा, जिससे बैंकिंग प्रणाली में एनपीए फिर से बढ़ जाएगा। यह पता चला है कि ईसीएलजीएस योजना में एनपीए वितरित कुल राशि का 5 प्रतिशत है। मार्च 2023 में एमएसएमई में एनपीए सामान्य तौर पर ऋण का 6.8 प्रतिशत था।

पिछले कुछ वर्षों में, एमएसएमई क्षेत्र में एनपीए लगभग 9 प्रतिशत से अधिक रहा है।

कई अर्थशास्त्रियों के लिए "नियामक सहनशीलता" एक गंदा शब्द है। इसे "सड़क पर लात मारकर" समस्याओं को भविष्य की तारीख के लिए टालने के साधन के रूप में देखा जाता है।

आरबीआई ने उन्हें गलत साबित कर दिया है। इससे पता चला है कि नियामक सहनशीलता, यदि अच्छी तरह से डिजाइन और क्रियान्वित की जाए, तो सकारात्मक परिणाम उत्पन्न कर सकती है।

बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव का अपेक्षित परिणाम आया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के निजीकरण की चर्चा, जिसने बैंकिंग संकट के चरम पर जोर पकड़ लिया था, अब शांत हो गई है। इन बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार ही एकमात्र कारण नहीं है। कोई भी सरकार पीएसबी का निजीकरण इस तरह से नहीं करना चाहेगी कि निजी और विदेशी स्वामित्व के ढांचे से समझौता हो जो भारतीय बैंकिंग में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।

लगातार दो गवर्नरों के विवादास्पद इस्तीफे के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पदभार संभाला। घरेलू और विदेशी दोनों मीडिया में, भारत के केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता के संभावित क्षरण के बारे में ज़ोर-शोर से शिकायत की गई। श्री दास ने दिखाया है कि आरबीआई के लिए आवश्यक स्वायत्तता का प्रयोग करना और राजनीतिक प्राधिकरण के साथ टकराव के बिना दुनिया भर में उच्च स्तर की विश्वसनीयता हासिल करना संभव है।

यहां एक महत्वपूर्ण सबक है. स्वायत्तता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे केंद्रीय बैंक थाली में सजाकर दिए जाने की उम्मीद कर सकता है। जब केंद्रीय बैंक प्रदर्शन प्रदर्शित करता है, जब वह सरकार सहित सभी हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखता है, तो राजनीतिक प्राधिकरण उसे अपना काम करने देने से बहुत खुश होता है।

ttramमोहन28@gmail.com

उपभोग के लिए उधार लेना

यू कई विकासशील देशों की तरह, भारत को घरेलू बचत की उच्च दर का आशीर्वाद प्राप्त है।
सकल घरेलू बचत (जीडीएस) और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अनुपात 1960 के दशक में 15 प्रतिशत से बढ़कर 2012 में जीडीपी के 35 प्रतिशत पर पहुंच गया। तब से यह गिरकर लगभग 30 प्रतिशत पर आ गया है।

इसका मतलब यह है कि भारत निवेश की उच्च दर वहन करने में सक्षम है। इसलिए, कम उत्पादकता के बावजूद, हम उम्मीद कर सकते हैं कि न्यूनतम विकास दर लगभग 5 प्रतिशत रहेगी। इसका मतलब यह भी है कि सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए पूरी तरह से घरेलू स्तर पर उधार ले सकती है (और 2019 में राष्ट्र-विरोधी कैसेंड्रा द्वारा संप्रभु विदेशी ऋण लेने और कई अन्य देशों की तरह ऋण जाल में फंसने के प्रयासों का मुकाबला कर सकती है)).

हालाँकि, भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक कठोरता का मतलब है कि जीडीएस की संरचना नाजुक है। बचत जो वित्तीय प्रणाली में प्रवेश करती है (और इसलिए, संगठित क्षेत्र और सरकार द्वारा उधार लेने के लिए उपलब्ध है) जीडीएस का एक अंश है।

रथिन रॉय

बाकी (ऐतिहासिक रूप से भौतिक बचत कहा जाता है) को आवास, भूमि, कृषि और सोने जैसी विभिन्न परिसंपत्तियों में तैनात किया जाता है, लेकिन अनगिनत प्रतिबद्धताओं के बावजूद, हम केवल सटीक संरचना का अनुमान लगा सकते हैं। हम यह जानते हैं कि आज अर्थव्यवस्था की बढ़ती वित्तीय स्थिति के बावजूद भौतिक बचत घरेलू जीडीएस का 60 प्रतिशत से अधिक है। इसका मतलब यह है कि "आधुनिक" अर्थव्यवस्था को जीडीएस संख्या की तुलना में बचत के बहुत छोटे पूल के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी - पूंजी की लागत में काफी वृद्धि करना, या बचत पर ब्याज दरों के साथ वित्तीय दमन का सहारा लेना प्रशासनिक रूप से उनकी कमी के सापेक्ष कम रखा जाएगा। बाजार मूल्य।

इस पहेली का समाधान तभी हो सकता है जब वित्तीय बचत का हिस्सा उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाए। लेकिन यदा-कदा आशावादी रुझानों के बावजूद ऐसा नहीं हुआ है।

मूल कारण को संबोधित करने में असमर्थ नीति ने परिणामों को प्रबंधित करने की कोशिश की है। प्रशासित ब्याज दरों और पहले उपाय के उधारकर्ता के रूप में सरकार की विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति का उपयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने उधार दरों को उचित स्तर पर रखा है, हालांकि इससे वित्तीय बचत का मूल्य कम हो गया है और भौतिक बचत करने के लिए प्रोत्साहन को बल मिला है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समितियों ने सरकारी उधार पर प्रतिबंध लगा दिया है (व्हाट्सएप मिथक के विपरीत, एफआरबीएम सीमाएं मैक्रो-आर्थिक विश्लेषण के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, मास्ट्रिच की नकल करके नहीं, आदि)।

इसके अलावा, प्राथमिकता-क्षेत्र उधार जैसे उपकरणों का उपयोग करते हुए, आरबीआई प्रभावी ढंग से क्रेडिट-राशनिंग तंत्र भी तैनात करता है। इन सभी चीजों ने पूंजी की लागत को उचित स्तर पर रखने में मदद की है। पिछले 40 वर्षों में विदेशी निवेश के बढ़े हुए प्रवाह ने भी स्थिति को संभालने में मदद की है।

प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री निखिल गुप्ता के काम के रूप में अब क्षितिज पर नई चुनौतियाँ हैं।[1]

स्पष्ट करता है. किसी भी अर्थव्यवस्था में संपन्न परिवार प्रमुख शुद्ध बचतकर्ता (बचत घटा उधार) होते हैं। हाल के वर्षों में घरेलू उधारी में तीव्र वृद्धि हुई है, जो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 5.8 प्रतिशत है।

ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वित्त वर्ष 2023 में आय में कमजोर वृद्धि हुई थी और इसलिए परिवारों ने वित्त वर्ष 24 में बचत कम करके और अधिक उधार लेकर अपने निवेश और उपभोग की आकांक्षा को बनाए रखा। श्री गुप्ता को उम्मीद है कि यह वित्त वर्ष 2015 में भी जारी रहेगा।

अधिकांश घरेलू देनदारियां बैंक ऋण हैं, वित्त वर्ष 2019 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.1 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 4.4 प्रतिशत और वित्त वर्ष 24 में 4.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। घरेलू उधार में यह वृद्धि मैक्रो प्रबंधन पर दबाव डालती है क्योंकि इससे सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र द्वारा पूंजी निर्माण के लिए पूंजी की लागत बढ़ जाती है। यह आरबीआई-प्रशासित वित्तीय दमन और राशन प्रणाली की सीमाओं को प्रभावित करने के लिए बाध्य है, जिसे बढ़ती घरेलू उधारी से निपटने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है।

यदि ये उधार बड़े पैमाने पर आवास बंधक के लिए थे तो यह एक सुधार कारक होगा। लेकिन श्री गुप्ता दर्शाते हैं कि कर्ज़ में वृद्धि का बड़ा हिस्सा गैर-है। बंधक घरेलू ऋण, कारों और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, शादियों, स्वास्थ्य आपात स्थितियों आदि जैसी चीजों की खरीद के वित्तपोषण के लिए उपयोग किया जाता है। यह काफी हद तक असुरक्षित ऋण है।
यह वृद्धिशील ऋण उपभोग व्यय का वित्तपोषण कर रहा है, और इसलिए, सरकारी उपभोग के वित्तपोषण के लिए उधार लेने की तरह, निवेश के लिए उपलब्ध धन के पूल को कम कर रहा है और पूंजी की लागत बढ़ा रहा है। इस प्रकार, सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत पर घरेलू बंधक ऋण अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत पर गैर-बंधक घरेलू ऋण कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक है।

इसके कई व्यापक आर्थिक निहितार्थ हैं, लेकिन अधिकारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना का एक संरचनात्मक नतीजा है, जो आगे चलकर मध्य-आय के जाल की ओर इशारा करता है। बंधक ऋण का निम्न अनुपात बाज़ार-आधारित रियल एस्टेट गतिविधि के संकीर्ण आधार को दर्शाता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। घरेलू क्षेत्र द्वारा उपभोग-आधारित उधार निवेश पूंजी को और भी महंगा बना देता है। इस प्रकार, G20 में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय के साथ, सरकार और घरेलू परिवार दोनों अब उपभोग के लिए तेजी से उधार ले रहे हैं - सरकार बुनियादी सेवाएं और क्षतिपूर्ति सब्सिडी प्रदान करने के लिए और परिवार उपभोग को वित्तपोषित करने के लिए उधार ले रहे हैं। यह पूंजी की लागत पर दबाव डालने के लिए वित्तीय बचत के पहले से ही सीमित और घटते प्रवाह को प्रभावित करता है।

स्थिति नीतिगत कार्रवाई के अनुकूल है। मैंने पहले मूल कारण को संबोधित करने के बारे में बड़े पैमाने पर तर्क दिया है, लेकिन यदि इसकी अपेक्षा बहुत अधिक है, तो कम से कम इसके परिणामों को प्रबंधित करने की आवश्यकता है। अधिकारियों द्वारा इन रुझानों को सकारात्मक मानने की हालिया रक्षात्मक मुद्रा मूर्खतापूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना दोनों है। उन्हें स्थिति पर तत्काल नियंत्रण पाने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था पानीपत की एक और भ्रामक लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकती।

[1] निखिल गुप्ता और तनीषा लढ़ा "इकोस्कोप" 1 जून,
4 अक्टूबर, 2023, 19 मार्च, 2024 मोतीलाल ओसवाल

लेखक वरिष्ठ फेलो, ओडीआई, लंदन और भारत के प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य हैं

चीन की ताकतवर पार्टी

पुस्तक समीक्षा

गुंजन सिंह

टी वह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) हमेशा से ही छाया रहा है अपारदर्शिता में, जिसमें है गहरा-
शी जिनपिंग के अधीन हुआ। श्री शी, जो चीनी नेतृत्व की पांचवीं पीढ़ी से हैं, ने इतनी शक्ति अर्जित कर ली है कि उन्होंने खुद को सीपीसी का पर्याय बना लिया है। उनका लक्ष्य चीनी राष्ट्र का कायाकल्प है, एक ऐसा कार्य जिसे वे पूरा करने में उनके अलावा कोई भी सक्षम नहीं है। 2012 में सीपीसी के महासचिव का पद संभालने के बाद से उन्होंने लगातार पार्टी और सरकार के दृष्टिकोण को बदला है। जब वे 2013 में राष्ट्रपति बने तो कुछ आशावाद था जिसकी ओर उनका झुकाव होगा खुलापन और सुधार. हालाँकि, खुद को जीवन भर के लिए एक नेता के रूप में स्थापित करके, श्री शी ने सीपीसी और चीन के इर्द-गिर्द कहानी को बदल दिया है, जिससे वे सुर्खियों में आ गए हैं।

द पार्टी ऑफ़ वन: द राइज़ ऑफ़ शी जिनपिंग एंड चाइनाज़ सुपरपावर फ़्यूचर, श्री जिनपिंग को नेता समझने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य पढ़ना चाहिए। पुस्तक श्री शी के बचपन पर एक नज़र डालती है और सांस्कृतिक क्रांति ने उन पर कैसे प्रभाव डाला। उनके पिता की भूमिका और वे इसे कैसे समझते हैं, इस पर भी चर्चा और विश्लेषण किया गया है। कई अस्वीकृतियों के बाद भी पार्टी सदस्य बनने की उनकी प्रतिबद्धता पार्टी के बारे में उनकी धारणा को रेखांकित करती है।

लेखक का तर्क है कि प्रांतीय नेता के रूप में अपने शुरुआती वर्षों के दौरान, श्री शी की नीतियां और निर्णय उतने सफल नहीं थे। लेखक फ़ूज़ौ के चांगले हवाई अड्डे और सैनफैंग किक्सियांग विकास का उदाहरण देते हैं जो विवादों में घिरे हुए थे। श्री शी के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके इर्द-गिर्द मीडिया की कहानी बदल गई। श्री शी के पास लगातार शक्ति केंद्रित है, जिससे वह तब से सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक बन गए हैं माओ ने पार्टी के भविष्य को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं. चुन हान वोंग लिखते हैं, "शी के अपने शब्दों में, साथ ही उन लोगों के शब्दों में जो उन्हें जानते थे, उनकी महत्वाकांक्षाएं उन्हें धन की ओर नहीं, बल्कि सत्ता की ओर ले गईं।"

उन्होंने अपनी छवि बनाने के लिए प्रचार विभाग का भी इस्तेमाल किया है. "उन्होंने खुद को एक विनम्र व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने अपने कठिन अनुभवों, आम लोगों के प्रति आत्मीयता और पार्टी के प्रति वफादारी के माध्यम से शासन करने का अधिकार अर्जित किया। उनकी संभ्रांत पृष्ठभूमि, जिसे कभी कुछ साथियों ने तिरस्कृत किया था, को शी के मिशन और पितृभक्ति की भावना को चित्रित करने के लिए दोबारा प्रस्तुत किया गया,'' श्री वोंग कहते हैं।

श्री शी की पहली कार्रवाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियान थी। आम धारणा यह थी कि यह सत्ता को मजबूत करने का एक प्रयास था क्योंकि उनसे पहले हर नेता ने अपनी स्थिति को बढ़ाने के लिए इस चाल का सहारा लिया था। लेकिन "... एक अनुष्ठान रक्तपात के बजाय, शी ने एक वास्तविक रक्तपात शुरू कर दिया।" मुख्य लक्ष्य शी जिनपिंग के विचार के प्रति सभी विरोधों को दूर करना और मक्खियों के साथ-साथ बाघों पर भी प्रहार करना है। उनके प्रकोप से कोई भी सुरक्षित नहीं दिखता. यह युग्मित है चीन की कमजोर न्यायिक प्रणाली किसी को यह निष्कर्ष निकालने पर मजबूर करती है कि "पार्टी न्यायाधीश, जूरी या यहां तक कि जल्लाद की भूमिका भी निभा सकती है"।
श्री शी के लिए एक और बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था रही है। सुधार और खुलेपन के चार दशकों ने निजी क्षेत्र की स्थिति को बढ़ावा दिया है, लेकिन राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों (एसओई) की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं।

श्री शी के लिए अर्थव्यवस्था को चलाने का दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र और एसओई पर होना चाहिए। कोई यह तर्क दे सकता है कि निजी और सार्वजनिक उद्यमों का संतुलन चीनी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

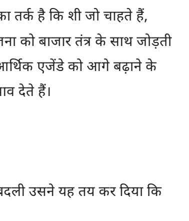

एक की पार्टी: द
शी जिनपिंग का उदय और
चीन की महाशक्ति
भविष्य
लेखक: चुन हान
वोंग
प्रकाशक: कोर्सेर
पृष्ठ: 416
कीमत: ~899

लेकिन श्री शी के नेतृत्व में निजी क्षेत्र अपना लाभ खो रहा है। "कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि शी जो चाहते हैं, वह एक मिश्रित प्रणाली है जो केंद्रीय योजना को बाजार तंत्र के साथ जोड़ती है, जहां राज्य और निजी उद्यम पार्टी के आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं" श्री वोंग सुझाव देते हैं।

जिस तरह से जैक मा की किस्मत बदली उसने यह तय कर दिया कि श्री शी का भविष्य कैसा होगा बढ़ते निजी क्षेत्र और उद्यमियों से निपटें। लेखक लिखते हैं, "स्वामित्व का प्रश्न तब तक मायने नहीं रखता जब तक वे पक्ष के साथ सुर में गाते हैं। चाबी बंद करना महंगा पड़ेगा।" श्री शी का मानना है कि वेतन बढ़ाने और नौकरियाँ पैदा करने की तत्काल आवश्यकता है और ऐसा करने के लिए "वह सबसे पहले राजनीति को फिर से कमान देंगे"।

ऐतिहासिक विमर्श का प्रबंधन पार्टी और उसकी वैधता के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है।

प्रत्येक कम्युनिस्ट नेता ने इस पुनर्लेखन में योगदान दिया है और श्री शी भी इससे अलग नहीं हैं।

पदभार ग्रहण करने के बाद से, श्री वोंग लिखते हैं, "...

शी जिनपिंग ने चीन के दिल और दिमाग के लिए लड़ाई छेड़ दी: कम्युनिस्ट पार्टी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, वह अतीत पर मजबूत पकड़ बना रहे थे... पार्टी को लुप्त होते पश्चिम पर चीन के प्रभुत्व के निर्विवाद गारंटर के रूप में प्रस्तुत करके, शी अपनी खुद की शक्ति को सुरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए कम्युनिस्ट शासन स्थापित करने की उम्मीद करते हैं।

आश्चर्य की बात नहीं है कि आज पार्टी जिस एक मुख्य चुनौती का सामना कर रही है वह उत्तराधिकार है। श्री शी ने डेंग जियाओपिंग के तहत स्थापित नेतृत्व परिवर्तन की समयबद्ध प्रक्रिया को छोड़ दिया है। उन्होंने अभी तक किसी संभावित उत्तराधिकारी की पहचान नहीं की है. कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि "मजबूत नेता विनम्र उत्तराधिकारियों को पसंद करते हैं जो उन्हें मात न दें या उन्हें धोखा न दें।

शी जिस किसी को उत्तराधिकारी के रूप में चुनते हैं वह अपेक्षाकृत कमजोर शासक हो सकता है जो खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है। जैसा कि लेखक रेखांकित करता है, "एक ऑटो-क्रेट की विरासत के लिए सबसे बड़ा खतरा वह स्वयं हो सकता है"।

लेखक उन पत्रकारों में से एक थे जो मीडिया पर शी जिनपिंग के कड़े नियंत्रण के निशाने पर थे। हालाँकि, उनका तर्क सही है कि पत्रकारिता के लिए कम होती जगह शी जिनपिंग के लक्ष्य में मदद नहीं कर रही है। सीपीसी की कार्यप्रणाली हमेशा रहस्य में डूबी रही है और श्री शी ने पर्दा और भी कसकर बंद कर दिया है। शीर्षक उपयुक्त है; वैकल्पिक विचारों और राय के लिए जगह कम होने के साथ, सीपीसी तेजी से श्री शी की पार्टी बनती जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्टी शी जिनपिंग के सामने टिक पाएगी?

समीक्षक जिंदल लॉ के एसोसिएट प्रोफेसर हैं
स्कूल, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी

Machine Translated by Google

राय

The Hindustan Times
ई अस्तबल 19 24 में स्थित है

{ हमारा लेना }

रक्षा कोण से कूटनीति

कई विदेशी मिशनों में रक्षा अताशे को भारत को रक्षा निर्यात बढ़ाने में मदद करनी चाहिए

एन नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त करने का कदम कई विदेशी मिशनों का एक हिस्सा है भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और उसका आत्म-ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में धारणा। यह इसे नई दिल्ली की 26 नए मिशन खोलने की योजना की पृष्ठभूमि में भी देखने की जरूरत है, जिनमें से 18 अफ्रीकी देशों में होंगे। **एक तीसरा कारक जो निर्णय को संदर्भ प्रदान करता है वह रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भरता) पर भारत का ध्यान है, जो न केवल आयात को प्रतिबंधित करने पर बल्कि भारतीय उत्पादों, विशेष रूप से अफ्रीकी देशों में निर्यात करने पर भी केंद्रित है।**

रूस जैसे मित्र राष्ट्रों में रक्षा अताशे और अमेरिका नई हथियार प्रणालियां हासिल करने और सैन्य-से-सैन्य सहयोग को सुविधाजनक बनाने के प्रयासों में शामिल है। वर्तमान दबाव विशेष रूप से व्यापार पहलू पर केंद्रित लगता है, विशेष रूप से रक्षा उत्पादन में निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने खुलासा किया कि भारत का रक्षा निर्यात 32.5% बढ़ा और ₹21,000- को पार कर गया।

पिछले वित्तीय वर्ष में पहली बार करोड़ का आंकड़ा। नई दिल्ली ने 2024-25 तक ₹35,000 करोड़ का रक्षा निर्यात लक्ष्य रखा है; भारत लगभग 85 देशों को सैन्य हार्डवेयर निर्यात करता है। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित तेजस हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जैसे प्रमुख उत्पादों के लिए एक व्यापक बाजार हो सकता है। फिलीपींस और आर्मेनिया में रक्षा अताशे नियुक्त करने का निर्णय कूटनीति में इस नए मीट्रिक को दर्शाता है: 2022 में, मनीला ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की तीन बैटरियां हासिल करने के लिए नई दिल्ली के साथ 375 मिलियन डॉलर का सौदा किया और आर्मेनिया पिनाका रॉकेट लॉन्चर के लिए पहला विदेशी ग्राहक बन गया। .

अफ्रीकी देशों - मोज़ाम्बिक, आइवरी कोस्ट, इथियोपिया और जिबूती - में नियुक्तियाँ नई दिल्ली की महाद्वीप तक पहुंच का अनुसरण करती हैं, जो जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिखाई दे रही थी जब भारत ने आक्रामक रूप से अफ्रीकी संघ को शामिल करने का समर्थन किया था। अफ़्रीकी महाद्वीप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। हाल के दिनों में, इसे उत्तर-औपनिवेशिक तीसरी दुनिया के आदर्शवाद द्वारा आकार दिया गया था, जिसमें नई दिल्ली ने अफ्रीका में कई राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों का समर्थन किया था और नए स्वतंत्र देशों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया था। इसका स्थान अब कठोर आर्थिक यथार्थवाद ने ले लिया है जिसमें भारत अफ्रीका को एक प्रमुख बाजार के रूप में उभरता हुआ देखता है। इस विस्तारित जुड़ाव का एक सुरक्षा आयाम भी है क्योंकि बीजिंग आक्रामक रूप से अफ्रीका को बढ़ावा दे रहा है और अपने बेल्ट और रोड पहल के एक हिस्से के रूप में वहां बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहा है।

व्यापार संतुलन पर अमेरिका की सख्त बात

टी यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के कोई असाधारण परिणाम नहीं हैं (अमेरिका) ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन का बस-चीन की यात्रा संपन्न हुई, लेकिन यह महत्वपूर्ण बनी हुई है दोनों देशों के बीच व्यापक जुड़ाव का हिस्सा। पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति जो बिडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद से इसमें तेजी आ रही है। दरअसल, येलेन के बीजिंग पहुंचने से कुछ दिन पहले बिडेन-शी की कॉल को यात्रा की प्रस्तावना के रूप में देखा गया था, जिसमें नेताओं ने मादक द्रव्यों के खिलाफ सहयोग, एआई से संबंधित जोखिम और जलवायु सहित कई मुद्दों पर हुई प्रगति की सराहना की थी। संकट।

हालाँकि, अमेरिका के लिए, काफी असुविधा के क्षेत्र बने हुए हैं। चाहे वह बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन और सौर विनिर्माण में चीन की अत्यधिक क्षमता को बढ़ावा देने वाली राज्य सब्सिडी हो या टिकटोक जैसे चीनी स्वामित्व वाले ऐप्स के आसपास डेटा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंताएं हों, इन्हें बीजिंग को सूचित करने की आवश्यकता है।

इस पृष्ठभूमि में, येलेन की यात्रा समस्याओं से निपटने के लिए सावधानीपूर्वक सोचे गए दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। एक राजनेता के बजाय एक शीर्ष आर्थिक दिमाग के रूप में उनकी छवि और अपने चीनी समकक्ष, हे लिफेंग के साथ उनके व्यक्तिगत संबंधों को देखते हुए, चीन को यह समझने की अधिक संभावना है कि उसने चीनी अतिक्षमता और ड्रैगन को घरेलू दबाव बढ़ाने की जरूरत पर अमेरिका के सख्त रुख की सराहना नहीं की है। उपभोग। चीन कैसे प्रतिक्रिया देता है यह दिलचस्प होगा।

जबकि वाणिज्य मंत्री वांग वेन्ताओ ने अत्यधिक क्षमता की चिंताओं को "निराधार" करार दिया है, कुछ चीनी नेता निजी तौर पर इस बात से सहमत हैं कि कुछ उद्योग गर्म हो रहे हैं। लेकिन चीन द्वारा दर्ज की गई कमजोर वृद्धि को देखते हुए कोई बदलाव संभव नहीं लग रहा है।

ऐसे संकेत हैं कि वह सबसे अधिक दांव लगाने को तैयार है, वह है बाजार की ताकतों को स्थिति को सही करने की अनुमति देना - यानी कमजोर कंपनियों को नीचे जाने देना। लेकिन चीन यह शिकायत नहीं कर सकता कि अगर अमेरिका और अन्य अर्थव्यवस्थाएं टैरिफ बाधाओं के अधिक सक्रिय मार्ग को प्राथमिकता देती हैं तो उसे चेतावनी नहीं दी गई थी।

एनसीईआरटी से लेकर आईआईटी तक विज्ञान दस्तक देता है

शैक्षिक संस्थानों की ओर से छात्रों से काल्पनिक परिकल्पनाओं और अपर्याप्त रूप से सिद्ध विचारों को आत्मसात करने के लिए कहना अवांछनीय और प्रवृत्तिपूर्ण है।

टी वह की अमर समापन पंक्तियाँ शेली की 1820 की कविता ओड टू पश्चिमी हवा, "द एक भविष्यवाणी की तुरही! हे हवा/अगर सर्दी आती है, तो कर सकते हैं वसंत बहुत पीछे रह गया है?", हालाँकि, अवांछनीय और वांछनीय के बीच उनका मेल नहीं हुआ

जब मैंने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के इतिहास के ग्रंथों में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा किए गए संशोधनों के बारे में पढ़ा तो मेरा मन

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण (एनसीईआरटी)। एनसीईआरटी की जिद चौंकाने वाली है यह स्थापित करते हुए कि हड़प्पावासी बाद में भारत के आद्य इतिहास में वैदिक लोगों के रूप में उभरे, मुझे इस विकृति से कोई सदमा नहीं लगा क्योंकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने ठीक यही कहा है।

खड़गपुर (IIT-K) ने अपने 2022 कैलेंडर में किया। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि सीबीएसई छात्रों के एक बड़े हिस्से की कल्पना शक्ति जागृत होती है आईआईटी में दाखिला लेने का सपना एनसीईआरटी उन्हें सिखाना चाहता है उस लक्ष्य की ओर तैयारी का तरीका? सबसे पहले आईआईटी-के के बारे में। 1951 में बनाया गया इसके पहले निदेशक के रूप में सर जेसी घोष और इसके बोर्ड सदस्यों में बीसी रॉय और एसएस भटनागर के साथ, इसका दृष्टिकोण "विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में वैश्विक नेताओं को तैयार करना" और "

ज्ञान सृजन का केंद्र बनें" सात दशकों बाद, कैलेंडर, को समर्पित भारतीय ज्ञान प्रणालियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, इसे "भारतीय ज्ञान प्रणालियों की नींव की पुनर्प्राप्ति" के लिए समर्पित किया गया था।

इसके घोषित उद्देश्य हैं: सबसे पहले, की मान्यता वेदों का रहस्य; अगला, सिंधु घाटी सभ्यता (आईवीसी) की पुनर्व्याख्या; और अंत में, आर्य आक्रमण मिथक का खंडन करना। इस ओर

अंत में, इसने 12 "सबूत" पेश किए, अजीब बहुवचन पर ध्यान न दें। इसने "सबूत" के रूप में जो पेश किया वह पक्षपातपूर्ण दावों की एक श्रृंखला थी: भारतीय सभ्यता की वर्तमान में स्वीकृत कालक्रम संदिग्ध और संदेहास्पद है; IVC और वैदिक के बीच कालानुक्रमिक अंतर

यह काल कुछ यूरोपीय विद्वानों की निन्दा है, उनके द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र है

"ब्रह्मांड संबंधी और परोपकारी नींव को नीचा दिखाना।" वेदों का" कैलेंडर ने यह दिखाने की कोशिश की कि आर्य आक्रमण मिथक कार्यों से कैसे उत्पन्न हुआ

मैक्स मुलर, आर्थर डी गोबिन्यू और एचएस चेम्बरलेन।

यह तो सर्वविदित है कि एडॉल्फ हिटलर आर्य श्रेष्ठता के विचारों को स्वीकार किया डी गोबिन्यू (1816-82) के कार्यों से, जिन्होंने एक लैन-गेज (इंडो-आर्यन) के नाम को एक जातीय-ग्राफिक शब्द (आर्यन) में बदल दिया, और चेम्बरलेन

ने इस विचार को और अधिक सुलभ बना दिया जर्मन। इसलिए, यह परे स्पष्ट है संदेह है कि भारत पर आर्यों का आक्रमण कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। हालाँकि यह भी स्थापित है कि "आर्यन" शब्द

संस्कृत का प्रयोग पहले मितन्नी में इंडो-ईरानी बोलने वालों द्वारा किया जाता था किसी व्यक्ति को संदर्भित करने की अवधि, जैसे "सर" शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह कितना बेतुका है

यह एक वैज्ञानिक अवलोकन के रूप में होगा यदि अब से सदियों बाद कोई भावी मानवविज्ञानी सरकार में फाइलें खोदेगा

पुरालेख और ए के अस्तित्व का दावा लोग "सर" कहते थे! कुछ ऐसा ही "आर्यन" शब्द के मामले में भी हुआ है।

हालाँकि, इसमें बहुत बड़ा अंतर है जिस तरह से भाषाएं प्रवास करती हैं और बड़ी आबादी ऐसा करती है। राखीगढ़ी स्केल-टन अनुसंधान के अंत के बीच पांच शताब्दी के अंतर के प्रश्न को खोलता है

1900 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा युग और वैदिक युग की शुरुआत लगभग 1400 ईसा पूर्व, लेकिन बहुत आगे तक

जी.एन
देवी

अनुसंधान की आवश्यकता होगी इसे बंद करें। भारतीय सभ्यता के यूरोपीय-विद्वानों को बदनाम करना किसी भी तरह से सिद्ध नहीं होता ऐतिहासिक रूप से गैर-मौजूद आर्य "बाहर चले गए।" यहाँ" के बजाय "यहाँ आया।" बाहर से"। बंदरगाह के लिए ऐसा विश्वास वैसा ही घृणित कार्य करने के समान है एडॉल्फ हिटलर की भूल प्रतिबद्ध लेकिन कल्पना के भारतीय छोर से।

पिछले दो दशकों के दौरान, आनुवंशिकी प्रागैतिहासिक काल की सूक्ष्म समझ तक पहुंचने में मदद मिली है जो पहले रहस्यों से घिरा हुआ था और बेतहाशा अनुमान के लिए खुला था। के संदर्भ में

भारत का, डेविड रीच की हू की **तरह काम करता है** वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर (2018) और टोनी जोसेफ की द अर्ली इंडियंस (2018) ने ठोस विवरण प्रस्तुत किए हैं

प्रवासन की विभिन्न लहरें। सिमी-लार्ली, डेविड एंथोनी की द हॉर्स, द व्हील, एंड लैंग्वेज: हाउ ब्रॉन्ज़-एज

यूरेशियन स्टेप्स शेप्ड द मॉडर्न वर्ल्ड के राइडर्स ने यूरेशियन में घोड़े से चलने वाले वैगनों के उदय का एक सटीक क्रम स्थापित किया है।

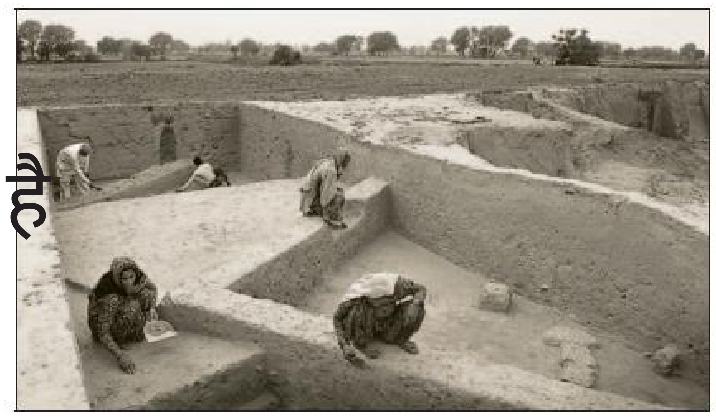

पिछले दो दशकों के दौरान, आनुवंशिकी ने प्रागैतिहासिक काल की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में मदद की है एचटी पुरालेख

स्टेपीज़ और उसके क्रमिक चरण भाषा का विकास, जो भारत की पश्चिमी सीमा पर आने के बाद संस्कृत के नाम से जानी जाने लगी।

इस इतिहास में निर्णायक मोड़ था तांबे का प्रयोग, घोड़ों पर नियंत्रण और व्हील-रन वैगनों का उपयोग जो प्राचीन यूरेशियन स्टेपी लोगों को अनुमति दी गई दक्षिण की ओर बाहर जाने के लिए और पश्चिम। इस प्रक्रिया में जिसे "प्रोटो-इंडो-यूरोपियन" (पीआईई) के रूप में वर्णित किया गया है, वह इंडो-यूरोपियन, इंडो-इरा-नियन और इंडिक में विभाजित हो गया। इंडिक बाद में था संस्कृत नाम दिया गया. इसका प्रारंभिक रूप अवेस्ता की भाषा से संबंधित था । **ध्यान देने योग्य बात यह है कि** अवेस्ता में प्रयुक्त इंद्र, मित्र, वरुण और होम जैसे कम से कम 380 शब्द पाए जाते हैं ।

ऋग्वेद.

दावा है कि हाल ही में प्राचीन राखीगढ़ी के कंकाल का डीएनए अध्ययन भाषा आंदोलन की पहले से स्थापित समझ को खारिज करता है, जो निष्पक्ष वैज्ञानिक विश्लेषण के बजाय जल्दबाजी, दूर की कौड़ी और एजेंडा से प्रेरित है। राखीगढ़ी कंकाल के डीएनए अध्ययन के आधार पर पुरातत्वविद् वसंत शिंदे और अन्य द्वारा प्रकाशित 2019 पेपर में, निष्कर्ष में कहा गया है कि डीएनए नमूना आईवीसी के बीच ईरानी किसानों के वंश की कोई उपस्थिति नहीं दिखाता है। यह नई दिशाओं की ओर इशारा करता है

भारत में कृषि के इतिहास पर शोध के लिए। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है, "आईवीसी के एक व्यक्ति के डेटा का हमारा विश्लेषण, 11 के साथ मिलकर

आईवीसी के साथ सांस्कृतिक संपर्क में साइटों से पहले रिपोर्ट किए गए व्यक्ति, एक पूर्व-प्रयास ढाल के अस्तित्व को प्रदर्शित करते हैं जो प्रायद्वीपीय के उत्तर-पश्चिम में किसानों में व्यापक था।

आईवीसी के शिखर पर भारत, जिसमें स्टेपी चरवाहों या पश्चिमी ईरानी किसानों या चरवाहों का कोई आनुवंशिक योगदान नहीं था, और इसका बाद के दक्षिण एशियाई लोगों की वंशावली पर प्राथमिक प्रभाव पड़ा। जबकि हमारा अध्ययन यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि यह वंशावली है

प्रोफ़ाइल आईवीसी की एक सामान्य विशेषता थी, एक एकल नमूना - या यहां तक कि हमारे द्वारा पहचाने गए 12 संभावित आईवीसी नमूनों का ग्रेड-डिएंट - पूरी तरह से विशेषता नहीं दे सकता है महानगरीय प्राचीन सभ्यता।"

भाषाओं के विकास का लेखा-जोखा तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक भाषाविज्ञान पर आधारित हैं। वे इसका दृढ़तापूर्वक संकेत करते हैं संस्कृत ऐतिहासिक रूप से पीआईई का बाद का चरण है और दक्षिण एशिया में हरप्पा-पूर्व इसका कोई अस्तित्व नहीं है। देखते हुए विभिन्न विषयों की वर्तमान स्थिति - मानव आनुवंशिकी, प्राचीन डीएनए अध्ययन, भाषा विज्ञान, पुरातत्व और भोजन और कृषि का इतिहास - यह अवांछनीय है

और की ओर से पूरी तरह से संवेदनशील एनसीईआरटी छात्रों से काल्पनिक परिकल्पनाओं और अपर्याप्त रूप से सिद्ध विचारों को आत्मसात करने के लिए कहेगा।

जीएन देवी राष्ट्रीय ख्याति के प्रोफेसर और स्कूल ऑफ सिविलाइजेशन के निदेशक हैं। सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय, बॉम्बे। व्यक्त किये गये विचार व्यक्तिगत हैं

चुनावों के बावजूद, भारत-अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे

मैं 2024 में, लगभग 3.5 अरब लोग बाहर हो जायेंगे ग्रह के आठ अरब की ओर प्रस्थान करेंगे चुनाव. सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रत्याशित में से दो दुनिया के दो राज्यों में होंगे चुनाव सबसे बड़े लोकतंत्र, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य (अमेरिका)। वाशिंगटन ने एक नया नेता चुना हर चार साल में, जबकि नई दिल्ली एक चुनती है हर पाँच में एक नई सरकार, और दो में एक बार दशकों, गणित के नियमों द्वारा, चुनावी वर्ष मेल खाता है. चुनाव प्रचार, प्रचार-प्रसार और राजनीतिक नारेबाज़ी होती है दोनों देशों में चल रहा है.

लोकतंत्र स्वाभाविक रूप से शोरगुल वाला होता है, और जीवंत मीडिया घराने और झगड़ालू सोशल मीडिया तरह-तरह के पूर्वानुमान लगाता है। कुछ राजनीतिक पंडितों ने दावा किया है कि भारत-अमेरिका संबंधों में गिरावट आ रही है। यह सच से बहुत दूर है।

सभी लोकतंत्रों में, एक सामान्य दिन पर, वहाँ विरोधाभासी राय, रंगीन बातचीत और जोरदार बहसें हैं। दोनों में

अमेरिका और भारत में कुछ राजनीतिक हस्तियां हैं जो भटक जाती हैं और पराधीन हो जाती हैं कानूनी न्यायशास्त्र के लिए. हाल ही में, में दोनों देशों की प्रमुख राजनीतिक हस्तियां राजनीतिक प्रतिष्ठान के पक्ष से बाहर हो गईं। बहुत कुछ हो चुका है

मीडिया में इसके बारे में बात की गई और राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना की गई सबसे आगे लाया गया.

हालाँकि, कानूनी प्राथमिकता सभी लोकतांत्रिक प्रतिष्ठान इसे स्वीकार करते हैं

बेशक और यह सहयोगियों और रणनीतिक के लिए उपयुक्त है साझेदार हस्तक्षेप न करें।

भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी वास्तव में है द्विदलीय और राजनीतिक रूप से अज्ञेयवादी। जबकि कुछ स्वतंत्र टिप्पणीकार भिन्न हो सकते हैं भावनाओं पर, आँकड़े स्वयं बोलते हैं। भारत में 1991 के सुधारों की शुरुआत के बाद से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अर्थ है बड़े पैमाने का आकर्षण

वैश्विक वाणिज्यिक बाजार ने दोनों देशों के बीच आर्थिक-आर्थिक संबंधों को फलीभूत किया है।

भारत-अमेरिका व्यापार नगण्य $2 से रह गया तीन दशक पहले एक बिंदु तक मिलियन अब जहां वाशिंगटन, नई दिल्ली शीर्ष पर है व्यापारिक भागीदार, जिसका द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में लगभग 200 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। इसके 500 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है आने वाले वर्षों में, नए विकास के साथ रक्षा, कृषि, अंतरिक्ष, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्र भी

जैसी महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ अर्धचालक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), और क्वांटम कंप्यूटिंग। अकेले 2023 में, भारत-अमेरिका संबंधों की परिणति एक के रूप में हुई साझेदारी के लिए सबसे अधिक उत्पादक वर्ष। एक युगांतकारी वर्ष जो केवल तीसरे वर्ष द्वारा चिह्नित है एक भारतीय नेता की वाशिंगटन की राजकीय यात्रा।

ए से कूटनीतिक गति प्राप्त हुई ऐतिहासिक राजकीय यात्रा धूमधाम से आगे बढ़ी और तुच्छ बातें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने रखा बहुआयामी क्षेत्रों में नए संवादों और पहलों के साथ एक रणनीतिक रोडमैप

जैसे स्वच्छ ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, अंतरिक्ष सहयोग, अर्धचालक, क्वान-टम कंप्यूटिंग, ड्रोन प्रौद्योगिकी और एआई। में स्मारकीय समझौते हुए भारत में GE F-414 जेट इंजन के निर्माण जैसी संयुक्त परियोजनाओं में तेजी लाई गई ऐसे देशों के विशिष्ट क्लब में भारत विनिर्माण क्षमता.

वाशिंगटन और नई दिल्ली ने नए सिरे से गहन रक्षा तालमेल बनाना जारी रखा है महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र 2023 में शुरू की गई पहलों के साथ

क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलो-जीज़ (iCET), और INDUS-X पर पहल। के साथ साथ उनके क्वाड पार्टनर ऑस्ट्रेलिया और जापान, भारत और अमेरिका दोनों बने रहेंगे

एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक को सुरक्षित करने में दृढ़। वे इसमें सफल भी रहे हैं विश्वास के नए आर्थिक गलियारे बनाना ऐतिहासिक भारत-मध्य पूर्व-यूरोप इको-नोमिक कॉरिडोर (आईएमईईसी), जो I2U2 (विशेषता) में पश्चिम एशिया क्वाड का अनुपालन करता है

भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात, और अमेरिका)। 2023 की सफलताएँ इसे जारी रखती हैं इस साल दोनों देश नए निर्माण पर काम कर रहे हैं व्यापार संबंध, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाना, स्वच्छ ऊर्जा गलियारे बनाना, और पश्चिम में I2U2 सहयोग को मजबूत करना एशिया.

इसके अलावा, बिडेन का समर्थन था 2023 G20 शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता, जो भारत के लिए एक यादगार वर्ष रहा और बिडेन की पहली यात्रा को चिह्नित किया भारत अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में. के एक समय में वैश्विक संघर्ष, G20 शिखर सम्मेलन में भारत की कुशल कूटनीति को दुनिया ने देखा नेता शांति का आह्वान करते हैं और कूटनीति को प्राथमिक उपकरण के रूप में उपयोग करें संघर्ष समाधान के लिए. नई दिल्ली के लिए बोलने में सफल रहे वैश्विक समानता और अधिक समतावादी विश्व, ग्लोबल साउथ के लिए बल्लेबाजी, विशेष रूप से शामिल करने के लिए G20 में अफ़्रीकी संघ.

मुकेश
अघी

अतीत में, वैध आलोचनाएँ हुई हैं भारत की व्यवस्था बहुत अधिक संरक्षणवादी और नौकरशाहीवादी है। आज देश है सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश. के साथ जनसांख्यिकीय लाभांश, देश के पास है विश्व मंच और वैश्विक पर अधिक साहसी दृष्टिकोण आकांक्षाएँ. यह दूसरों को संलग्न करना जारी रखता है द्विपक्षीय और लघु-पार्श्व और बहुपक्षीय मंचों दोनों के माध्यम से भागीदार।

भारत ने परंपरागत रूप से संरक्षित निजीकरण किया है रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र, और यहां तक कि इसका राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया। भारत का ऐतिहासिक चंद्रयान-3 की लैंडिंग का रास्ता साफ दोनों के बीच गहरा अंतरिक्ष सहयोग देशों, और इंडस-एक्स के तहत, के लिए जगह अंतरिक्ष स्टार्टअप में निवेशकों के लिए अधिक विकास।

अमेरिका और भारत इसे और मजबूत करेंगे इस वर्ष विदेशी और रक्षा नेताओं और क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन के बीच 2+2 संवाद में द्विपक्षीय साझेदारी, जो

नई दिल्ली मेजबानी करेगी. लेकिन, ज़ाहिर है, विदेशी नीति अस्थायी रूप से छह के रूप में पीछे हट जाती है सप्ताह भर का मतदान शुरू।

अमेरिकी चुनाव, जबकि कुछ महीने दूर, के लिए कठिन बाधाएँ प्रस्तुत करें निवर्तमान राष्ट्रपति. जबकि राष्ट्रपति बिडेन को घरेलू स्तर पर सफलता का गौरव प्राप्त हुआ है मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम (आईआरए) और चिप्स और विज्ञान अधिनियम में बिगड़ते हालात पश्चिम एशिया, यूक्रेन में विस्तारित युद्ध, जल्दबाजी अफगानिस्तान से वापसी, और का उदय युद्धरत चीन उनके सर्वेक्षण को देखना जारी रखता है संख्या घट जाती है. इससे भी बड़ी कहानी यह है जबकि अमेरिका और भारत समाचार चक्र होंगे राजनीतिक विमर्श के प्रभुत्व के कारण, वाणिज्यिक प्रक्षेपवक्र ऊपर की ओर बना हुआ है रुझान। राजनीतिक किस्मत की परवाह किए बिना बदल रहा है, आर्थिक भाग्य बना हुआ है वही, बीच के मजबूत बंधन को मजबूत करना दो राष्ट्र.

मुकेश अघी अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी हैं अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी के अधिकारी मंच। व्यक्त किये गये विचार व्यक्तिगत हैं

{ फुमियो किशिदा } जापान के प्रधान मंत्री

पी को बदलने का एकतरफ़ा प्रयास बलपूर्वक यथास्थिति बिल्कुल है अस्वीकार्य, चाहे वह कहीं भी हो। अमेरिका और जापान जारी रहेंगे ऐसी हरकतों का जवाब दें

दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के सैन्य दावों की पृष्ठभूमि में

पुस्तकालय स्वतंत्रता, न्याय के लिए मामले को बाध्य कर सकते हैं

डब्ल्यू हेन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III ने संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) का दौरा किया वाक्यांश का सामना करना पड़ सकता है "लोगों के लिए महल," एक शब्द अक्सर अमेरिकी सार्वजनिक पुस्तकालयों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। वह निश्चित रूप से इसके महत्व के प्रति आश्वस्त थे वहां उनका सामना सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली से हुआ; वह बड़ौदा में एक बनाने के लिए एक अमेरिकी को नियुक्त किया 1910 में - और इस प्रकार, विलियम एलनसन बोर्डेन ने आधुनिक भारत में मुफ्त पुस्तकालयों की एक प्रणाली बनाई।

एक प्रकाशक ने हाल ही में मुझे केरल-अला के बारे में बताया, जहां करीब 10,000 पुस्तकालय हैं: "वहां की बात ही अलग है" (केरल देश के बाकी हिस्सों से अलग है)। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य की पहले लगभग पूर्ण साक्षरता आई, और फिर आई किताबें और पढ़ने की संस्कृति। तो, अगर हम कर सकते गायकवाड़ और उनके मुफ़्त पुस्तकालयों के प्रति प्रेम के केवल एक शताब्दी बाद, केरल की राह पर आगे बढ़ने के लिए बस खुद को प्रेरित करें, हम उस सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना के बारे में सोच सकते हैं जिसकी भारत को आवश्यकता है।

प्रकाशक सही है. केरल देश के बाकी हिस्सों से अलग है, जहां प्रति 80,000 लोगों पर एक शहरी पुस्तकालय का अनुपात बेहद खराब है।

और प्रत्येक 11,500 लोगों पर एक ग्रामीण पुस्तकालय। लेकिन वह इसलिए भी गलत है लोग पहले साक्षरता और फिर किताबें नहीं हासिल करते। वे किताबें पहले हासिल करते हैं और साक्षरता उसके बाद। केरल का साक्षरता आंदोलन पहले हुआ था एक सदी लंबे पुस्तकालय आंदोलन द्वारा।

और यहां तक कि केरल भी अब ऐसा नहीं कर पाएगा केरल की तरह स्वायत्तता का प्रयोग करें। केरल के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदू

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज़ ने लाइब्रेरी प्रश्न को केंद्र से स्थानांतरित करने की केंद्र की योजना पर अपने राज्य की आपत्ति जताई।

समवर्ती सूची में राज्य. केरल इससे चिंतित है यदि वे अपने पुस्तकालयों पर नियंत्रण खो देते हैं, तो वे ऐसा करेंगे अब वे अपनी गुणवत्ता बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे प्रणाली, जो एक के अनुपात में पुस्तकालय प्रदान करती है प्रति 3,500 लोग.

भारत में पुस्तकालय आन्दोलन अधिकतर नहीं चला महाराजाओं या सरकारी अधिकारियों द्वारा नेतृत्व किया गया । यह एक जन आंदोलन रहा है, जिसका नेतृत्व उन लोगों ने किया है जो निस्संदेह समझते हैं कि लोगों को यह समझ है उन स्थानों का अधिकार जहां वे मिल सकें, बात कर सकें, पढ़ सकें और एक साथ सोचें. आंदोलन में नेता भारत के विभिन्न स्थानों और समय से आए हैं: बड़ौदा में मोतीभाई अमीन, आंध्र प्रदेश में सर अय्यंकी वेंकट रामनय्या, केरल में पीएन पणिक्कर, बंगाल में मोनींद्र देव राय महा-शय, राजस्थान में मास्टर मोतीलाल, संत राम भाटिया पंजाब, असम में कुमुदेशर बार-ठाकुर, सहित अन्य। एसआर रंगा-नाथन, जिन्होंने इस आंदोलन की कल्पना की थी

राष्ट्रीय स्तर के महत्व को समझा निःशुल्क पुस्तकालयों और राष्ट्र के बीच संबंध। सिर्फ रंगनाथन ही जिम्मेदार नहीं हैं मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, पहला पुस्तकालय भारत में अपनाया गया कानून, लेकिन एक मॉडल के लिए भी पुस्तकालय अधिनियम, अफसोस, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर कभी नहीं अपनाया गया।

भारत में वर्तमान पुस्तकालय आंदोलन भी है एक जन आंदोलन. इसका नेतृत्व 300 से अधिक पुस्तकालय करते हैं देश भर के अभ्यासकर्ता और नेता 200 से अधिक निःशुल्क पुस्तकालय संगठनों का प्रयास और संचालन करते हैं। फ्री लाइब्रेरी नेटवर्क में लगभग किसी भी लाइब्रेरी के पास संसाधनों तक पहुंच नहीं है

यह उन्हें वह करने की अनुमति देगा जो वे करते हैं, जो कि सभी लोगों का स्वागत करना है और किसी को भी उन पुस्तकालयों में मुफ्त सदस्यता से रोकना है जहां साहित्य और समुदाय पनपते हैं। जो चमत्कारी प्रतीत होता है उसका संबंध चमत्कारों से कम और लोगों की तात्कालिकता को पूरा करने की प्रतिबद्धता से अधिक है।

मृदुला
कोशी

सूचना तक पहुंच की आवश्यकता.

निःशुल्क पुस्तकालय आंदोलन यह स्वयं को एक जाति-विरोधी आंदोलन के रूप में वर्णित करता है क्योंकि यह अपनी भूमिका को पहचानता है जाति ने लोगों को पुस्तकालयों से बाहर रखने में भूमिका निभाई है। की भूमिका को पहचानता है जाति उन्मूलन में पुस्तकालय। यह शुरू होता है इस दावे के साथ कि पुस्तकालयों को ऐसा करना चाहिए जाति-विरोधी होने के लिए स्वतंत्र रहें।

भारत में ये जुझारू शब्द हैं, जहां पढ़ने के माहौल से लोगों का सक्रिय बहिष्कार तब होता है जब राजस्थान में एक बच्चे को पानी के 'गलत' कंटेनर तक पहुंचने के लिए उसके शिक्षक द्वारा पीटा जाता है।

पीपुल्स नेशनल लाइब्रेरी पॉलिसी 2024 फ्री लाइब्रेरी नेटवर्क का (पीएनएलपी24) इस आधार से शुरू होता है कि पुस्तकालयों को मुक्त होना चाहिए सभी लोगों, सभी जातियों, धर्मों, लिंगों के लिए लागत, वर्ग, जातियाँ, योग्यताएँ, और किसी को भी किसी भी तरह से वर्जित नहीं करना चाहिए, और इससे भी आगे लोगों को करना चाहिए पुस्तकालय में संकलित विचारों में से चयन करने के लिए स्वतंत्र रहें। चुनने की स्वतंत्रता का महत्व जो पढ़ना है वह आवश्यक रूप से पर्याप्त सार्वजनिक धन और पुस्तकालयों के पर्याप्त अनुपात से शुरू होता है प्रति व्यक्ति और पुस्तकें, और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालयों पर स्थानीय स्वायत्तता।

हम पुस्तकालय बनाने के लिए स्वायत्तता पर भरोसा कर सकते हैं लोगों को संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के वादे को सुनिश्चित करने के लिए पीएनएलपी24 की तर्ज पर एक अच्छी राष्ट्रीय नीति की जरूरत है। संविधान उतनी ही आसानी से सर्वोत्तम सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का वर्णन कर सकता था जितना कि यह हमारे राष्ट्र का वर्णन करता है

बनने की कोशिश कर रहा हूँ.

मृदुला कोशी, एक लेखिका, फ्री लाइब्रेरीज़ नेटवर्क की बोर्ड सदस्य हैं। व्यक्त किये गये विचार व्यक्तिगत हैं

आरएनआई नंबर 503/1957 • पोस्टल रजि. क्रमांक DL(ND)-11/6058/2018-19-20 'बिना पूर्व भुगतान के पोस्ट करने का लाइसेंस' लाइसेंस क्रमांक U(C)-113/2006-08, हवाई अधिभार: रायपुर और उससे आगे रेल या सड़क मार्ग से - 5 रुपये /-, अहमदाबाद, बैंगलोर, कोयम्बटूर, चेन्नई, कोचीन, गोवा, हैदराबाद, खजुराहो, मुंबई, त्रिवेन्द्रम, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और उससे आगे रेल या सड़क मार्ग से - रु. 10/-;
एचटी मीडिया लिमिटेड 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 ... (ऊपर)। पिन-201306.
बोर्ड: (011)23361234 • संपादकीय: (011)66561234 एक्सटेंशन। 1254, 1268 • प्रसार: (011)66561111 • विज्ञापन: (011)66561389 • फैक्स: (011)66561270।
संपादक: कुणाल प्रधान

Machine Translated by Google

हमारा दृष्टिकोण

आईस्टॉकफोटो

क्या माता-पिता को अपने बच्चों के अपराधों की कीमत चुकानी चाहिए ?

किशोर अपराध में माता-पिता की ज़िम्मेदारी कहाँ से शुरू और ख़त्म होती है? में माता-पिता को दोषी ठहराया गया अमेरिका में उनके 15 साल के बेटे द्वारा ली गई जान से भारत में भी यह कांटेदार सवाल उठता है

टी उन्होंने खबर दी कि जेनिफर और जेम्स अमेरिका के मिशिगन में 2021 में चार साथी छात्रों की हत्या के दोषी ठहराए गए 15 वर्षीय एथन के माता-पिता क्रम्बली को गैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया है और 10-15 साल जेल की सजा सुनाई गई है, यह एक चेतावनी है सभी के लिए

हम। अभागे माता-पिता पर जूरी ने मुकदमा चलाया अपनी संतानों की वजह से हुई मौतों के लिए दोषी। उनका अपराध? अपने बेटे को रोकने में असफल हो रहे हैं जघन्य अपराध करना। एक दिन और उम्र में जब कई माता-पिता, यहां तक कि हमारे जैसे अपेक्षाकृत पारंपरिक समाजों में भी, नुकसान पर शोक व्यक्त करते हैं माता-पिता का अपने बच्चों पर 'नियंत्रण', बढ़ रहा है बाल अपराध की घटनाएँ जीवन का एक दुखद तथ्य है। लेकिन एक अपराधी के माता-पिता की सजा, ए अमेरिकी इतिहास में पहली बार, माता-पिता और बच्चों के लिए एक आह्वान है- और वास्तव में बड़े पैमाने पर समाज के लिए - आत्मनिरीक्षण करना। माता-पिता की जिम्मेदारी कहां से शुरू होती है और किशोर अपराध के संदर्भ में अंत?

निश्चित रूप से, बंदूक नियंत्रण पर अमेरिका की विफलता - रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच विवाद की एक बड़ी जड़ - ऐसी हत्याओं के लिए दोष का एक बड़ा हिस्सा साझा करना चाहिए। अमेरिका में बड़े पैमाने पर गोलीबारी की घटनाएं चिंताजनक रूप से अक्सर सामने आती रहती हैं। फिर भी, यह हमें माता-पिता की ज़िम्मेदारी के अधिक परेशान करने वाले प्रश्न के साथ छोड़ देता है। सजा जारी करने से पहले मिशिगन के पोंटियाक में ओकलैंड काउंटी सर्किट कोर्ट के न्यायाधीश चेरिल मैथ्यूज ने कहा, "माता-पिता से मानसिक रोगी होने की उम्मीद नहीं की जाती है," लेकिन ये सजाएं खराब पालन-पोषण के बारे में नहीं हैं।

ये दृढ़ विश्वास बार-बार किए गए कृत्यों या कृत्यों की कमी की पुष्टि करते हैं जो आने वाली भागती हुई ट्रेन को रोक सकते थे - बार-बार उन चीजों को नजरअंदाज करना जो एक उचित व्यक्ति को उसकी गर्दन के पीछे बाल खड़े होने का एहसास कराते हैं। पीड़ितों में से किसी एक के पीड़ित माता-पिता से कोई भी सहमत नहीं हो सकता है कि "त्रासदी पूरी तरह से पूर्व-कल्पना योग्य थी।" फिर भी, जैसा कि क्रम्बलीज़ के परीक्षण से पता चला,

इस बात के पर्याप्त सबूत थे कि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने न केवल अपने बेटे की मानसिक परेशानी के चिंताजनक संकेतों को नजरअंदाज किया, बल्कि इससे भी बुरी बात यह है कि उन्होंने यह सुनिश्चित करने का भी ध्यान नहीं रखा कि खतरनाक हथियार उसकी पहुंच से दूर रखे जाएं। हम भारत में इस मामले में बेहतर स्थिति में हैं; बंदूकों तक पहुंच आसान नहीं है. परिणामस्वरूप, किशोरों द्वारा ऐसे जघन्य अपराध दुर्लभ हैं। हालाँकि, कम उम्र और कभी-कभी जानलेवा लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामलों की बढ़ती संख्या से पता चलता है कि नाबालिगों के साथ बच्चों जैसा व्यवहार करने की सामाजिक कीमत चुकानी पड़ती है। पिछले हफ्ते ही, दिल्ली में आठवीं कक्षा के एक छात्र का भयावह मामला सामने आया था, जिसे स्कूल में सहपाठियों के एक समूह द्वारा कथित तौर पर छड़ी से यौन उत्पीड़न के बाद आंतों में चोट लग गई थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की भारत में अपराध 2021 रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में नाबालिगों से जुड़े 31,710 अपराध दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.7% अधिक है। भारतीय कानून के तहत, 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को 'नाबालिग' माना जाता है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और संबंधित 2021 संशोधन 16-18 आयु वर्ग के किशोरों पर कानून के जघन्य उल्लंघन के मामलों में वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। लेकिन संबंधित किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रारंभिक सुनवाई के बाद ही। इसके अलावा, भारतीय कानून के तहत, किसी भी बच्चे को रिहाई की संभावना के बिना किसी भी अपराध के लिए आजीवन कारावास या मौत की सजा नहीं दी जा सकती है। मिशिगन मामले में, अपराधी पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया गया और बिना पैरोल के सलाखों के पीछे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

भारत का कानून माता-पिता की गलती पर चुप है। लेकिन जैसा कि हम तेजी से बढ़ती हिंसक दुनिया से जूझ रहे हैं, जहां माता-पिता का अक्सर अपने बच्चों पर सोशल मीडिया की तुलना में कम प्रभाव होता है, उदाहरण के लिए, शायद हमारे लिए माता-पिता की जिम्मेदारी के कठिन प्रश्न की जांच करने का समय आ गया है: यह कहां से शुरू होता है और कहां समाप्त होता है किशोर अपराध का संदर्भ? कोई आसान जवाब नहीं हैं।

मेरा दृष्टिकोण | टेक व्हिस्पर्स

क्रिस्टल बॉल गेजिंग स्कोरकार्ड: एआई आंशिक रूप से भविष्यवाणी के अनुसार विकसित हुआ है

तकनीकी युद्ध ज्यादातर पूर्वानुमान के अनुसार ही चल रहे हैं लेकिन सब कुछ वैसा नहीं चल रहा है जैसा जनवरी में लग रहा था

जसप्रीत बिंद्रा
एक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, 'द टेक व्हिस्पर्र' के लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एआई और एथिक्स में मास्टर हैं।

यहां तक कि मानवता भी इन सबके बारे में चिंता करती है एआई नौकरियों को प्रभावित करेगा, एक पेशा स्पष्ट रूप से खतरे में है भविष्य निर्धारित करना. एक भविष्यवादी के पास क्या काम है अगर सब कुछ समय-समय पर बदलता रहे क्योंकि एक एआई कंपनी एक ऐसा उत्पाद पेश करती है जिसे देखकर हमारे होश उड़ जाते हैं। हर जनवरी में, मैं उन शीर्ष 10 चीज़ों की भविष्यवाणी करता हूँ जो उस वर्ष तकनीकी क्षेत्र में घटित होंगी; और फिर साल के अंत में कुछ घबराहट के साथ वापस जाइए और स्कोर कीजिए कि मैंने अपनी भाग्य-बताने की क्षमताओं में कैसा प्रदर्शन किया। मैंने इस जनवरी में भी ऐसा ही किया और 2024 के लिए अपनी 10 एआई भविष्यवाणियाँ जारी कीं। हालाँकि, नवाचार के हमले को देखते हुए, मैंने एक त्रैमासिक स्कोर-कार्ड बनाने का संकल्प लिया है। वर्ष की पहली तीव्र तिमाही समाप्त होने के साथ, यहाँ यह है:

तकनीकी युद्ध भड़केंगे: मैंने कहा, एआई की दौड़ तेज हो जाएगी, माइक्रो-सॉफ्ट-ओपनएआई गठबंधन एक पुनरुत्थानशील Google के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा में है। OpenAI GPT5 लॉन्च करेगा, जो Gem-ini Ultra को पीछे छोड़ देगा। फैसला: यह अभी भी खेला जाना बाकी है, लेकिन संकेत आशाजनक दिख रहे हैं। सैम ऑल्टमैन ने "वर्ष के मध्य" में GPT5 के बारे में बात की है। ऐसा प्रतीत होता है कि जेमिनी अल्ट्रा को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है और इसे अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। तो, यह पैसे के मामले में सही लगता है, 10/10।

AI बढ़त पर है: Pixel पर जेमिनी नैनो और iPhones पर AppleGPT स्लीपर हिट हो सकते हैं, जो OpenAI को बढ़त से हटा देंगे। मोबाइल पहुंच और एकीकरण पीसी पर जीत हासिल करेगा।

फैसला: सैमसंग एआई फोन लॉन्च हुआ फ़रवरी। माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस एआई संस्करण की घोषणा की गई, उसके बाद इंटेल एआई पीसी की घोषणा की गई। क्वालकॉम ने 2024 के अंत तक $99 AI फोन की भविष्यवाणी की है। कोई AppleGPT नहीं। लेकिन एआई तेजी से बढ़त की ओर बढ़ रहा है। तो यह 7/10 है।

नियमन की दौड़: यह दौड़ एआई विकसित करने की दौड़ जितनी ही बड़ी है। EU AI अधिनियम के बाद, कई अन्य देश AI नियम जारी करेंगे। परमाणु IAEA या CoP जलवायु शिखर सम्मेलन की तर्ज पर वैश्विक विनियमन के लिए प्रयास किया जाएगा। फैसला: ईयू एआई अधिनियम सही समय पर आया। अन्यथा, हमारे पास कार्रवाई से अधिक शोर था। भारत और अमेरिका को अभी भी व्यापक नियमों की घोषणा करनी है। 4/10.

काम का भविष्य: एआई ट्रांस- शुरू करेगा विशेष रूप से माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट और इसी तरह के उत्पादों के लॉन्च के साथ, निर्माण कार्य। GenAI के लिए कार्य सबसे बड़ा उपयोग मामला होगा। फैसला: माइक्रोसॉफ्ट अब हर चीज के लिए कोपायलट के साथ है, जिसमें इसके सरफेस कीबोर्ड पर कोपायलट कुंजी भी शामिल है। जीथब कोपायलट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन 365 कोपायलट अभी भी कमजोर है। 3/10.

एआई का नौकरियों पर असर: नौकरियों पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन दुनिया भर में कई कंपनियां एआई और जेनएआई का इस्तेमाल करेंगी दक्षता के लिए छंटनी हेतु कवर। फैसला: प्रौद्योगिकी जगत में हर कोई नौकरियां छोड़ रहा है और 'एआई संबंधी दक्षताओं' को दोष दे रहा है। हर देश एआई के जरिए नौकरियों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। 7/10.

खुला और मालिकाना एलएलएम: दूसरी दौड़ मालिकाना के बीच होगी

शीघ्र पढ़ें

सप्ताह दर सप्ताह प्रौद्योगिकी में बदलाव के साथ, वर्ष की शुरुआत की भविष्यवाणियों की त्रैमासिक समीक्षा उचित होगी। 2024 के लिए अब तक, पूर्वानुमान के अनुसार बहुत कुछ हुआ है लेकिन बहुत कुछ वैसा नहीं हुआ है।

तकनीकी युद्ध गर्म हो रहे हैं, स्मार्टफोन पर एआई वास्तविकता के करीब है और एआई के नेतृत्व वाली नौकरी में बदलाव की तैयारी चल रही है, लेकिन हम अभी भी मुख्य एआई अधिकारियों को नहीं देख रहे हैं क्योंकि एआई को अपनाना थोड़ा धीमा है।

और ओपन-सोर्स GenAI, विकेंद्रीकरण के विरुद्ध परफॉर्म-एसेंस ट्रेडिंग के साथ। मालिकाना तकनीक का दबदबा कायम रहेगा, कम से कम 2024 में।

निर्णय: ऐसा प्रतीत होता है कि खुला स्रोत स्वामित्व को समाप्त कर रहा है। ग्रोक खुला हो गया है, मेटा लामा गैंगबस्टर्स बन रहा है। वहां गति है. अपनी गर्दन बाहर निकालते हुए, मुझे लगता है कि 2024 अभी भी ओपनएआई और गैर-ओपन मॉडल का है। 5/10.

बिग टेक को नया आकार दिया गया: नया होगा माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, नेटफ्लिक्स, अल्फाबेट और अमेज़ॅन की बिग टेक लीग में प्रवेशकर्ता। फैसला: एनवीडिया का रथ आगे बढ़ रहा है। यह अब नंबर 3 बिग टेक फर्म है, और इसके हालिया डेवलपर दिवस पर दिलचस्प घोषणाएं हुई थीं। लगता है गूगल फिसल रहा है. 7/10.

एआई लोकतंत्र के लिए खतरा है: 2024 में 2 अरब से अधिक लोगों के चुनाव में जाने के साथ, कई खिलाड़ियों द्वारा आख्यानों और मतदाताओं के दिमाग को बदलने के लिए डीपफेक जैसी तकनीकों का सक्रिय रूप से उपयोग किया जाएगा। फैसला: इस पर मेरे दांत पीस गए हैं। अभी कॉल करना जल्दबाजी होगी क्योंकि अमेरिका और भारत दोनों में चुनाव इस साल के अंत में हैं। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए तो डीपफेक अस्थिरता के संकेत अभी भी आशाजनक दिखते हैं। 5/10.

Microsoft और OpenAI: Microsoft OpenAI खरीद सकता है या उससे नाता तोड़ सकता है। कुछ बड़े वित्त पोषित GenAI स्टार्टअप बंद हो सकते हैं (स्थिरता?), और कुछ का विलय हो सकता है।
फैसला: आह, यह दिलचस्प है।
माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई के खिलाफ एक बड़े बचाव कदम में मुस्तफा सुलेमान और इन्फ्लेक्शन पर कब्ज़ा कर लिया। ऑल्टमैन थोड़ा अस्थिर दिख रहा है। इमाद मोस्ताक बाहर हैं; स्थिरता अब उतनी स्थिर नहीं रही. 8/10.

मुख्य एआई अधिकारी: अधिक कंपनियां सीएआईओ की नियुक्ति करेंगी, जैसे उनमें से कई के पास मुख्य डिजिटल अधिकारी थे। CAIO शहर में नया हॉट टिकट बन जाएगा।

फैसला: ठीक है, कहीं न कहीं गलती तो होनी ही चाहिए। बहुत सारे CAIO नहीं हैं, क्योंकि व्यवसाय ने अभी तक GenAI को अपनाया नहीं है। 0/10.

वे कहते हैं कि कभी भी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, खासकर भविष्य के बारे में। लेकिन तकनीक जगत पीटर ड्रकर से सहमत होगा जब उन्होंने कहा कि भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका इसे बनाना है। और कोई भी एक चीज़ एआई की तरह भविष्य का निर्माण नहीं कर रही है।

10 YEARS AGO

JUST A THOUGHT

एआई मानवता के लिए या तो सबसे अच्छी या सबसे खराब चीज़ होने की संभावना है।

स्टीफन हॉकिंग

अतिथि दृश्य

अमेरिका में अमूल: आइए भारतीय सहकारी समितियों को वैश्विक स्तर पर ले जाएं

जॉर्ज स्केरिया

एक स्तंभकार और हालिया पुस्तक 'बियॉन्ड थ्री जेनरेशन: द डेफिनिटिव गाइड टू बिल्डिंग एंड्योरिंग इंडियन फैमिली बिजनेस' के सह-लेखक हैं।

पिछले सप्ताह, गुजरात सहकारी दूध मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) ने मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (एमएमपीए) के साथ साझेदारी की घोषणा की जिसके तहत ब्रांडेड अमूल दूध अमेरिका में हजारों भारतीयों और अमेरिकियों को उपलब्ध कराया जाएगा। यह कई कारणों से महत्वपूर्ण है.

एक, भले ही अमूल उत्पाद पहले से ही लगभग 50 देशों में निर्यात किए जा रहे हैं, यह पहली बार है कि अमूल की ब्रांडेड ताज़ा दूध रेंज भारत के बाहर कहीं भी लॉन्च की जा रही है। दूसरा, हालांकि यह कदम वर्तमान में अमेरिका तक ही सीमित है, इसमें अन्य क्षेत्रों में अमूल ब्रांड के लिए द्वार खोलने और इसे वैश्विक स्तर पर ले जाने की क्षमता है।

तीन, यह अन्य भारतीय सहकारी समितियों के लिए - जो बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय या उप-राष्ट्रीय संगठन हैं - वैश्विक संस्थानों में खिलने के लिए एक आकांक्षात्मक टेम्पलेट तैयार करता है।

दरअसल, पिछले दो दशकों में कॉरपोरेट भारत में वैश्विक कंपनियों का उदय हुआ है, लेकिन सहकारी समितियों के मामले में ऐसा नहीं हुआ है।

यह उसे बदलने का समय है.

भारत के सहकारी आंदोलन का इतिहास: स्वतंत्रता और एक कानून पारित करके औपचारिक सहकारी संरचनाओं के अस्तित्व में आने से पहले भी, भारत के कई हिस्सों में सहकारी गतिविधियाँ प्रचलित थीं। उदाहरण के लिए, अनाज की कटाई के बाद ग्रामीण समुदाय सामूहिक रूप से संसाधनों को इकट्ठा करेंगे ताकि अगली समुद्री फसल से पहले समूह के जरूरतमंद सदस्यों को उधार दिया जा सके।

सहकारी समिति विधेयक 25 मार्च 1904 को अधिनियमित किया गया था। 14 दिसंबर 1946 को, खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादक दूध संघ, जिसे अमूल के नाम से जाना जाता था, पंजीकृत किया गया था। 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद, सहकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला और यह पंचवर्षीय योजनाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया।

अक्टूबर 1964 में आनंद, गुजरात की यात्रा पर, दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा लाए गए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन से प्रभावित होकर, भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की स्थापना की कल्पना की।), पूरे देश में दुग्ध सहकारी समितियों के आनंद पैटर्न को दोहराने के लिए।

1991 के आर्थिक सुधारों के साथ, सहकारी समितियाँ तीव्र दबाव में आ गईं। लेकिन उन पर अधिक ध्यान देने के प्रयास में, संघ सहयोग मंत्रालय जुलाई 2021 में कृषि मंत्रालय से अलग करके बनाया गया था। वर्तमान में, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लगभग 300 मिलियन सदस्यों वाली 850,000 से अधिक सहकारी समितियाँ हैं, जो डेयरी, कृषि, आवास, ऋण, मत्स्य पालन, हथकरघा और चीनी जैसे कई क्षेत्रों को कवर करती हैं। उनमें से दो, जीसीएमएमएफ और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी (इफको), दुनिया की अग्रणी सहकारी समितियों में से हैं।

भारतीय सहकारी समितियाँ, वैश्विक पहुंच: जीसीएमएमएफ द्वारा अमेरिका में ताजा ब्रांडेड अमूल दूध पेश करने का कदम अन्य भारतीय सहकारी समितियों को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। यह कैसे किया जा सकता है? अमूल चैप्टर से कुछ सीख लेना एक उपयोगी और आसान पहला कदम हो सकता है। जीसीएमएमएफ के पहले और पूर्व अध्यक्ष और व्यापक रूप से स्वीकृत 'भारत की श्वेत क्रांति के जनक' वर्गीज कुरियन के करिश्माई नेतृत्व ने अमूल की सफलता में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिशिगन विश्वविद्यालय

शीघ्र पढ़ें

अमेरिका में अमूल का लॉन्च न केवल ब्रांड के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवेश के द्वार खोलने में एक महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है, बल्कि अन्य भारतीय सहकारी समितियों के लिए वैश्विक स्तर पर जाने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है।

इसके लिए नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। हम उन देशों की प्रथाओं से सीख सकते हैं जहां सहकारी समितियों का सफलतापूर्वक वैश्वीकरण हो गया है। आइए कुछ लोगों को इस उद्देश्य के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके शुरुआत करें।

पूर्व छात्रों ने पांच दशकों से अधिक समय तक अमूल की देखरेख की और आंशिक रूप से 'अमूल गर्ल' शुभंकर के माध्यम से एक मजबूत ब्रांड बनाया। जबकि उनके कार्यकाल की लंबी उम्र उनके नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण कारक थी, वे सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों से राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने में भी सक्षम थे। भारत को दूध की कमी वाले देश से अधिशेष वाले देश (वैश्विक दूध उत्पादन में मौजूदा 24% हिस्सेदारी के साथ) में बदलकर, उन्होंने विश्व स्तर पर पहचान हासिल की।

हालाँकि निगम वर्तमान में संगठन के प्रमुख रूपों में से हैं, मलेशिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और केन्या जैसे कुछ अन्य देशों में सहकारी समितियाँ फल-फूल रही हैं। इन देशों में सहकारी समितियों से सीखना और उनके साथ सहयोग करना उपयोगी होगा। संयोगवश, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। इसलिए, भारत के सहकारी आंदोलन के वैश्वीकरण का एक विशेष संदर्भ है।

न्यूजीलैंड में फोंटेरा (डेयरी के लिए), वॉलनट कोऑपरेटिव और जेस्प्री (कीवी फल के लिए) जैसे मजबूत वैश्विक सहकारी संगठन हैं। ये सभी सहकारी बिजनेस एनजेड नामक एक व्यापक संगठन का हिस्सा हैं, जो अपने सदस्य संस्थानों को शासन, विपणन, प्रौद्योगिकी सहायता, वकालत और साझेदारी के लिए कार्यशालाओं और गतिविधियों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर जाने में सहायता करता है। यह सहकारी समितियों के लिए अगली पीढ़ी का नेतृत्व विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम भी संचालित करता है ताकि ये संस्थाएं दीर्घायु हों। भारत ऐसी प्रथाओं से सीख सकता है और ऐसे संगठनों के साथ साझेदारी कर सकता है।

अंत में, एक बार में वैश्विक पहुंच और मान्यता के लिए पूरे सहकारी क्षेत्र को एक साथ विकसित करने की कोशिश करने के बजाय, विभिन्न क्षेत्रों से चैंपियन सहकारी समितियों का एक चुनिंदा समूह बनाना उपयोगी होगा। वर्तमान में, लगभग 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियाँ हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए 'नवरत्न' अवधारणा की तरह, सरकार वैश्विक भारतीय सहकारी समितियों के रूप में लगभग 10-12 राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों का चयन कर सकती है।

यात्रा आसान नहीं होने वाली है, लेकिन भारतीय सहकारी समितियों को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए एक ढांचा तैयार करने से रोजगार, धन सृजन और इस प्रकार समग्र राष्ट्रीय विकास में मदद मिलेगी।

Machine Translated by Google

उनका दृष्टिकोण

प्रश्नकाल: क्या विपक्षी दलों ने संसद में अच्छा प्रदर्शन किया?

विश्लेषण से सरकार को जवाबदेह बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरण के उपयोग में एनडीए और यूपीए के बीच मतभेद का पता चलता है

युगांक गोयल और श्रेयस रामकुमार

क्रमशः, फ्लेम यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर नॉलेज अल्टरनेटिव्स के एसोसिएट प्रोफेसर और संस्थापक-निदेशक और फ्लेम यूनिवर्सिटी में एक छात्र हैं।

सवाल करने का अधिकार

विपक्ष में, भाजपा (और एनडीए) ने सत्तारूढ़ कांग्रेस (और) से अधिक लोकसभा प्रश्न पूछे यूपीए) ने 2014 के सत्ता परिवर्तन के बाद 10 वर्षों में जितना पूछा था, हालाँकि सांसदों के अनुपात में प्रश्नों पर पैमाना दूसरी तरफ झुका हुआ है

लोकसभा	विपक्ष के प्रश्नों का प्रतिशत	विरोध
14	67	एनडीए एट अल
15	63	एनडीए एट अल
16	31	यूपीए एट अल
17	51	यूपीए एट अल

लोकसभा	दल	सीटें	प्रशन	प्रति सीट प्रश्न
14	बी जे पी	138	647	4.69
15	बी जे पी	116	570	4.91
16	कांग्रेस	44	276	6.27
17	कांग्रेस	52	368	7.08
14	माकपा	43	210	4.88
16	माकपा	9	70	7.78
17	माकपा	3	23	7.67
14	सपा	36	127	3.53
15	सपा	23	72	3.13
16	सपा	5	24	4.80
17	सपा	5	1	0.20

mint

स्रोत: लेखकों का शोध, लोकसभा डेटा

सतीश कुमार/मिंट

प्रश्नकाल (QH) एक शक्तिशाली है

कार्यपालिका पर सवाल उठाने का उपकरण विधायिका के हाथ में है। भारत में, प्रत्येक लोकसभा सत्र सुबह 11 बजे की घोषणा के साथ शुरू होता है, जिसमें सांसद विभिन्न नीतिगत मामलों पर उत्तर देने के लिए विभिन्न मंत्रियों के सामने कई प्रकार के प्रश्न रखते हैं। प्रश्नों को लगभग दो सप्ताह पहले देना होगा, ताकि जवाब देने वाले मंत्रियों के पास अपने उत्तर तैयार करने के लिए पर्याप्त समय हो। इस घंटे टेलीविज़न दिखाने का मतलब महत्वपूर्ण चुनावी लाभ और हानि भी हो सकता है। बड़ी मात्रा में नीति और राजनीतिक जानकारी उत्पन्न होने के बावजूद, QH बहुत अधिक विद्वानों या डेटा-संचालित मीडिया जांच के अधीन नहीं रहा है।

जैसे-जैसे देश अगली लोकसभा के लिए आम चुनावों के करीब पहुंच रहा है, हमने पिछले चार लोकसभा कार्यकाल के दौरान पूछे गए सभी 'तारांकित' (मौखिक) प्रश्नों के डेटा का पता लगाना और अंतर्निहित पैटर्न की तलाश करना प्रासंगिक समझा। जहाँ तक QH कार्यपालिका की विधायी पूछताछ को दर्शाता है, इस तरह के विश्लेषण से पार्टी के स्वभाव का पता चल सकता है और मंत्रालयों में प्रश्न कैसे वितरित किए जाते हैं।

ध्यान दें कि QH का उपयोग न केवल विपक्ष, बल्कि सत्तारूढ़ दल भी करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाद वाला इसे अपनी ताकत को उजागर करने के अवसर के रूप में उपयोग कर सकता है। हालाँकि, लोकतांत्रिक आदर्शों को आगे बढ़ाने में QH का सार निकालने के लिए, हम विपक्षी दलों और सदस्यों के सवालों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

हम केवल अनूठे प्रश्नों को देखते हैं - वे जो केवल एक सदस्य द्वारा पूछे जाते हैं और गैर-पूरक होते हैं।
ये सभी मौखिक प्रश्नों का 80% से अधिक हिस्सा हैं।
दिलचस्प पैटर्न सामने आते हैं. पिछली चार लोकसभाओं में, QH के दौरान लगभग 10,000 प्रश्न पूछे गए: क्रमशः 2,466, 2,059, 2,864 और 2,347, जिनमें से विपक्षी दलों ने 67%, 63%, 31% और 51% पूछे। स्पष्ट रूप से, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की तुलना में अधिक 'स्पष्ट' विपक्ष था। विशेष रूप से, एनडीए का नेतृत्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2004-14 के दशक के दौरान 1,217 प्रश्न पूछे थे, जब यूपीए केंद्र में सत्ता में थी। यूपीए नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ने 2014-24 के दौरान केवल 644 प्रश्न पूछे, जिस अवधि में वर्तमान भाजपा सरकार सत्ता में रही है। लेकिन यह लोकसभा में उनकी अपनी-अपनी ताकत को प्रतिबिंबित कर सकता है। 2004 से 2014 के दौरान बीजेपी के पास औसतन 127 सीटें थीं, जबकि 2014 से 2024 के दौरान कांग्रेस का औसत सिर्फ 52 था।

इसलिए, विपक्ष की प्रभावी ढंग से जांच करने के लिए-
भूमिका में, हमें विपक्ष की कुल सीटों के लिए समायोजन करने की आवश्यकता है, और भाजपा-कांग्रेस प्रतिद्वंद्विता से परे भी जाना होगा। प्रश्न-प्रति-सीट गणना से यह पता चलता है कि प्रश्न पूछने के संदर्भ में विपक्ष कितना प्रभावी रहा है। से

आंकड़ों से साफ है कि विपक्ष सबसे कमजोर था 2014-19, जब उसके प्रश्नों का हिस्सा उसकी सीटों के हिस्से से कम था (उसकी प्रति सीट प्रश्न 0.815 थी)। इस उपाय ने 2004-09 और 2009-14 के दौरान क्रमशः 1.15 और 1.21 का मान लिया, और 2019-24 में 1.37, जो नवीनतम लोकसभा में मजबूत विरोध का संकेत देता है। हालाँकि, ध्यान दें कि संसद सदस्य (सांसद) को मंच देने का निर्णय काफी हद तक सदन के अध्यक्ष पर निर्भर करता है।

हम प्रत्येक पार्टी के लिए इसका विश्लेषण कर सकते हैं। पार्टी के आकार को समायोजित करते हुए, हम एक पार्टी से 'प्रति सांसद प्रश्नों' की संख्या को देखते हैं, यह देखने के लिए कि विपक्ष में रहते हुए प्रत्येक पार्टी ने QH के दौरान कैसा प्रदर्शन किया। उपरोक्त ग्राफ़ शिक्षाप्रद है। उदाहरण के लिए, 2014-24 में कांग्रेस की तुलना में 2004-14 के दौरान भाजपा एक 'शांत' विपक्ष थी।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) 'सबसे मुखर' थी और पिछले कुछ वर्षों में इसकी पूछपरख बढ़ी है। 2004-09 में QH के दौरान तेलुगु देशम पार्टी और शिव सेना बहुत मजबूत थीं, लेकिन अगली लोकसभा में उनकी पूछ कमजोर हो गई (भले ही वे समग्र रूप से मजबूत रहीं)। बीजू जनता दल ने एक विपक्षी दल के रूप में लगातार भूमिका निभाई है, हालांकि बाद की लोकसभाओं के दौरान यह शांत भी हो गई है। 2014-19 में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाली समाजवादी पार्टी 2019-24 में इस मोर्चे पर फिसड्डी नजर आ रही है.

चूंकि विपक्षी दल विशिष्ट मंत्रालयों की जांच के लिए क्यूएच का उपयोग करते हैं, इसलिए डेटा से यह भी पता चलता है कि इनमें से किसे सबसे अधिक विरोध क्यूएच प्रश्नों का सामना करना पड़ा।

शीघ्र पढ़ें

जिस दशक में कांग्रेस सत्ता में थी, उस दौरान भाजपा ने 1,217 प्रश्नकाल प्रश्न पूछे, जबकि कांग्रेस ने 2014 से 2024 तक 644 प्रश्न पूछे, हालांकि लोकसभा में उसकी सीटें भी बहुत कम थीं।

जिन मंत्रालयों को संसद में सबसे अधिक जांच के दायरे में रखा गया था, उनमें 2014 में भाजपा के सत्ता हासिल करने के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया। यह आंशिक रूप से देश के राजनीतिक फोकस में बदलती नीतियों को प्रतिबिंबित कर सकता है।

साथ ही उनमें से 'सबसे अधिक जांचे गए' लोगों पर निर्देशित प्रश्नों की हिस्सेदारी में रुझान। संख्याएँ बताती हैं कि एक विपक्षी गठबंधन के रूप में, एनडीए विशेष रूप से 2004-14 के सत्तारूढ़ यूपीए गठबंधन के तहत पेट्रोलियम क्षेत्र, मानव संसाधन विकास, कृषि और वाणिज्य और उद्योग के मंत्रालयों पर सवाल उठाने पर केंद्रित था।

दिलचस्प बात यह है कि जब 2014 में सत्ता बदली, तो सवालों की दिशा भी बदल गई, जो उसके बाद स्वास्थ्य, वित्त और ग्रामीण विकास से संबंधित मामलों पर अधिक केंद्रित हो गई। यह डेटा उन नीतियों की प्रकृति को भी प्रतिबिंबित करता है जो संबंधित सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा लागू की गई हो सकती हैं, और इसलिए यह राष्ट्रीय स्तर पर बदलते नीति परिदृश्य का एक उपयोगी संकेत है।

राज्य-स्तरीय विधान सभाओं को शामिल करने के लिए इस शोध का विस्तार करने और शायद प्रतिनिधित्व के राज्य सदनों के भीतर किसी पार्टी के विपक्ष के प्रदर्शन का अनुमान लगाने के लिए एक मीट्रिक बनाने का एक सम्मोहक मामला है।

लोकसभा के क्यूएच पर अनुसंधान, हालांकि अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है, राष्ट्रीय संदर्भ में महत्वपूर्ण महत्व रखता है। यह सूचित करता है

कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने और मंत्रालयों को नियंत्रण में रखने के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरण का उपयोग करने में प्रतिनिधियों ने जो भूमिका निभाई है। लोगों की ओर से उठाए गए प्रश्न कानून के कार्य को गतिशीलता प्रदान करते हैं, जो नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि क्यूएच शोध से पार्टियों की संवेदनशीलता बढ़ेगी कि मतदाता उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं।

टकसाल क्यूरेटर

चार-दिवसीय कार्य सप्ताह दशकों तक क्षितिज पर नहीं रहेगा

इसे हानिरहित तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है लेकिन इसे सक्षम करने के लिए बाज़ार विकसित हो सकते हैं

एलिसन श्रेजर

अर्थशास्त्र को कवर करने वाले ब्लूमबर्ग ओपिनियन स्तंभकार हैं।

कीन्स ने भविष्य में बेहतर कार्य-जीवन संतुलन की भविष्यवाणी की थी गेटी इमेजेज

सभी लोग कम से कम एक बात पर सहमत हैं: वे अमेरिका के बी अरबपति और सीनेटर बर्नी सैंडर्स भविष्य में चार दिवसीय कार्य सप्ताह देखते हैं। हेज फंड मैनेजर स्टीव कोहेन गोल्फ कोर्स में निवेश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ख़ाली समय में बड़ी वृद्धि की उम्मीद है, और आईएसी के संस्थापक बैरी डिलर उम्मीद कर रहे हैं कि लोग सप्ताह में केवल चार दिन कार्यालय में रहेंगे। सैंडर्स ने कार्य सप्ताह को 32 घंटे करने के लिए कानून बनाने का भी प्रस्ताव रखा है।

मुझे संशयवादी के रूप में चिह्नित करें. कुछ बड़े तकनीकी-तार्किक नवाचार लोगों को अधिक उत्पादक बनाने का वादा करते हैं, लेकिन चार-दिवसीय कार्य सप्ताह जल्द ही आदर्श नहीं होगा।

और अगले चार वर्षों में इसे लागू करने वाला कानून अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा।
पहला प्रश्न यह है कि 'चार दिवसीय कार्य सप्ताह' का क्या अर्थ है। कभी-कभी इसका मतलब चार दिनों में पांच के बजाय 40 घंटे काम करना होता है, हालांकि यह कम कुशल होता है।

या इसका मतलब सप्ताह में चार दिन आठ घंटे काम करना हो सकता है, जो सैंडर्स के मन में है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और अन्य जगहों पर दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं अधिक आम हो गई हैं - हालांकि अधिकांश वृद्धि उन लोगों में है जो 40 घंटे से कम काम करते हैं।

जहां तक विचार की खूबियों का सवाल है: छोटे कार्य सप्ताह के लिए मूल रूप से दो तर्क हैं। कोई यह मानता है कि लोग काम पर इतना समय बर्बाद करते हैं कि यदि वे समय का अधिक कुशलता से उपयोग करते हैं तो 20% कम काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ छोटे अध्ययन, मुख्य रूप से गैर-ग्राहक-सामना वाली सेवा नौकरियों में, यह पाया गया है कि घंटों में 20% की गिरावट के परिणामस्वरूप राजस्व में गिरावट नहीं होती है।

लेकिन क्या यह निष्कर्ष अधिक श्रम-गहन नौकरियों पर लागू होता है, यह संदिग्ध है। एकमात्र बड़ा प्रयोग फ़्रांस से आया है, जिसने 1998 में बड़ी कंपनियों पर 35 घंटे का कार्य सप्ताह इस उम्मीद से लगाया था कि इससे रोज़गार बढ़ेगा। अध्ययनों से पता चलता है कि इससे रोज़गार या ख़ुशी नहीं बढ़ी और बाद में फ़्रांस ने इसे निरस्त करने का प्रयास किया।

सैंडर्स का प्रस्ताव कई मायनों में फ्रांसीसी कानून से भी बदतर है। उस कानून की तरह, यह लोगों को कम घंटे काम करने के लिए मजबूर नहीं करता है।
इसके बजाय, यह उस सीमा को कम कर देता है जिस पर ओवरटाइम वेतन मिलता है। सैंडर्स बिल यह भी निर्धारित करता है कि यदि लोग कम घंटे काम करते हैं तो नियोक्ता वेतन कम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ श्रमिकों के लिए, यह 20% वेतन वृद्धि के समान होगा एक घंटे के आधार पर.

यह अर्थव्यवस्था पर थोपा जाने वाला एक उल्लेखनीय बोझ है (हालाँकि कुछ श्रमिकों को छूट दी जाएगी)। शायद कुछ बहुत लाभदायक कंपनियाँ इतनी बड़ी वेतन वृद्धि को समायोजित करने में सक्षम होंगी। अधिवक्ता इस बात पर जोर देते हैं कि लोग इतने खुश और उत्पादक होंगे कि कंपनियों को कोई अंतर नज़र नहीं आएगा। लेकिन केवल अधिक खुश रहने और अधिक व्यस्त रहने से उत्पादकता में 20% की वृद्धि होती है?

और कई कंपनियों के लिए - विनिर्माण में, मान लीजिए, या ऐसे उद्योगों में जहां फेस टाइम आवश्यक है - उच्च मनोबल से उत्पादकता लाभ अधिक सीमित हैं।

श्रम-समय-गहन नौकरियाँ भी कम मार्जिन वाली कंपनियों में होती हैं।
जब लगभग एक दशक पहले आइसलैंड ने अपनी आबादी के 1% के लिए कार्य सप्ताह में केवल कुछ घंटे कम कर दिए, तो आइसलैंड सरकार को अधिक लोगों को काम पर रखना पड़ा, जिससे श्रम लागत बढ़ गई। 20% वेतन वृद्धि कई निजी कंपनियों को या तो बंद करने, कीमतें बढ़ाने या कर्मचारियों को प्रौद्योगिकी से बदलने के लिए मजबूर कर देगी।

सैंडर्स बिल से होने वाले लाभ से ज्यादातर पहले से ही उत्पादक कंपनियों में उच्च-कौशल और अच्छी तनख्वाह वाले श्रमिकों को लाभ होगा।

इसके अलावा, कम घंटे लगाना आवश्यक नहीं हो सकता है। अमेरिका में 1938 से 40 घंटे का कार्य सप्ताह पूर्णकालिक मानक रहा है, लेकिन बड़े विधायी परिवर्तनों के बिना भी, काम के घंटों में गिरावट आई है क्योंकि प्रौद्योगिकी और धन ने विकसित दुनिया में कई लोगों के लिए कार्य सप्ताह को छोटा कर दिया है। . यह मानने के कई कारण हैं कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी।

छोटे कार्य सप्ताह के लिए दूसरा-कुछ हद तक संबंधित-तर्क यह है कि तकनीक-विज्ञान लोगों को अधिक उत्पादक बनाता है, जिससे वे कम काम करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए, 1930 में, जॉन मेनार्ड कीन्स ने 15 घंटे के कार्य सप्ताह की कल्पना की थी।

वह बात नहीं बनी. लेकिन कीन्स पूरी तरह से गलत नहीं थे: लोग उनके समय की तुलना में कम घंटे काम कर रहे हैं। उस समय, कम वेतन वाले कर्मचारी अधिक काम करते थे।

आज, अधिक कमाई करने वाले ऐसा करते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि लोग कम काम करें। मायने यह रखता है कि प्रौद्योगिकी उनके काम को किस प्रकार प्रभावित करती है।
पिछले 50 वर्षों में, प्रौद्योगिकी ने उच्च-कौशल वाले श्रमिकों को लाभ पहुंचाया है, इसलिए अधिक काम करने से उन्हें अधिक लाभ हुआ है।

अब तकनीक सफेदपोश श्रमिकों के लिए घर से काम (डब्ल्यूएफएच) और अधिक लचीलेपन की अनुमति देती है। यह संभवतः अधिक अंशकालिक काम और अधिक कमाई करने वालों के लिए कम घंटे सक्षम करेगा, और शायद कम काम करने वाले सभी लोगों के प्रति एक अभिसरण होगा।

हालाँकि, कुल मिलाकर, जब आर्थिक मामलों की बात आती है, तो मुझे बर्नी सैंडर्स की तुलना में जॉन मेनार्ड कीन्स पर अधिक भरोसा है।

मेरा मतलब यह है कि भविष्य में हम सभी संभवतः कम घंटे काम करेंगे।

लेकिन 32 घंटे के कार्य सप्ताह को मानक बनाने में कई दशक लगेंगे और समय से पहले जबरन इसमें शामिल होने से बहुत से लोगों की स्थिति और खराब हो जाएगी।

©ब्लूमबर्ग

मेरा दृष्टिकोण | पेन ड्राइव

पूर्ण रिटर्न के लिए निवेश करना निवेशकों को मुक्त कर सकता है

स्वानंद केलकर

ब्रेकआउट कैपिटल में मैनेजिंग पार्टनर है।

मैं एक बार अपने फंड के लिए एक स्टॉक पेश कर रहा था मैं एक निवेश विश्लेषक के रूप में अपने शुरुआती दिनों में, मैनेजर बॉस. पिच के दो मिनट बाद उन्होंने मुझसे पूछा, "वजन क्या है?" मुझे नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रहे थे और इसलिए मैंने बाद में अपने एक वरिष्ठ सहकर्मी से पूछा कि उनका क्या मतलब है। भारत में अधिकांश संस्थागत निवेश सापेक्ष रिटर्न प्रकार के होते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक फंड को एक सूचकांक के खिलाफ बेंचमार्क किया जाता है और एक फंड मैनेजर की क्षमता या अन्यथा यह मापा जाता है कि वह बेंचमार्क के खिलाफ कितना अच्छा प्रदर्शन करता है। इसलिए निवेश चर्चाओं में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न वही है जो मेरे बॉस ने मुझसे पूछा था। इसका मतलब था: बेंचमार्क इंडेक्स में स्टॉक कितना बड़ा है?

बाय-साइडर बनने से पहले, मैं एक शौकिया इक्विटी निवेशक था, और वजन का यह सवाल मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था। जो पसंद आया उसे खरीदा और जो पसंद नहीं आया उसे नहीं खरीदा। लेकिन जैसे-जैसे मैं संस्थागत निवेश की दुनिया में डूबता गया, 'इंडेक्स वेट' शब्द कई लोगों का केंद्र बन गया

पोर्टफोलियो चर्चा. जब आपको किसी बेंचमार्क को मात देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो आप तुरंत निवेश के इस नए तरीके को अपना लेते हैं।
इस बदलाव के कई निहितार्थ हैं. किसी को हैवीवेट का विश्लेषण करने में बहुत समय खर्च करना पड़ता है: यानी, ऐसे स्टॉक जिनका सूचकांक में बड़ा प्रतिनिधित्व होता है। हो सकता है कि वे स्टॉक पैसे कमाने के लिए सबसे अच्छे विचार न हों, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल फंड के सापेक्ष प्रदर्शन, आपके वार्षिक बोनस और यहां तक कि आपके करियर पर भी असर डालेगा। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस और लार्सन एंड टुब्रो भारत के पांच सबसे बड़े स्टॉक हैं, जो वजन के हिसाब से निफ्टी 100 इंडेक्स का लगभग एक तिहाई हिस्सा हैं, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे सबसे अच्छे कवर किए गए शेयरों में से कुछ हैं। इक्विटी रिसर्च हाउस द्वारा. फिर, इसलिए नहीं कि बेचने वाले पक्ष को लगता है कि ये सर्वोत्तम निवेश विचार हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि उनके बड़े ग्राहक उनकी बहुत परवाह करते हैं।

'सूचकांक भार' के अलावा, मेरे निवेश शब्दकोष में शामिल अन्य शब्द 'अधिक वजन' और 'कम वजन' थे। यदि किसी स्टॉक का सूचकांक भार 3% है और यह आपके फंड का 5% है, तो आप 2% अधिक वजन वाले हैं। इसी तरह, यदि यह इसका केवल 2% है, तो आपका वजन 1% कम है।

ईमानदारी से कहूं तो, मुझे 'कम वजन' की अवधारणा को समझने में संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि इससे पता चलता था कि फंड मैनेजर को स्टॉक पसंद नहीं है।

और फिर भी इसे धारण करता है। बाय साइड मार्केटिंग मशीनरी वेटेज को सही ठहराने के लिए 'फंड मैनेजर सावधानीपूर्वक आशावादी है' के कुछ संस्करण को स्पिन करेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी स्थिति जोखिम प्रबंधन स्थान-धारक हैं। यदि, किसी भी कारण से, स्टॉक अच्छा प्रदर्शन करता है, तो फंड मैनेजर सूचकांक में पिछड़ना नहीं चाहता है और इसलिए इसमें कुछ पूंजी आवंटित करता है। यह जांचना सार्थक हो सकता है कि आपके फंड पोर्टफोलियो के किस अनुपात में कम वजन वाले नाम शामिल हैं क्योंकि यह धन आवंटित करने का एक उप-इष्टतम तरीका है।

सापेक्ष रिटर्न ढांचे का दूसरा परिणाम यह है कि पोर्ट-फ़ोलियो बेंचमार्क से चिपके रहते हैं। भारत में 12 सबसे बड़े लार्ज-कैप फंड, जो प्रबंधन के तहत लार्ज-कैप परिसंपत्तियों का 90% से अधिक हिस्सा रखते हैं, सभी पांच इंडेक्स हेवीवेट के मालिक हैं।

भारत के बारह शीर्ष निवेश पेशेवरों का एक जैसा विचार रखना आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन प्रोत्साहन संरचना को देखते हुए ऐसा नहीं है।

शीघ्र पढ़ें

इंडेक्स के प्रदर्शन में गिरावट के साथ सापेक्ष रिटर्न का पीछा करने से फंड प्रबंधकों को बड़े-कैप शेयरों से बंधे रखा जाता है, केवल इन पर या तो कम या अधिक वजन रखने की छूट होती है।

यदि विशिष्ट वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करना है, तो हमें पूर्ण रिटर्न का लक्ष्य रखना चाहिए, और यह परिसंपत्ति प्रबंधकों को इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता देता है कि उनकी निवेश क्षमता के क्षेत्र में क्या है।

खुदरा निवेशकों की प्रेरणा जो फंड मैनेजरों को अपना पैसा सौंपते हैं, मुद्रास्फीति को मात देना है। संस्थागत निवेशकों के लिए, इसे वेतन और पेंशन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने, या किसी शैक्षणिक संस्थान, शहर या यहां तक कि देश की स्थिरता और विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जा सकता है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक पूर्ण-ल्यूट-रिटर्न बाधा की आवश्यकता होती है। सेवानिवृत्त लोगों को यह नहीं बताया जा सकता है कि उनकी पेंशन 10% कम होने वाली है क्योंकि जिस बेंचमार्क के आधार पर फंड को मापा जा रहा था वह 10% नीचे है।

निवेशक और धन प्रबंधक के अंतिम लक्ष्यों को संरेखित करने के अलावा, पूर्ण-वापसी निवेश के अन्य फायदे भी हैं। निवेश पेशेवरों का कुशल समय आवंटन सबसे महत्वपूर्ण है। एक निवेशक किन शेयरों और क्षेत्रों का विश्लेषण करने का निर्णय लेता है, यह सूचकांक की संरचना से तय नहीं होता है, बल्कि पूर्ण रिटर्न देने की संभावना से तय होता है।

इसके अलावा, यह निवेशकों को उनकी क्षमता के दायरे में रहने और अन्य शेयरों, क्षेत्रों और बाजारों को 'बहुत कठिन' ढेर में धकेलने की अनुमति देता है।

हालाँकि, पूर्ण-वापसी मानसिकता के लिए दृष्टिकोण में कुछ संशोधन की आवश्यकता होती है।
वॉरेन बफेट की "पैसा कभी न खोने" की सलाह सर्वोपरि हो जाती है, जिसका अर्थ है कि एक पूर्ण-रिटर्न निवेशक नकारात्मक जोखिमों के बारे में बहुत कुछ सोचता है। इनमें वे जोखिम शामिल हैं जिन्हें हम स्ट्रोक-ऑफ-द-पेन जोखिम कहते हैं, जैसे अचानक नियामक परिवर्तन, दंडात्मक कार्रवाई या किसी प्रमुख कर्मचारी के अचानक चले जाने का जोखिम। एक प्रभावी पूर्ण-रिटर्न रणनीति के लिए समय-समय पर स्टॉक या संपूर्ण पोर्टफोलियो को हेज करने की क्षमता की आवश्यकता होती है क्योंकि अल्पकालिक बाजार में गिरावट अपरिहार्य है, और एक पूर्ण-रिटर्न प्रबंधक नकारात्मक सूचकांक रिटर्न के बहाने के पीछे छिप नहीं सकता है।

सापेक्ष और पूर्ण रिटर्न दृष्टिकोण के बीच यह अंतर भारत में ज्यादा मायने नहीं रखता, जहां मजबूत सूचकांक रिटर्न का एक लंबा इतिहास है। लेकिन उभरते बाजारों की इक्विटी जैसे परिसंपत्ति वर्ग के लिए, जहां पिछले पांच और 10 वर्षों में वार्षिक कुल डॉलर रिटर्न क्रमशः 2% और 3% से कम रहा है, सापेक्ष-रिटर्न मानसिकता को त्यागना संभवतः सम्मानजनक रूप से उत्पन्न करने का एकमात्र तरीका है। बड़े रिटर्न.

Machine Translated by Google

बिना फूलों वाले ग्रह के लोग सोचेंगे कि हमें पूरे समय खुशी से पागल रहना चाहिए

मर्डोक

इंडियन एक्सप्रेस कोई उद्योग नहीं है. यह एक मिशन है.

-रामनाथ गोयनका

डीएमके कड़ी मेहनत कर रही है की पुनरावृत्ति से बचने के लिए 2011 की क्रूर गर्मी

HE पावर सेक्टर लगातार बुरे सपने दे रहा है

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके. 2011 में जब पार्टी को AIAD के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा एमके, राज्य भर में लगातार बिजली कटौती को जिम्मेदार ठहराया गया प्रमुख कारणों में से एक के रूप में। औद्योगिक राज्य, जो हमेशा बिजली की कमी से जूझता रहा है, ने भारी कर्ज का बोझ उठाते हुए किसी तरह से काम चलाया।

लेकिन 2011 की क्रूर गर्मी में, तीन घंटे तक की निर्धारित बिजली कटौती और चुनावी मौसम के दौरान लगातार अनिर्धारित कटौती ने डीएमके के भाग्य को सील कर दिया। जबकि कई दिग्गज हार गए, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कोलाथुर से 2,800 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल की।

ये गर्मी भी बेहाल है. लेकिन सत्तारूढ़ डीएमके कोई कसर नहीं छोड़ रही है. टैंगेडको, घाटे में चल रही राज्य बिजली उपयोगिता, के पास अपनी झोली में कोई बड़ा छेद किए बिना स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने का अविश्वसनीय कार्य है। राज्य ने स्पष्ट रूप से पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में जल-विद्युत उत्पादन में 50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। राज्य के स्वामित्व वाले जलविद्युत संयंत्रों ने 2023-24 में 3,000 मिलियन यूनिट से थोड़ा अधिक उत्पादन किया, जो सात वर्षों में सबसे कम उत्पादन है। कर्नाटक से पानी की कमी और पश्चिमी जिलों में, जहां अधिकांश जलविद्युत संयंत्र स्थित हैं, कम वर्षा ने गड़बड़ी पैदा कर दी है। टैंगेडको के लिए, जो ऋण पर प्रति वर्ष `13,000 करोड़ से अधिक ब्याज का भुगतान करता है, उत्पादन में गिरावट वास्तव में महत्वपूर्ण है।

जब से मांग बढ़ी है, कंपनी राज्य के बाहर से बिजली लेने के लिए संघर्ष कर रही है। मांग में और बढ़ोतरी की उम्मीद में, उपयोगिता ने मई तक लगभग 4,500 मेगावाट की खरीद के लिए निजी खिलाड़ियों के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फरवरी और मई के बीच के चार महीनों में, टैंगेडको की बिजली खरीद लागत `4,600 करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान खर्च किए गए `2,400 करोड़ से लगभग दोगुना है।

जबकि टैंगेडको ने अभी तक खातों को अंतिम रूप नहीं दिया है, 2023-24 के लिए इसकी बिजली खरीद लागत `65,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। आने वाले हफ्तों में बिजली की खपत केवल एक ही तरीके से बढ़ेगी, संभवतः कंपनी को इस वित्तीय वर्ष में और भी अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दो साल के अंतराल के बाद सुरक्षा जमा एकत्र करने की प्रथा को फिर से शुरू करने का कदम राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन टैन-जेडको के पास बहुत अधिक विकल्प नहीं हो सकते हैं।

आंध्र पक्ष का चेहरा हताश कैडर

जन सेना और बीजेपी के सामने असली समस्या है. आंध्र प्रदेश के विधानसभा और लोक में जाने के साथ लोकसभा चुनाव एक साथ, दांव बहुत ऊंचे- वह सत्तारूढ़ वाईएसआरसी और टीडीपी के विपक्षी गठबंधन। एक हर किसी के लिए. टीडीपी और जन सेना के भाजपा के साथ साझेदारी के पीछे का तर्क सही है- वे अपने अभियान में अतिरिक्त उत्साह जोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता चाहते हैं। लेकिन कोई भी रणनीति तभी सफल कही जा सकती है जब वह जमीन पर काम करे. सीट-बंटवारे की घोषणा के बाद से जो कुछ सामने आ रहा है, उसे देखते हुए, वोट-बंटवारे को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ करना होगा।

बड़ी संख्या में जन सेना और भाजपा नेता और कैडर उन्हें आवंटित की गई 31 विधानसभा और आठ लोकसभा सीटों से नाखुश हैं। कई भगवा नेता इस बात पर खफा हैं कि पार्टी जिन छह लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनमें से काफी सीटें टीडीपी से आए लोगों को दी गई हैं। ऐसी ही शिकायत है जनसेना की.

तेलंगाना के विपरीत, जहां उनके समकक्ष सक्रिय हैं, राज्य के प्रमुख भाजपा नेता सक्रिय नहीं हैं। निजी तौर पर, कई लोग स्वीकार करते हैं कि उनकी पार्टी नेतृत्व ने सौदेबाजी में कमज़ोर प्रदर्शन किया है।

जन सेना के मामले में, कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी है और बचे हुए कई लोग टीडीपी द्वारा 'छोटा बदलाव' किए जाने से नाराज हैं। जब टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू सलाखों के पीछे थे, तब पवन कल्याण अधिक मजबूत दिखाई दिए, लेकिन फिर उन्होंने वह किया, जिसे उनके सहयोगी एक बड़ी गलती बताते हैं - वह सीट-बंटवारे पर बातचीत किए बिना, जेल के बाहर ही गठबंधन के लिए सहमत हो गए। चोट पर नमक छिड़कते हुए, सीटों की अनुमानित संख्या कम से कम 40 से घटकर मात्र 21 रह गई। यहां तक कि पवन को खुद को जीतने में मदद करने के लिए एक टीडीपी नेता को मनाना पड़ा, इसे एक सुपरस्टार के लिए एक बड़ी गिरावट के रूप में देखा जाता है।

वाईएसआरसी के लिए समस्या अलग तरह की है. मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी अपनी पार्टी कैडर के बजाय उन 2.6 लाख स्वयंसेवकों की सद्भावना पर भारी भरोसा कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने योजनाओं के सुचारू वितरण के लिए भर्ती किया था। वाईएसआरसी के कई नेता इस बात से नाखुश हैं कि जिस तरह से स्वयंसेवक प्रणाली ने उनका दबदबा कम किया है। ग्राउंड रिपोर्ट से पता चलता है कि उनका कैडर टीडीपी कार्यकर्ताओं जितना सक्रिय नहीं है। दोनों पक्ष इन मुद्दों से कैसे निपटते हैं, इसका चुनाव के नतीजों पर असर पड़ेगा।

जल्दी करो

दिमाग और संसाधनों का मेल

अमेरिका और जापान ने तेजी लाने के लिए साझेदारी की घोषणा की है- वैज्ञानिक कार्बन मुक्त बिजली प्रदान करने के लिए संलयन, एक प्रकार की परमाणु प्रतिक्रिया जो सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती है, का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब, दुनिया की कुछ अनुसंधान शक्तियाँ इसे संभव बनाने के लिए प्रयास करेंगी। भारत के लिए दो सबक हैं.

हमें खतरनाक विखंडन पर बहुत अधिक दांव लगाने से पहले संलयन के लाभों पर ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हम 2032 तक 18 और रिएक्टर बनाने की योजना बना रहे हैं। और हम सीमा पार विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और निजी फर्मों को एक साथ रखने के सहयोगी मॉडल से सीख सकते हैं। गेम-चेंजिंग समाधान प्रदान करें।

यूरोप में भारतीय मूल के तीन प्रधानमंत्रियों के साथ शुरू हुआ साल किसी के साथ खत्म होने की संभावना नहीं है। शायद यह कुछ काल्पनिक परिदृश्यों में शामिल होने का समय है

बिना नेता सीमाएँ: विचार किसका शायद समय आ गया है

शशि थरूर

तिरुवनंतपुरम से तीसरी बार लोकसभा सांसद और साहित्य अकादमी विजेता, 24 पुस्तकों के लेखक, हाल ही में अम्बेडकर: एक जीवन

टी

हाल ही में पोर्टु-गैल के प्रधान मंत्री एंटोनियो कोस्टा का इस्तीफा, 'गोवा मूल के प्रधान मंत्री के इस्तीफे' की तर्ज पर भारत में कई अपमानजनक सुर्खियों में रहा। कोस्टा की उत्पत्ति हमारे तटीय राज्य गोवा में हुई - हमारे लिए एक पूर्व, और प्रवासी भारतीय सम्मान के प्राप्तकर्ता, यूरोपीय सरकार के पहले भारतीय प्रमुख होने के लिए भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए सर्वोच्च भारतीय सम्मान। अब वह चला गया था.

इस दुखद समाचार के बाद एक भारतीय आप्रवासी के बेटे, 45 वर्षीय लियो वराडकर ने, "व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों से" आयरलैंड के प्रधान मंत्री के रूप में चौंकाने वाला इस्तीफा दे दिया।

जब वराडकर, जो उस समय केवल 38 वर्ष के थे, 2017 में आयरलैंड के प्रधान मंत्री बने, तो भारत में इसका इस तरह स्वागत किया गया जैसे कि यह किसी प्रकार की राष्ट्रीय विजय का प्रतीक हो।

"देखो- हमारा एक लड़का उनका नेता बन गया है," एक मुंबईकर मित्र ने बड़े गर्व के साथ मुझसे कहा। मैं इतना असभ्य था कि मैंने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने उसी आधार पर भारत के प्रधान मंत्री के रूप में सोनिया गांधी के चुनाव का विरोध किया था, जिस आधार पर वे वराडकर की नियुक्ति की सराहना कर रहे थे। "यह अलग है," उसने अपने चेहरे पर निराशा भरे भाव के साथ विषय बदलने से पहले, लापरवाही से उत्तर दिया।

हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री के रूप में ऋषि सुनक के उदय का भारत में व्यापक रूप से जश्न मनाया गया है, यहां तक कि उन लोगों द्वारा भी जो राजनीति के उनके रूढ़िवादी ब्रांड को साझा नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ भी, इस वर्ष की दूसरी छमाही में चुनाव होने की व्यापक रूप से उम्मीद है, और कम से कम चुनावों को देखते हुए, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में उनका कार्यकाल समाप्त होने की संभावना है।

यूरोप में भारतीय मूल के तीन प्रमुख प्रधानमंत्रियों के साथ शुरू हुआ साल किसी के साथ खत्म होने की संभावना नहीं है।

अधिकांश भारतीयों को अफसोस की भावना का अनुभव होगा। वराडकर ने शीर्ष पर पहुंचने के लिए असंभव बाधाओं को पार कर लिया। एक पीढ़ी पहले, उन्हें बहुत युवा, बहुत "अलग" (वह समलैंगिक है) और पश्चिमी लोकतंत्र का नेतृत्व करने की इच्छा रखने के लिए बहुत भूरे रंग के रूप में देखा जाता था। उनके नाम ने भी उन्हें विदेशी के रूप में चिह्नित किया। और फिर भी उनकी जीत से पता चला कि दुनिया उन प्रकार के पूर्वाग्रहों से कितना आगे बढ़ चुकी है, जबकि अन्य प्रवृत्तियों से पता चलता है कि ज़ेनोफ़ोबिया बढ़ रहा था।

और फिर भी, आख़िरकार, क्या यह दुनिया में इतना नया विकास था? आयरिश गणराज्य के संस्थापक प्रमुख पुर्तगाली मूल के व्यक्ति इमोन दा वलेरा थे। और यूरोप में, जहां फ्रांस में वह दुर्लभ था, दुर्लभ था

सौरव रॉय

19वीं शताब्दी में एक राष्ट्रपति का नाम मैकमोहन था, और दूसरे का नाम सरकोजी था, जो हाल ही में हंगेरियन काउंट का बेटा था। दरअसल, यूरोप में राष्ट्रीय पहचान लंबे समय से अस्थिर रही है-

अंग्रेजी राजाओं का वर्तमान राजवंश जर्मनी से और स्वीडिश राजवंश फ्रांस से आया था।

फ्रांसीसियों और जर्मनों ने सदियों से एक-दूसरे के साथ अनगिनत युद्ध लड़े हैं, लेकिन एक दशक पहले ही फ्रांसीसियों के पास एक वित्त मंत्री था जिसका नाम जर्मन नाम स्ट्रॉस-कान था, जबकि उनके जर्मन समकक्ष का फ्रांसीसी नाम लाफोंटेन था।

बराक हुसैन का चुनाव 2008 में ओबामा - एक केन्याई आप्रवासी का बेटा, जिसे उसने ख़ुशी-ख़ुशी स्वीकार किया था, वह एक "मजाकिया नाम" था, साथ ही साथ एक मुस्लिम मध्य नाम - अमेरिकी-इकॉनिक व्यापकता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आख़िरकार, टोक्यो में एक गैर-जापानी प्रधान मंत्री या बीजिंग में एक गैर-चीनी की कल्पना करना असंभव था। और फिर भी अमेरिका शायद ही कोई वैश्विक अग्रणी था; आर्गेन-टीना ने एक सीरियाई अप्रवासी कार्लोस शाऊल मेनेम के बेटे को राष्ट्रपति के रूप में चुना था, और पेरू ने अल्बर्टो फुजीमोरी के साथ भी ऐसा ही किया था, जिनके माता-पिता जापानी थे, हालांकि दोनों ही अत्यधिक श्वेत-बहुल राष्ट्र हैं। जमैका में, एक लेबनानी आप्रवासी के बेटे एडवर्ड सीगा को उस देश में प्रधान मंत्री चुना गया, जहां 97 प्रतिशत लोग काले थे, जबकि जेनेट जगन, एक सफेद यहूदी अमेरिकी महिला, गुयाना की राष्ट्रपति बनीं, जिनकी आबादी पूरी तरह से काले या भारतीयों की है। .

तो वास्तव में, राजनीतिक प्रतिभाओं को राष्ट्रीय सीमाओं के पार क्यों नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए?

बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हर समय ऐसा करती हैं और हर कोई इसकी सराहना करता है।

भारतीयों को खुशी है कि सात प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नेतृत्व उन भारतीयों द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने विदेश में पैसा कमाने के लिए हमारा देश छोड़ा था।

मध्यकालीन राजाओं ने अपने योद्धाओं को वहां नियुक्त किया जहां वे कर सकते थे - भारतीय सेनाओं में, औपनिवेशिक युग से काफी पहले, तुर्क-ईश तोपखाने वाले, उज़्बेक घुड़सवार और फ्रांसीसी जनरलों थे, और किसी को भी यह अजीब नहीं लगा। अभी हाल ही में हमने अपने नेताओं से राष्ट्रीय पहचान की रूढ़िवादिता के अनुरूप होने की अपेक्षा की है।

लेकिन वह टूट सकता है. 2015 में, जॉर्जिया के निवर्तमान राष्ट्रपति (2004-2013), मिखाइल साकाश्विली को उनके देश के संविधान द्वारा तीसरे कार्यकाल से वंचित कर दिया गया था, उन्होंने फैसला किया कि जब वह अभी 50 वर्ष के नहीं थे, तब वह केवल सेवानिवृत्ति में ही नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने देशों को बदल दिया, यूक्रेनी नागरिकता अपना ली और ओब-लास्ट के गवर्नर का पद संभाला। (प्रांत) ओडेसा का। पहले साल सफल रहने के बाद, दूसरे साल में उन्हें परेशानी हुई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन वह अभी केवल 54 वर्ष के हैं, और शायद कोई यह सुझाव देना चाहेगा कि वह उदाहरण के लिए अगला प्रयास बिहार में करें।

जब लीबिया के दिवंगत तानाशाह मुअम्मर अल-गद्दाफी ने 1970 के दशक में मिस्र के साथ (संयुक्त अरब गणराज्य या यूएआर के नाम से) गठबंधन को बढ़ावा दिया, तो उन्होंने बिना सोचे-समझे कहा कि उनका विचार इस तथ्य से आया है कि मिस्र में लोग तो हैं लेकिन नहीं वास्तविक नेता, जबकि लीबिया के पास नेता तो थे लेकिन वास्तविक लोग नहीं थे।

मिस्र के अधिकारी स्वाभाविक रूप से इस तरह की धारणाओं पर विलय से पीछे हट गए, और यूएआर मृत अवस्था में ही मर गया।

लेकिन साकाश्विली ने जो मिसाल कायम की है, वह सिंगापुर के ली कुआन यू जैसे अधिक सहमति-सहयोगी सफल हस्तियों पर लागू हो सकती है, जिन्हें अपने छोटे शहर-राज्य की तुलना में बड़े देश में अपनी दृष्टि और आत्म-अनुशासन कभी लागू नहीं हुआ। भारतीय व्हाट्सएप ग्रुपों पर सिन-गपोर के प्रशंसकों की संख्या से पता चलता है कि उनका यहां कई लोगों ने स्वागत किया होगा।

आज तर्क और भी बेहतर काम करेगा. कल्पना कीजिए, मान लीजिए, बराक ओबामा, जो 53 साल की उम्र से बेरोजगार हैं, को ब्रिटेन को उसके विचित्र ब्रेक्सिट के आसपास की घिनौनी हरकतों के बाद चलाने के लिए भर्ती किया जाना था? या फिर चीन के उन डरावने टेक्नोक्रेट्स को, जो (अपने सर्वोच्च नेता, शी जिनपिंग के विपरीत) अपनी पार्टी के कठोर 10-वर्षीय शासन के कारण पद से सेवानिवृत्त होने के लिए बाध्य हैं, शायद पाकिस्तान को सुलझाने के लिए आमंत्रित किया गया था? संभावनाएँ मन को भ्रमित कर देती हैं।

(ये विचार निजी हैं)
(office@tharoor.in)

कप्तान को इसकी आवश्यकता क्यों है? रैंकों के साथ विनम्र रहें

आर गोपालकृष्णन

लेखक और व्यवसाय टिप्पणीकार; उनकी नई किताब है गले लगाओ भविष्य: कोमलका विज्ञान व्यापार परिवर्तन

भावी नेता को विनम्रता विकसित करने की सलाह देना आसान है, लेकिन एक नेता को विनम्रता कैसे विकसित करनी चाहिए? ये सबकुछ आसान नहीं है। पाठक नेस्ले के अध्यक्ष सुरेश नारायण के टेलीविजन साक्षात्कार में शी-रीन भान के साथ उनके तीन मुद्दों इनायत, इबा-दत, इंसानियत को देख सकते हैं। मेरे कई वर्षों के अवलोकन और चिंतन से, मुझे कुछ विचार उपयोगी लगे हैं।

नेतृत्व के बारे में सामान्य धारणा और शिक्षा-विज्ञान से पता चलता है कि विनम्रता और नेतृत्व एक साथ अच्छी तरह से नहीं बैठते हैं, हालांकि विनम्र नेतृत्व को 'कल के नेता' की एक अनिवार्य विशेषता के रूप में देखा जाता है। मेरे अनुभव में यह सच नहीं है.

एक मानसिकता के रूप में विनम्रता

शक्ति एक ऐसी संपत्ति है जिसका उपयोग समझदारी से किया जाना चाहिए। विनम्रता एक मानसिकता है. एक नेता को किसी बड़े उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करने की शक्ति प्रदान की जाती है। विनम्रता एक मानसिकता है जिसके लिए तीन आंतरिक विश्वासों की आवश्यकता होती है - कि नेता उन लोगों से अधिक चालाक नहीं है जो उसके आसपास हैं, कि नेता के लिए गलत होना संभव है, और यह कि असुरक्षा एक नेतृत्व गुण हो सकती है।

राष्ट्रों और कंपनियों को देखें. उन राजनीतिक या कॉर्पोरेट नेताओं की पहचान करने का प्रयास करें जो विनम्र मानसिकता प्रदर्शित करते हैं। यदि आपकी सूची अत्यंत छोटी है तो निराश न हों।

नेतृत्व को दूसरों द्वारा दया और स्नेह, और दूसरों में सच्ची रुचि लेने के लिए याद किया जाता है। मैं इसे 'महान संबंध नेतृत्व' की संज्ञा देता हूं, जो 'महान निर्णायक नेतृत्व' जितना ही महत्वपूर्ण है। चूंकि नेता लगातार कसरत कर रहे हैं

जो प्राधिकार सत्ता से प्राप्त होता है, वह संभवतः उन अवसरों से अनभिज्ञ होता है जब आत्ममुग्धता या अनजाने में किया गया विरोध उसके व्यवहार में आ जाता है।

इसीलिए नेता को एक 'मनोवैज्ञानिक दर्पण' की आवश्यकता होती है जो उसके आत्ममुग्ध व्यवहार की छवियों को प्रतिबिंबित करता हो।

मैं इस मनोवैज्ञानिक दर्पण को 'क्लेमेंटाइन मिरर' के नाम से ब्रांड करता हूं, जिसका नाम विंस्टन चर्चिल की पत्नी क्लेम-एंटाइन के नाम पर रखा गया है। ऐसी कुछ कहानियाँ हैं जो उसके मनमौजी और चिड़चिड़े पति पर शांत करने वाले प्रभाव को दर्शाती हैं। यह निश्चित रूप से एक नेता को व्यवहार में सुधार करने और कार्यस्थल पर अधिक टिकाऊ रिश्ते बनाने में मदद करता है।

सॉरी बोलो और आगे बढ़ो

महान नेताओं की विनम्रता के कार्यों से सीखें। यहां बीते समय की एक कहानी है, जिसे टाटा ब्रांड के पूर्व संरक्षक हरीश भट्ट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट, शॉर्ट टाटा स्टोरीज़ में सुनाया था।

जब जेआरडी टाटा टाटा संस के अध्यक्ष थे, तो उनकी नेतृत्व टीम के प्रमुख सदस्यों में से एक सुमंत मूलगांवकर थे, जिन्होंने टाटा मोटर्स (तब टेल्को कहा जाता था) का नेतृत्व किया था।

वे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सप्ताह में एक बार मिलते थे। ऐसी ही एक साप्ताहिक बैठक के दौरान, मूलगांवकर एक महत्वपूर्ण मामले पर जेआरडी टाटा से असहमत थे। दरअसल, उन्होंने एक खास बात को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति जताई थी

टाटा संस

> जेआरडी टाटा ने बड़ी विनम्रता के साथ टाटा संस का नेतृत्व किया। उनके इस नरम पक्ष को दिखाने की कई कहानियाँ हैं, जिनमें अपना आपा खोने के लिए बिना कहे माफी माँगने से लेकर कर्मचारियों के साथ मतभेदों को दूर करने तक शामिल हैं। उनके कुछ पत्र अब भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास का हिस्सा हैं

जेआरडी ने जो दृष्टिकोण व्यक्त किया। जब ऐसा हुआ, तो जेआरडी ने मूलगांवकर पर अपना आपा खो दिया और कुछ कठोर शब्द कहे।

मूलगांवकर इस बात से निराश होकर चले गए कि जेआरडी उनकी बात की सराहना नहीं कर रहे हैं। "क्या फायदा? जेह समझ नहीं पाता,'' उसने अपने एक सहकर्मी से कहा। कुछ दिनों बाद, जेआरडी टाटा, अपने निजी समझौते से, सुमंत मूलगांवकर के कार्यालय में गए। उन्होंने मूलगांवकर के असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण को समझने और उस पर चर्चा करने के लिए उनसे विस्तार से बात की। फिर, उन्होंने मूलगांवकर को एक असाधारण हस्तलिखित पत्र भेजा, जिसमें अपना आपा खोने के लिए गहरा खेद व्यक्त किया। इस पत्र की एक प्रति नीचे दी गई है। इसमें कहा गया, "प्रिय सुमंत, मैं अपने गुस्से के लिए माफी मांगता हूं। मैं घर पर और जाम की अपनी यात्रा पर बहुत दबाव में था- शेडपुर, और मैं थोड़ा अनिद्रा का रोगी हूँ। इसलिए, मैं अनावश्यक रूप से संवेदनशील हूं और आपकी आलोचना से आहत हुआ हूं, मैं जानता हूं कि इसका मतलब अच्छा था। आपके प्रति मेरा स्नेह और प्रशंसा कभी नहीं बदलेगी। हमेशा तुम्हारा, जेह।"

टाटा की कई कहानियों में से एक 1950 के दशक की शुरुआत में समूह के अध्यक्ष जेआरडी टाटा और टाटा के वरिष्ठ निदेशक एडी श्रॉफ से जुड़ी एक घटना से संबंधित है (सिक्स लेंस, 2015 से)।

इस घटना में टाटा संस की बोर्ड मीटिंग के दौरान जेआरडी और श्रॉफ के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि जेआरडी ने श्रॉफ द्वारा व्यक्त एक विचार को 'बेईमान राय' के रूप में संदर्भित किया। श्रॉफ को बुरा लगा कि उन्हें बेईमान कहा गया। इस घटना से टाटा के साथ उनका जुड़ाव जारी रहने पर खतरा पैदा हो गया।

एडी श्रॉफ ने अपना इस्तीफा भेज दिया लेकिन जेआरडी ने समतावाद और विनम्रता की महान भावना के साथ मामले को सुलझा लिया। 23 अगस्त, 1951 को श्रॉफ को लिखे एक पत्र में उन्होंने यही लिखा था: "आपका पत्र पाकर मैं आश्चर्यचकित और परेशान था।

मुझे ठीक से याद नहीं है कि बैठक में कुछ हद तक तीखी नोकझोंक के दौरान मैंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन आपसे मेरी शिकायत केवल यह थी कि आपने मुझ पर बहस का मुद्दा उठाने के लिए जिस तर्क का इस्तेमाल किया वह ईमानदार नहीं था। यह निश्चित रूप से आपकी ईमानदारी पर सवाल उठाने से बहुत दूर है और मुझे आश्चर्य है कि आपने इसकी इस तरह से व्याख्या की। मेरे गुस्से में बोलने या इसके परिणामस्वरूप अभद्रता दिखाने पर आपको नाराज होने का अधिकार है और इसके लिए मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं, लेकिन अगर दोस्तों और सहयोगियों ने हर बार बहस होने पर अलग होने का फैसला किया, तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। आप मेरी फर्म का संदर्भ लें। सिवाय इसके कि मैं व्यक्तिगत रूप से अपेक्षाकृत छोटा शेयरधारक हूं। मुझे नहीं लगता कि हममें से किसी में भी इस संबंध में कोई मतभेद है। हम सभी इसके लिए काम करते हैं और हमें इसे अपनी फर्म के रूप में सोचना चाहिए। हम दोनों के साथ परेशानी यह है कि हम दोनों बहुत गुस्से वाले हैं!"

श्रॉफ ने अपने इस्तीफे पर दबाव नहीं डाला।

वास्तव में, इसके बाद उन्होंने विश्वास की अपनी पुरानी भावना के साथ टाटा की सेवा की। प्रामाणिकता वह मुद्रा है जिसका उपयोग व्यक्ति विश्वास उत्पन्न करने के लिए करता है।

विनम्र नेतृत्व विकसित करना और प्रदर्शित करना सीखना सार्थक है।

(ये विचार निजी हैं)
(rgopal@themindworks.me)

MAILBAG

WRITE TO: letters@newindianexpress.com

बेरोज़गारी डेटा

संदर्भ: विपक्ष के पास कोई बेरोज़गारी का विश्वसनीय डेटा नहीं है पर (11 अप्रैल)। कोई यह जानना चाहेगा कि क्या सरकार के पास स्वयं भारत में बेरोजगारी पर प्रामाणिक डेटा है? जब तक शैक्षणिक संस्थान और नौकरी बाजार मिलकर काम नहीं करेंगे, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या, जो देश में चिंताजनक रूप धारण करती जा रही है, को कम नहीं किया जा सकता है।

एस रामकृष्णसायी, चेन्नई

असंबंधित उत्तर

वित्त मंत्री अपने इंटरव्यू में कड़े सवालों से बचती रहीं और कुछ और ही जवाब देती रहीं. जब उनसे पूछा गया कि अपराधियों को बीजेपी में शामिल होने के बाद राहत मिल रही है तो उन्होंने कहा कि राहत तो कोर्ट से मिली है. क्या अदालतें कार्रवाई से पहले उनके भाजपा में शामिल होने का इंतजार कर रही थीं? उन्होंने कहा कि राज्यों को धन का आवंटन केंद्र सरकार का नहीं बल्कि वित्त आयोग का काम है। क्या वित्त आयोग सरकार से ऊपर है?

वीओ हरींद्रनाथन, ईमेल

मृत्यु कक्ष

संदर्भ: बच्चों की जान बचाने के लिए बंद पड़े बोरवेल के ढक्कन (11 अप्रैल)। बिना ढके छोड़े गए बोरवेल मानवीय उदासीनता से ढके मौत के कमरे हैं। ऐसी आपराधिक लापरवाही तभी सामने आती है जब किसी दुर्घटना में कोई मासूम बच्चा फंस जाए।

ऐसी अमानवीय उपेक्षा की पुनरावृत्ति यह दर्शाती है कि सज़ा और समस्या के प्रति जागरूकता दोनों ही उतनी व्यापक नहीं हैं जितनी होनी चाहिए।

सच्चिदानंद सत्पथी, संबलपुर

नियमित जांच

बोरवेलों को ढकने में अधिकारियों का रवैया सुस्त नजर आ रहा है। अगर कोई हादसा हो जाए तो वे नींद से जाग जाते हैं और बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं। भू-स्वामियों को उचित निर्देश दिए जाने चाहिए तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दौरा किया जाना चाहिए।

एस चोकलिंगम, कोट्टारम

जलवायु जवाबदेही

SC ने मौलिक अधिकारों के दायरे का विस्तार करते हुए इसमें "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार" भी शामिल किया है।

यह जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए राष्ट्र की जिम्मेदारी को उजागर करता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने में सरकारों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए न्यायपालिका सक्रिय कदम उठा रही है।

विशाल मयूर, बेंगलुरु

अन्य बकाएदार

संदर्भ: एससी जंक रामदेव माफी मांगें, रोस्ट करें उत्तराखंड सरकार (अप्रैल11). पतंजलि मामले में सुप्रीम कोर्ट की निर्दयी कार्रवाई सरकार को नकली दवाओं, भ्रामक दावों और अयोग्य विशेषज्ञों से भरे चिकित्सा पारिस्थितिकी तंत्र को सही करने का संकेत है।

विनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा।

राजाराव कुमार, ईमेल

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस

बोर्ड के अध्यक्ष: मनोज कुमार सोंथालिया संपादक: सांत्वना भट्टाचार्य

रेजिडेंट एडिटर (तेलंगाना): टी कल्याण चक्रवर्ती* एक्सप्रेस पब्लिकेशंस (मदुरै) प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आरके झुनझुनवाला द्वारा मुद्रित और प्रकाशित , मकान नंबर 6-3-1113/1, बीएसएमक्टा लेन, सोमाजीगुडा, ग्रैंड काकतीय होटल के पास , पुंजागुट्टा, हैदराबाद - 500 016 और उनके द्वारा साक्षी प्रेस, प्लॉट नंबर डी-75 और ई-52, इंडस्ट्रियल एस्टेट (एपीआईई), बालानगर, मेडचल-मलकजगिरी जिला, तेलंगाना में मुद्रित। हैदराबाद: वॉल्यूम. 48, क्रमांक 87 आरएनआई रजि. क्रमांक 32179/77. फ़ोन: 040-23413908. * पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेदार। कॉपीराइट: एक्सप्रेस पब्लिकेशंस (मदुरै) प्राइवेट लिमिटेड, सर्वाधिकार सुरक्षित। पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा, पूर्ण या आंशिक रूप से पुनरुत्पादन निषिद्ध है।

Machine Translated by Google

the pioneer

Opinion

संपूर्ण यूनानी ट्रै- अरस्तू, सुकरात और अन्य से गुजरते हुए डिशन ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है कि 'मनुष्य एक सीखने वाला प्राणी है।' इस विश्वास को सावधानीपूर्वक पोषित किया गया और इसने ग्रीक-रोमन परंपरा पर गहरा प्रभाव छोड़ा। जैसे-जैसे ग्रीक-रोमन परंपरा उत्तरी अफ्रीका, एशिया और यूरोप के विभिन्न हिस्सों में फैलती गई, इसने मानव सोच और सीखने पर अपनी छाप छोड़ी। यह कि 'मनुष्य एक सीखने वाला प्राणी है' एक विश्वास और प्रतिमान के स्तर तक पहुँच गया है। गहन विचार से इस कथन पर बारीकी से विचार करना आवश्यक हो जाता है।

स्पष्टतः, यह एक सघन विचार है। इस प्रभाव की कुछ मान्यता और कुछ अनुभवजन्य साक्ष्य हैं जो भिन्न हैं-

जीवन चक्र के सभी चरणों में सीखने की तीव्रता और सामग्री अलग-अलग होती है। एक व्यक्ति युवावस्था और वयस्कता में व्यापक रूप से सीखता है और जैसे-जैसे वह बढ़ता है और नरम होता है, सीखने के कुछ पहले के अवशेष बचे रहते हैं।

जो नहीं रहता वह है व्यवहार या निरंतरता पर उस सीख का समान प्रभाव

विचार और कर्म में सीखना।

इस प्रकार, सभी समग्र कथनों की तरह, उन्हें संशोधित, अनुकूलित और फिट करने की आवश्यकता है
प्रसंग।

किस प्रकार की सीख क्रम और निरंतरता में रहती है और क्यों, इसका कुछ भाग न तो क्रम में रहता है और न ही निरंतरता में? वास्तव में, किस प्रकार की शिक्षा टुकड़ों में बनी रहती है, इसका एहसास सामग्री के खो जाने के साथ ही होना चाहिए। इस प्रकार का अन्वेषण मानव विकास के केंद्रीय संदर्भों में से एक होना चाहिए। यह विचार करने योग्य है कि सीखने के लिए इस तरह के दृष्टिकोण पर उतना ध्यान क्यों नहीं दिया गया, जितना कि विद्वतावाद के अन्य क्षेत्रों ने अर्जित किया है।

अंत में, ज्ञान, व्यवहार और आध्यात्मिकता तीन मूल तत्व हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व में प्रवेश करते हैं। इन तत्वों के बारे में जागरूकता पैदा करने की सामान्य आवश्यकता है

सामान्य साक्षर समुदाय के बीच जो इस भूमि में मायने रखता है। वह भारत को 'जगत गुरु' बनने और नेतृत्व करने के लिए एक आवश्यक तत्व होगा

बेहतर भविष्य की ओर दुनिया।

यह परिचालन स्तर पर जोर देने का विषय हो सकता है। एक हद तक इसे उन कौशलों के साथ पर्याप्त रूप से संरेखित नहीं किया गया है जो शिक्षित ज्ञान और व्यवहार से उत्पन्न होने चाहिए। इस प्रकार भारतीय शिक्षा की नींव पर और अधिक गहराई से विचार करने और अवलोकनित सीखने की प्रक्रियाओं में इसे प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। यह भी स्पष्ट है कि मनुष्य को बार-बार सिखाना पड़ता है। जैसे-जैसे ऐसा होता है, सीखना फीका पड़ जाता है और इसे फिसलने से रोकने के लिए निरंतर नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। इसमें कई तरीकों से हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जिसमें पाठ्यक्रम कैसे डिज़ाइन किया गया है, इसे किसी भी कक्षा में कैसे प्रदान किया जाता है और यह जीवन और पेशे की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक उपयोगी इनपुट कैसे बनता है।

सीखने की कई अभिव्यक्तियाँ होती हैं और यह ऑटो-मोटिव व्यवहार से शुरू होता है, जैसे कि खाना कैसे खाना है, अपनी उंगलियों का उपयोग कैसे करना है और स्वच्छता और अन्य मूल्यों को कैसे बनाए रखना है। यह एक जीवन होना चाहिए-

लंबी प्रक्रिया. हालाँकि, जैसा कि पहले कहा गया है, कुछ निश्चित हैं

जीवन के ऐसे पहलू जहां सीखने को आंतरिक बनाने के बार-बार प्रयास करने पड़ते हैं। जीवन के कुछ क्षेत्रों में, कोई ग़लती करने का जोखिम नहीं उठा सकता-

बार-बार लेता है.

इस स्थिति को व्यक्ति के जीवन चक्र में संबोधित किया जाना चाहिए और सामूहिक रूप से ठीक किया जाना चाहिए। अब 'सीखने' का समय आ गया है क्योंकि कला को सभी विषयों का अभिन्न अंग बना दिया गया है। इस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से समझने के लिए, किसी को यह पहचानने की आवश्यकता है कि गणित सीखने के लिए कुछ विशिष्ट तरीकों और क्षमताओं की आवश्यकता होती है। एक भाषा के रूप में अंग्रेजी या हिंदी सीखने के लिए वे तरीके और क्षमताएं समान नहीं हैं। सीखने की प्रक्रिया की आवश्यकताओं और विशेषताओं में अन्य परिवर्तन और कोणीयताएँ भी हैं।

उदाहरण के लिए, जब इतिहास या भूगोल सीखने की बात आती है तो सीखने की विधि को इसकी अनूठी आवश्यकता हो सकती है-

नेस.

इसलिए यह तर्क देना उचित है कि प्रत्येक विषय वस्तु के लिए, उस विषय की सीखने की पद्धति के प्रति एक अभिविन्यास होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, एक शिक्षक

गणित को बहुत स्पष्ट होना चाहिए और छात्रों को यह समझाना चाहिए कि गणित-इमेटिक्स कैसे सीखें। जैसा कि ऊपर बताया गया है, किसी भाषा को पढ़ाते समय शिक्षक का रुझान अलग-अलग होगा और शिक्षक को छात्रों को किसी भाषा की सीखने की विधियों को समझाने की आवश्यकता होगी। उदाहरणों को गुणा किया जा सकता है.

यह समझना कि किसी विषय को सीखने से निकलने वाले कौशल, व्यवहार और जानकारी के सफल आंतरिककरण का मूल क्या है, शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना देगा। यह 'मनुष्य सीखने वाला प्राणी है' के दृष्टिकोण को भी अधिक व्यापक पहुंच प्रदान करेगा।

अन्य चीज़ों की तरह, सीखने के सिद्धांत को शिक्षण योजना का एक हिस्सा बनाने की आवश्यकता है।

कहीं न कहीं यह अधिक यथार्थवादी और व्यावहारिक अभिविन्यास की शुरुआत का प्रतीक होगा। खुद को यह याद दिलाना उपयोगी होगा कि सारी सीख हम सभी को प्रभावित करती है और जिस भूमि पर हम रहते हैं, उसके जीवन का हिस्सा बनी रहती है।

(लेखक अंतरराष्ट्रीय ख्याति के जाने-माने प्रबंधन सलाहकार हैं। व्यक्त विचार निजी हैं)

रात के आकाश में और क्या आपने कभी सूर्यास्त देखा है आश्चर्य हुआ कि क्या हम थे अकेला? या हो सकता है कि आपने सोचा हो कि वास्तव में "अच्छा" या "बुरा" होने का क्या मतलब है? या फिर लाखों पक्षी आकाश में एक सुर में क्यों उड़ते हैं?

दर्शनशास्त्र कोई पुस्तकालय में बंद किया हुआ कोई बोझिल विषय नहीं है। यह एक मनमोहक सूर्यास्त को देखने और उन सभी चीज़ों पर सवाल उठाने जैसा है जिनके बारे में आपने सोचा था कि आप जानते हैं। क्या वह उग्र नारंगी चमक "असली" है या सिर्फ प्रकाश की एक चाल है? क्या सूर्यास्त की सुंदरता तब भी मौजूद रहती है जब इसे देखने वाला कोई नहीं होता?

ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें दार्शनिक पूछना पसंद करते हैं। पूरे इतिहास में, दुनिया भर के दार्शनिकों ने इन बड़े सवालों से जूझते रहे हैं।

उन्होंने अस्तित्व की प्रकृति, हमारे दिमाग की शक्ति और एक पूर्ण जीवन जीने के सर्वोत्तम तरीके पर बहस की है।

दर्शन का दायरा विशाल है, जिसमें विभिन्न उपक्षेत्र शामिल हैं जैसे तत्वमीमांसा (वास्तविकता की प्रकृति का अध्ययन), ज्ञानमीमांसा (ज्ञान और विश्वास का अध्ययन), नैतिकता (नैतिक सिद्धांतों का अध्ययन), तर्क (मान्य तर्क का अध्ययन) , सौंदर्यशास्त्र (सुंदरता का अध्ययन-

ty और कला), राजनीतिक दर्शन (शासन और न्याय का अध्ययन) और कई अन्य।

दर्शनशास्त्र अन्य क्षेत्रों के साथ अंत:विषय संवाद में भी संलग्न है, जिससे दर्शनशास्त्र और इन अन्य विषयों दोनों को समृद्ध किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा में दर्शनशास्त्र का महत्व अत्यधिक है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में जिस गिरावट पर हम हमेशा विचार करते हैं, वह हमारे पाठ्यक्रम में दर्शनशास्त्र की शिक्षा की कमी के कारण है। वर्तमान पीढ़ी के छात्रों और शिक्षकों में सीखने और सिखाने के दर्शन की समझ का अभाव है। हालाँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 का निर्माण दर्शनशास्त्र को पृष्ठभूमि में रखकर किया गया है, लेकिन यह छात्रों या शिक्षकों के दिमाग में घुसपैठ करने में विफल है।

बौद्धिक विकास, नैतिक जागरूकता और महत्वपूर्ण जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण दर्शन आवश्यक है

विश्व, अंततः समग्र रूप से व्यक्तियों और समाज दोनों को समृद्ध करता है।

यहां तक कि पीएचडी कार्यक्रम में, हालांकि डिग्री डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है, अधिकांश विश्वविद्यालय दर्शनशास्त्र नहीं पढ़ाते हैं।

दर्शनशास्त्र डॉक्टरेट छात्रों को स्वतंत्र शोधकर्ताओं के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक बौद्धिक टूलकिट से सुसज्जित करता है।

विविध दार्शनिक-सोफिकल दृष्टिकोणों के संपर्क में आने से खुले दिमाग का विकास होता है।

डॉक्टरेट छात्र विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना सीखते हैं, बौद्धिक जिज्ञासा और दूसरों से सीखने की इच्छा को बढ़ावा देते हैं।

अकादमिक अनुसंधान की निरंतर विकसित हो रही दुनिया में सहयोग और मार्गदर्शन के लिए यह महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एक विज्ञान का छात्र वैज्ञानिक पद्धति के दार्शनिक आधारों का पता लगा सकता है, जबकि एक साहित्य का छात्र सत्य और व्याख्या की अवधारणा में गहराई से उतर सकता है।

दर्शनशास्त्र डॉक्टरेट अनुसंधान के लिए आवश्यक आलोचनात्मक सोच कौशल को निखारता है। छात्र तर्कों का विश्लेषण करना, पूर्वाग्रहों की पहचान करना और साक्ष्य का मूल्यांकन करना सीखते हैं। वे जांच-पड़ताल वाले प्रश्न पूछने, धारणाओं को विखंडित करने और ध्वनि निर्माण करने की क्षमता विकसित करते हैं

उनके शोध का समर्थन करने वाले तर्क। कई डॉक्टरेट कार्यक्रमों में नैतिक विचारों के साथ अनुसंधान शामिल होता है।

दर्शनशास्त्र नैतिक निर्णय लेने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। छात्र अनुसंधान डिजाइन, डेटा विश्लेषण और प्रकाशन में नैतिक दुविधाओं से जूझते हैं, जिससे उन्हें अपने चुने हुए क्षेत्र की नैतिक जटिलताओं से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। छात्र अपने शोध प्रश्नों को स्पष्ट करना, अपने निष्कर्षों का बचाव करना और सहकर्मियों के साथ विद्वतापूर्ण बहस में संलग्न होना सीखते हैं।

उच्च शिक्षा केंद्रों में दर्शनशास्त्र की शिक्षा के अभाव के परिणामस्वरूप बौद्धिक रूप से कम संलग्न, नैतिक रूप से सूचित और आलोचनात्मक सोच वाला समाज बन सकता है, जो संभावित रूप से अकादमिक, शासन और सामाजिक विकास में प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। यहां तक कि जब वर्षों में विज्ञान की नई शाखाएं उभरती हैं, तब भी एक विषय जो हर समाज में प्रासंगिक रहता है, यहां तक कि अंतरिक्ष कॉलोनी में भी, दर्शनशास्त्र होगा। अब समय आ गया है कि हम अपनी उच्च शिक्षा में दर्शनशास्त्र को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करें।

(लेखक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज में सहायक संकाय हैं; विचार व्यक्तिगत हैं)

महोदया - समाचार लेख का हवाला देते हुए, "अमेरिका में एक और भारतीय छात्र की मृत्यु हो गई; अब तक 11वीं,'' 10 अप्रैल को प्रकाशित, यह मेरी प्रतिक्रिया है। भारतीय छात्र मोहम्मद अब्दुल अरफात की यह घटना कोई अकेली घटना नहीं है, क्योंकि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में दस और भारतीय छात्रों को भी इसी तरह की घटना का सामना करना पड़ा है। विडंबना यह है कि वे वहां शिक्षा और ज्ञान हासिल करने के लिए जाते हैं लेकिन उन्हें ताबूतों में मृत अवस्था में वापस भेज दिया जाता है। यह स्थिति वहां कानून और व्यवस्था की बेहद खराब दुर्दशा को उजागर करती है, जिससे अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय छवि पर असर पड़ रहा है और इससे अमेरिकी प्रशासन में जनता का विश्वास कम हो रहा है।

नए अभ्यर्थी अब अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखने से पहले दो बार सोचेंगे। शुक्र है कि भारतीय वाणिज्य दूतावास कथित तौर पर अमेरिकी कानून-प्रवर्तन अधिकारियों के संपर्क में है और उनके साथ काम कर रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैदराबाद के मोहम्मद अब्दुल अरफात क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी से एम-टेक (आईटी) करने के लिए पिछले साल मई में अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन कुछ समय से वह अपने माता-पिता के कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे।

तलाशी अभियान के दौरान, अराफात को मृत पाया गया जिससे उसके उन्मत्त माता-पिता सदमे में आ गए। हालाँकि, न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने खाली परिवार के प्रति 'गहरी संवेदना' व्यक्त करते हुए, हर संभव सहायता देने के अलावा, अराफात की मौत की गहन जांच का वादा किया है!

अज़हर ए खान | कोटवालन

महोदया - 10 अप्रैल को प्रकाशित संपादकीय, "लॉस्ट चांस" के संदर्भ में, यह मेरी प्रतिक्रिया है। यह संपादन प्रधानमंत्री की स्फिंक्स जैसी चुप्पी की ओर इशारा करता है जब मणिपुर में हिंसा अपने चरम पर थी, उसके बाद भी।

अंततः विपक्षी दलों के संयुक्त प्रयासों से उन्हें अपनी चुप्पी तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। फिर भी, उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से नहीं बताया जैसा कि अपेक्षित था, बल्कि इसका संक्षिप्त संदर्भ दिया।

उन्हें मणिपुर के बारे में बोलते हुए सुनना बहुत बड़ा आश्चर्य था और वह भी उनकी अपनी इच्छा से। यह लगभग वैसा ही था जैसे प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर अपना मौन व्रत तोड़ दिया हो।

सुजीत दे | कोलकाता

हालाँकि, उन्होंने जो कहा उसे नमक की कहावत से कहीं ज्यादा गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार के "समय पर हस्तक्षेप" से स्थिति को सुलझाने में मदद मिली। यह कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन यह "समय पर हस्तक्षेप" लगभग 300 लोगों की जान को रोकने में बुरी तरह विफल रहा और कई अन्य घायल हो गए और विस्थापित हो गए। सबसे बढ़कर, राज्य को गहरे और खतरनाक जातीय घावों का खामियाजा भुगतना पड़ा, जो शायद कभी नहीं भरेंगे।

क्योंकि किसी के लिए भी तथ्यों पर प्रधान मंत्री को चुनौती देना प्रथागत नहीं है, मैं केवल अमेरिकी राजनेता और राजनयिक डैनियल पैट्रिक मोयनिहान को उद्धृत करूंगा, जिन्होंने कहा था कि "हर कोई अपनी राय का हकदार है, लेकिन अपने तथ्यों का नहीं।"

अविनाश गोडबोले | देवास

महोदया - हाल ही में महंगाई बढ़ रही है। इसके अलावा माता-पिता को अपने बच्चों की शिक्षा और पालन-पोषण पर भी काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा, हाल ही में पति-पत्नी दोनों कामकाजी हैं, इसलिए बच्चों के पालन-पोषण की कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। परीक्षा दें-

अकेले पुणे शहर के बहुत से लोग। पुणे शिक्षा का घर है और देश के कई हिस्सों से नागरिक विभिन्न प्रकार की नौकरियों के लिए यहां आते हैं। एक सर्वे के मुताबिक पुणे में 4 लाख 46 हजार उपजाऊ जोड़े हैं.

दिलचस्प बात यह है कि 37 प्रतिशत जोड़े 2 बच्चों से संतुष्ट हैं और 27 प्रतिशत जोड़े केवल एक बच्चे से संतुष्ट हैं।

यानी 64 जोड़ों ने 'हम दो, हमारे एक या दो' के नारे को सच कर दिखाया है. लगभग चार-पाँच दशक पहले प्रत्येक जोड़े के चार-पाँच बेटे-बेटियाँ हुआ करते थे। हाल ही में कई तरह के मुद्दे उठे हैं और कपल्स जनसंख्या को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब एक बात सामने आई है कि बच्चों को किताब में चाचा-चाची का रिश्ता देखना पड़ेगा। अब 2024-2025 के लिए सर्वे जल्द ही शुरू किया जाएगा

पुणे और यह अगले दो महीनों में पूरा हो जाएगा। अधिक जानकारी नीचे दी जाएगी।

शांताराम वाघ | पुणे

Machine Translated by Google

the pioneer analysis

प्रथमस्तंभ

5 अप्रैल, 2024 को चालू वित्त वर्ष (FY) की पहली द्विमासिक बैठक में छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा लिए गए निर्णयों की घोषणा करते हुए, गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, “हाथी अब टहलने के लिए बाहर चला पर गया है।” और जंगल की ओर लौटता हुआ प्रतीत होता है। हम चाहेंगे कि हाथी जंगल में लौट आए और टिकाऊ आधार पर वहीं रहे।''

दास उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा दर्शाए गए खुदरा मुद्रास्फीति के प्रक्षेप पथ को चित्रित करने के लिए हाथी सादृश्य का उपयोग कर रहे थे। अप्रैल 2022 में 7.8 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद, सीपीआई दिसंबर 2023 में घटकर 5.7 प्रतिशत हो गई और जनवरी/फरवरी 2024 के दौरान 5.1 प्रतिशत पर आ गई। वह चाहते हैं कि सीपीआई में गिरावट जारी रहेगी और कि यह 'टार-' पर स्थिर हो जाएगा

स्थायी आधार पर स्तर प्राप्त करें। चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, आइए कुछ बुनियादी बातों पर गौर करें।

2016 में, केंद्र सरकार ने एमपीसी को मौद्रिक नीति तैयार करने और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए प्रमुख ब्याज दरें निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया। इसने आरबीआई को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के लिए 4 प्रतिशत (+/- 2 प्रतिशत) की लक्ष्य सीमा के भीतर नीति दर (वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है) को इस तरह से सीपीआई बनाए रखने के लिए तय करने का आदेश दिया। 31 मार्च, 2021। जनादेश को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

आरबीआई मुद्रास्फीति के प्रबंधन के लिए दो प्रमुख मौद्रिक नीति उपकरणों अर्थात् नीति दर और तरलता (बैंकिंग प्रणाली में उपलब्ध ऋण की मात्रा के लिए एक शब्दजाल) का उपयोग करता है। यह उच्च और समावेशी आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है। लेकिन, व्यवहार में, यह मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण पर असंगत ध्यान देता है। फिर भी जब महंगाई के नतीजे की बात आती है तो इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिलती. आइये कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं.

दिसंबर 2018 में जब दास ने कार्यभार संभाला, तब अर्थव्यवस्था गिरावट की ओर थी, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर गिर रही थी।

फिर, उनके पूर्ववर्ती उर्जित पटेल द्वारा उठाए गए सख्त रुख के कारण नीति दर 6.5 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई। फरवरी 2019 की शुरुआत में, दास ने नीति दर में आक्रामक कटौती की, जो मई 2020 तक गिरकर 4 प्रतिशत हो गई। कटौती के बावजूद, विकास में सुधार नहीं हुआ।

2019-20 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 4 प्रतिशत के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई। 2020-21 के दौरान, कोरोना महामारी के प्रबल प्रभाव के कारण, यह 6.6 प्रतिशत पर नकारात्मक था। 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बढ़कर 8.9 प्रतिशत हो गई। हालांकि कोई यह तर्क दे सकता है कि कम ब्याज दरों ने पुनरुद्धार में मदद की, तथ्य यह है कि यह मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों की बहाली थी - कोरोना से संबंधित प्रतिबंध हटने के बाद - जिसने इसे संभव बनाया। प्रासंगिक रूप से, कम ब्याज दर के बावजूद उस वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के दौरान मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा के भीतर रही।

दर।

जनवरी 2022 के बाद से, मुद्रास्फीति में तेजी आई जो वित्त वर्ष 2022-23 के अधिकांश समय तक जारी रही। इस उछाल ने आरबीआई को 'मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण' के अपने पसंदीदा विषय को लागू करने के लिए प्रेरित किया। मई 2022 से शुरू होकर, इसने वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान नीति दर में 1.4 प्रतिशत की संचयी बढ़ोतरी की (तीन लॉट में यानी)

मई/जून/अगस्त)। इसने दूसरी छमाही के दौरान 1.1 प्रतिशत (अक्टूबर/दिसंबर) तक बढ़ोतरी जारी रखी

2022 और फरवरी 2023)। इस प्रकार 2.5 प्रतिशत की कुल बढ़ोतरी ने दर को फरवरी 2023 तक 6.5 प्रतिशत के अपने पहले शिखर पर बहाल कर दिया। फिर भी, मुद्रास्फीति लगभग पूरे 2022-23 के दौरान स्थिर बनी रही। दास ने अपने अप्रैल 2023 के नीति वक्तव्य में इसे चुपचाप स्वीकार किया था: “जब हमने विकास को समर्थन प्रदान करने के लिए फरवरी 2019 में दर में कटौती का चक्र शुरू किया, तो सीपीआई मुद्रास्फीति लगभग 2 प्रतिशत थी और नीति रेपो दर 6.50 प्रतिशत थी। अब, नीतिगत दर 6.50 प्रतिशत है लेकिन मुद्रास्फीति 6.4 प्रतिशत है।

दूसरे शब्दों में, उन्होंने स्वीकार किया कि आरबीआई नीतिगत दर को 6.4 प्रतिशत तक बढ़ाने के बाद भी मुद्रास्फीति को कम करने में असमर्थ है। फरवरी 2023 के बाद, अप्रैल/जून/अगस्त/अक्टूबर/दिसंबर 2023 और फरवरी 2024 में लगातार छह नीति समीक्षाओं के दौरान, आरबीआई ने नीति दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा।

ऐसा तब हुआ जब सीपीआई मुद्रास्फीति जुलाई 2023 में 7.4 प्रतिशत के उच्च स्तर से घटकर सितंबर 2023 में 5 प्रतिशत, अक्टूबर 2023 में 4.8 प्रतिशत और जनवरी/फरवरी 2024 के दौरान 5.1 प्रतिशत हो गई।

पूरे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, 5.4 प्रतिशत पर, यह 6 प्रतिशत की बाहरी (यद्यपि लक्ष्य) सीमा से कम था।

अप्रैल 2024 की समीक्षा में आरबीआई ने एक बार फिर नीतिगत दर को 6.5 फीसदी पर अपरिवर्तित रखा है। यह उसके आकलन के बावजूद है कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत होगी जो कि 4 प्रतिशत (+/- 2 प्रतिशत) की लक्ष्य सीमा के भीतर है। फिर भी, यह निर्णय केंद्रीय बैंक की उस प्रतिबद्धता से प्रेरित है जिसे दास 'अंतिम-मील मुद्रास्फीति को सुनिश्चित करने' के रूप में वर्णित करते हैं, उनका कहना है कि जब तक मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती, तब तक ब्याज दरों में कटौती शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वास्तव में यही इरादा था तो (+/- 2 प्रतिशत) क्यों रखा जाए?

आरबीआई ने "आवास की वापसी" पर केंद्रित नीतिगत रुख भी बरकरार रखा है।

यह शब्दावली दास द्वारा जून 2019 में गढ़ी गई थी जब उन्होंने 'समायोजन' की बात की थी।

रुख नीतिगत दर में कटौती और ऋण-उपलब्धता में वृद्धि की ओर इशारा कर रहा है। जून 2022 से आरबीआई ने इस रुख को उलट दिया है और आज तक आवास वापस लेने पर अड़ा हुआ है। दास ने दिसंबर 2023 की द्विमासिक नीति समीक्षा में एक नई शब्दावली गढ़ी है और अब इसे "सक्रिय रूप से अवस्फीतिकारी" कहते हैं। आरबीआई अपने सख्त नीतिगत रुख को क्यों नहीं छोड़ना चाहता है? भले ही कोर मुद्रास्फीति (ईंधन और भोजन को छोड़कर सीपीआई) 3.4 प्रतिशत पर आरबीआई के 4 प्रतिशत लक्ष्य से नीचे बनी हुई है और ईंधन की कीमतें पूरे वर्ष अपरिवर्तित बनी हुई हैं, इसकी मुख्य चिंता खाद्य मुद्रास्फीति है। जुलाई 2023 में 11.8 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से घटकर अक्टूबर 2023 में 6.6 प्रतिशत होने के बाद, हाल के महीनों में, यह सबसे हालिया रीडिंग 8 प्रतिशत तक बढ़ गई है।

खाद्य मुद्रास्फीति पर बहुत अधिक ध्यान देना गलत है। सबसे पहले, मौजूदा सीपीआई बास्केट भोजन को लगभग 39 प्रतिशत का भार देता है। लेकिन, यह 2011-12 के उपभोग व्यय सर्वेक्षण (सीईएस) पर आधारित है।

2022-23 सीईएस के सारांश आंकड़े बताते हैं कि इसमें काफी गिरावट आई है। इस सुधार के साथ, सीपीआई पर खाद्य मुद्रास्फीति का प्रभाव काफी कम हो जाएगा।

दूसरा, खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल मुख्य रूप से मौसमी कारकों के कारण आपूर्ति में व्यवधान से जुड़ा है।

पिछले दो वर्षों के दौरान, 2021-22 के दौरान असामान्य रूप से उच्च तापमान और 2022-23 में बारिश के साथ ओलावृष्टि से गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ था। जुलाई 2023 में उच्च मुद्रास्फीति सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण थी - फिर से मौसमी कारकों के कारण। तीसरा,

आरबीआई नीति दर में वृद्धि या ऋण उपलब्धता को सीमित करके बहुत कम हासिल कर सकता है क्योंकि ये उपाय मुख्य रूप से मांग पक्ष पर काम करते हैं जबकि समस्या आपूर्ति पक्ष पर है।

इस बीच, सख्त मौद्रिक नीति रुख जारी रखने से उधार दरों में वृद्धि, लाखों उधारकर्ताओं की ईएमआई में वृद्धि और उद्योगों, विशेषकर एमएसएमई को उच्च लागत वाले ऋण के कारण विकास के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

जबकि, हर कोई - गवर्नर की तरह - चाहेगा कि हाथी जंगल में लौट आए और स्थायी रूप से वहीं रहे, आरबीआई के अकेले ऐसा करने से उलटफेर हो सकता है।

“गेहूं की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है...गेहूं की उपलब्धता उतनी प्रभावित नहीं होगी जितनी 2 साल पहले हुई थी जब मार्च से हीटवेव की स्थिति शुरू हो रही थी। तो, गेहूँ में, इतना नुकसान नहीं है-

सर्न.

लेकिन सब्जियों की कीमतों और गर्मी की लहर की स्थिति के कारण होने वाले किसी भी अन्य प्रभाव पर नजर रखनी होगी, ”दास ने नीति-पश्चात प्रेस वार्ता में कहा। “पिछले तीन वर्षों की तुलना में, INR ने 2023-24 में सबसे कम अस्थिरता प्रदर्शित की। आईएनआर की सापेक्ष स्थिरता भारत की मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी बातों, वित्तीय स्थिरता और बाहरी स्थिति में सुधार को दर्शाती है, ”उन्होंने कहा।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार मार्गों में बढ़ते व्यवधान से हालांकि, परिदृश्य पर जोखिम पैदा हो गया है। गवर्नर दास ने कहा कि इसके लिए दृष्टिकोण

कृषि और ग्रामीण गतिविधियाँ उज्ज्वल दिखाई देती हैं। गवर्नर दास ने कहा कि कृषि और ग्रामीण गतिविधि का दृष्टिकोण उज्ज्वल दिखाई देता है।

(लेखक नीति विश्लेषक हैं; ये उनके निजी विचार हैं)

राष्ट्रीय फुटबॉल

जब भी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चुनावों में टीम को अपने प्रतिद्वंद्वियों से हार का सामना करना पड़ता है, राष्ट्रीय कोच इगोर स्टिमैक के पास इसका रेडीमेड जवाब है। “यह परिणाम अपेक्षित तर्ज पर है। इस नतीजे में कुछ भी असामान्य नहीं है।”

स्टिमैक ने मीडिया को बताया। वह 2019 से देश के मुख्य कोच हैं और खेल को नियंत्रित करने वाली विश्व संस्था फीफा के अनुसार, भारत की रैंकिंग 121 है। ऐसे समय में जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। , राष्ट्रीय फुटबॉल टीम एक पतवारहीन जहाज की याद दिलाती है जो गहरे समुद्र में पस्त और क्षतिग्रस्त हो गया है।

भारतीय फुटबॉल टीम के प्रदर्शन में कोई आश्चर्य की बात नहीं है

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के बाद से

पिछले 1960 के दशक में, राष्ट्रीय पक्ष की गुणवत्ता हमेशा नीचे की ओर रही है जिसमें इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत और विदेशी देशों से खिलाड़ियों के आगमन से देश के औसत फुटबॉल प्रेमियों को कुछ उम्मीद जगी थी, लेकिन वह धूमिल हो गई है। अधिकांश

आईएसएल में जूते पहनने वाले खिलाड़ियों में से वे हैं जो

अपने देश की राष्ट्रीय या क्लब टीमों में जगह बनाने में असफल रहे थे। इसलिए आईएसएल थके हुए खिलाड़ियों और छोड़े गए कोचों के लिए डंपिंग ग्राउंड बन गया है। यह ज्ञात नहीं है कि स्टिमक उन कोचों में से हैं या नहीं जिन्हें कार्ड से हटा दिया गया है। लेकिन क्रोएशियाई खिलाड़ी भारतीय फुटबॉल में कोई प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे हैं।

यह केरल की फुटबॉल नर्सरी, फोर्ट कोच्चि में हुए हालिया विकास की पृष्ठभूमि में लिखा जा रहा है। इस सुरम्य शहर में स्थित 90 वर्षीय फुटबॉल कोच रूफस डिसूजा को जर्मनी के विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब बोरूसिया डॉर्टमुंड द्वारा सम्मानित किया गया, जो देश की पेशेवर लीग के शीर्ष स्तर बुंडेसलिगा में खेलता है।

यह सम्मान रूफस की कड़ी मेहनत और समर्पण को मान्यता देने के लिए था

फुटबॉल की कोचिंग ली.

हर सुबह ठीक साढ़े पांच बजे रूफस औपनिवेशिक युग के परेड ग्राउंड में पहुंचता है और सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित करता है।

रूफस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारिश हो रही है या बगल के अरब सागर से ठंडी हवा आ रही है। फुटबॉल अंकल, जैसा कि बच्चे और उनके माता-पिता उन्हें सम्मान से संबोधित करते हैं, एक समझौता न करने वाला कार्य है। समय की पाबंदी और अनुशासन उनकी विशेषता है।

रूफस खिलाड़ियों से कोई फीस या दान नहीं लेता है।

लेकिन शर्त यह है कि उन्हें साढ़े पांच बजे तक स्टेडियम में पहुंचना होगा।

रूफस की कक्षाओं में देर से आने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। वह कोई साधारण फुटबॉल कोच नहीं हैं. आठ दशकों से वह फुटबॉल और हॉकी के लिए ही जिए हैं।

कोचिंग तपस्या का कार्य है

इस पूर्व पेशेवर फुटबॉलर के लिए जिन्होंने नेताजी स्पोर्टिंग और मद्रास के WIMCO जैसी टीमों के लिए जूते पहने थे। वह पहले केरलवासी हैं, जिन्होंने 1950 के दशक में भारतीय फुटबॉल के दिग्गजों में से एक, WIMCO के लिए खेलते हुए ब्राजीलियाई दा'कुन्हा के साथ मिलकर काम किया है। 1950 के दशक के अंत में हमेशा के लिए संन्यास लेने के बाद, रूफस ने बड़े पैमाने पर कोचिंग शुरू की। खिलाड़ियों को ढाला गया

उनके द्वारा भारतीय फुटबॉल की प्रतिभा से मिलता जुलता है। जेवियर्स पियस, हैमिल्टन बॉबी, सेबेस्टियन नेट्टो, केरल के पूर्व कप्तान टीए जाफर और सूची लंबी है।

रूफस ने अपने पड़ोस में एक क्लब सैंटोस को पुनर्जीवित और पुनर्जीवित किया। “यह नाम विश्व फुटबॉल के सर्वकालिक महान पेले को मेरी श्रद्धांजलि थी।

जब महान मास्टर को पता चला कि हमारे पास सैंटोस नाम से एक क्लब है, तो उन्होंने मुझे सराहना पत्र भेजा,'' रूफस अपने बच्चों जैसे उत्साह के साथ कहते हैं। कोचिंग के अपने व्यस्त कार्यक्रम और टूर्नामेंट में खेलने के लिए सैंटोस को पूरे दक्षिण भारत में ले जाने में, रूफस अपना जीवन भूल गया। फुटबॉल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें शादी और परिवार से दूर रखा।

यहां एक फुटबॉल गुरु है जो सांस लेता है, सोता है और फुटबॉल को ही जीता है। कई प्रतिष्ठित कोच

रूफस के फुटबॉल ओडिसी के बारे में सुनने के बाद यूरोप से फोर्ट कोच्चि आए थे, जो मिडा टच वाले हैदराबाद के एसए रहीम को पसंद करते हैं। “रहीम, मन्ना, चुन्नी गोस्वामी, सुखविंदर और जरनैल सिंह जैसे अच्छे कोच थे।

रूफस कहते हैं, ''विदेशी प्रशिक्षकों के बजाय हमें विदेशी प्रबंधकों को चुनना चाहिए जो फुटबॉल की बारीकियों को जानते हों।''

यह भले ही अजीब लगे, लेकिन इस देसी गुरु से देश के फुटबॉल मालिकों ने कभी भी राष्ट्रीय टीम को प्रशिक्षित करने के लिए उन कारणों से संपर्क नहीं किया, जो केवल वे ही जानते हैं। रूफस, जो सूर्यास्त की ओर तेजी से चल रहे हैं, भारतीय फुटबॉल की स्थिति से दुखी हैं। उन्होंने इंडियन सॉकर लीग को देश के साथ किया गया बड़ा धोखा बताया है. से अवधि

मार्च से मई तक भारत का फुटबॉल सीज़न था। राज्य के 14 जिलों में से प्रत्येक में एक अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट था। सभी

कलकत्ता की बिग थ्री (मोहन बागान, बंगाल और ईस्ट मोहम्मडन स्पोर्टिंग) सहित टीमें इन टूर-नामेंट्स में खिलाड़ी नियमित रूप से शामिल थीं और घरेलू नाम थे। “प्रायोजकों की कमी के कारण टूर-नाम और टीमों की स्वाभाविक मृत्यु हो गई। जब टूर-नाम और टीमें ही नहीं होंगी तो खिलाड़ी भी कहीं नहीं होंगे। आईएसएल आगामी खिलाड़ियों को कोई मौका नहीं देता है,'' रूफस कहते हैं, जो फुटबॉल दिग्गज के अतिथि के रूप में डॉर्टमुंड के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहे हैं।

(लेखक द पायनियर के विशेष संवाददाता हैं; ये उनके निजी विचार हैं)